5 राज्यों के विधानसभा चुनाव

दैनिक जागरण

www.dainikjagranmpcg.com

वर्ष 73 ▶▶ अंक 211 ▶▶ पृष्ठ 12
रीवा, गुरुवार 30 अप्रैल, 2026
वैशाख शुक्ल पक्ष 14, विक्रम संवत् 2083
नगर ▶▶ मूल्य 5 रुपए

एग्जिट पोल

बंगाल में भाजपा सरकार, केरलम में कांग्रेस

नई दिल्ली, जेएनएन। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के आधार पर देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल और केरलम के नतीजे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 7 एग्जिट पोल में से 5 ने भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया है, जबकि 2 एग्जिट पोल में टीएमसी की वापसी की संभावना जताई गई है। औसत आंकड़ों के अनुसार भाजपा लगभग 154 सीटें हासिल कर सकती है, जो बहुमत के आंकड़े 148 से अधिक है। वहीं टीएमसी को करीब 131 सीटें मिलने का अनुमान है। यह संकेत देता है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन संभव है।

इसी तरह, तमिलनाडु में 9 एग्जिट पोल में से 6 ने डीएमके गठबंधन की वापसी का अनुमान जताया है। यहां डीएमके गठबंधन को लगभग 120 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के 118 के आंकड़े से अधिक है। अन्नाद्रमुक को करीब 78 सीटें और फिल्मस्टार विजय की पार्टी टीवीके को 37 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इससे साफ है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक रुझान की निरंतरता देखने को मिल सकती है।

केरलम में 6 के 6 एग्जिट पोल ने यूडीएफ गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। यहां यूडीएफ को करीब 78 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एलडीएफ को 61 सीटों पर सिमटने का अनुमान है। अगर ये नतीजे सही साबित होते हैं, तो केरलम में लगभग 10 साल बाद सत्ता परिवर्तन होगा। असम में 11 एग्जिट पोल सामने ■ शेष पृष्ठ 7 पर

पोल ऑफ पोल्स 2026

पश्चिम बंगाल (कुल सीटें 294, बहुमत 148)		
टीएमसी	भाजपा	अन्य
131	154	06

तमिलनाडु (कुल सीटें 234, बहुमत 118)		
द्रमुक	अन्नाद्रमुक	टीवीके
120	78	37

केरलम (कुल सीटें 140, बहुमत 71)		
एलडीएफ	यूडीएफ	अन्य
61	78	03

असम (कुल सीटें 126, बहुमत 64)		
भाजपा	कांग्रेस	अन्य
90	29	07

पुडुचेरी (कुल सीटें 30, बहुमत 16)		
भाजपा+	कांग्रेस+	अन्य
20	08	02

तमिलनाडु में द्रमुक, असम और पुडुचेरी में भाजपा की सरकारें बरकरार

पश्चिम बंगाल 294

	तृणमूल	भाजपा	अन्य
मैट्रिज	125-140	146-161	6-10
पीपुल्स पल्स	177-187	95-110	1- 4
पी मार्क	118-138	150-175	0-0
पोल डायरी	99-127	142-171	5-9
प्रजा पोल	85-110	178-208	0-5
चाणक्य स्ट्रेटेजीज	130-140	150-160	0-5
जनमत पोल्स	195-205	80-90	1-4

तमिलनाडु 234

	द्रमुक	अन्नाद्रमुक	टीवीके
मैट्रिज	122-132	87-110	10-12
पीपुल्स पल्स	125-145	65-80	18- 24
एक्सिस माय इंडिया	92-110	22-32	98-120
पी मार्क	125-145	65-85	16-26
प्रजा पोल	148-168	61-81	1-9
जेवीसी-टाइम्स नाउ	75-95	128-147	8-15
पीपुल्स इनसाइट	120-140	60-70	30-40

केरलम 140

	वामदल	कांग्रेस	अन्य
मैट्रिज	60-65	75-85	3-5
पीपुल्स पल्स	55-65	70-85	0-3
एक्सिस माय इंडिया	49-62	78-90	0-3
पी मार्क	62-69	71-79	1-7
वोट वाइब	58-68	70-80	0-4
जेवीसी-टाइम्स नाउ	57-66	72-82	2-6
पीपुल्स इनसाइट	58-68	66-76	10-15

असम 126

	कांग्रेस	भाजपा	अन्य
मैट्रिज	85-95	25-32	6-12
पीपुल्स पल्स	68-72	22-26	3-5
एक्सिस माय इंडिया	88-100	24-36	0
पी मार्क	82-94	30-40	1-5
पोल डायरी	86-101	15-26	3-7
जेवीसी	88-101	23-33	2-5
चाणक्य स्ट्रेटेजीज	88-98	22-32	3-5

पुडुचेरी-30 सीटें : चार एजेंसियों के औसत में भाजपा +20 और कांग्रेस + 8 तथा अन्य के खाते में दो सीटें जा रही हैं

मतदान प्रतिशत बढ़ा: इन चुनावों में 3-12 फीसदी तक मतदान में वृद्धि दर्ज हुई है। इसका प्रमुख कारण एसआईआर को माना जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए। इससे कुल मतदाता संख्या कम हुई, लेकिन वास्तविक मतदान बढ़ा।

मुझे विश्वास है कि इन पांच राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। 4 मई के नतीजे, विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत रही है। सीआरपीएफ इस तरह से टार्चर नहीं कर सकती। इन्हें सीमा की रक्षा करनी चाहिए लेकिन इसकी जगह वे एक राजनीतिक दल की रक्षा कर रहे हैं।

- ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल

महिला वोटर्स ने बदला समीकरण

इन चुनावों में महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही। मुफ्त योजनाएं, नकद सहायता और आरक्षण जैसे वादों ने महिला वोटर्स को खासा प्रभावित किया। बंगाल और तमिलनाडु में महिलाओं का मतदान पुरुषों से 2 फीसदी अधिक रहा, असम में 1 फीसदी, केरलम में 5 फीसदी और पुडुचेरी में 3 फीसदी ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। नतीजन पुडुचेरी को लेकर जारी चारों एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान है। एडीए को करीब 20 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस+ को 8 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है।

(क्या कहता है फलोदी सट्टा बाजार, पढ़ें -पेज 8)

बंगाल में दूसरे चरण में 92% मतदान, कई जगह हिंसा व तनाव

कोलकाता, जेएनएन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में रिकॉर्ड मतदान के साथ-साथ कई जगह हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, 142 सीटों पर हुए मतदान में रात 9 बजे तक करीब 92.32 फीसदी वोटिंग- दर्ज की गई। यह आंकड़ा राज्य में लोकतांत्रिक भागीदारी के उच्च स्तर को दर्शाता है, लेकिन इसके साथ ही कई इलाकों में तनाव भी देखने को मिला।

लाठी डंडों के साथ मुक्के चले: नॉर्थ 24 परगना जिले के अरविंद इलाके में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और मुक्कों से हमला किया। मौके पर मौजूद सुरक्षाबलों के बावजूद हालात कुछ समय के लिए बेकाबू हो गए।

बुजुर्ग की मौत पर हंगामा: हावड़ा के उदयनारायणपुर में बुजुर्ग की मौत को लेकर विवाद हो गया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि रूप से सीआरपीएफ की मारपीट के कारण बुजुर्ग की मौत हुई। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि बुजुर्ग बेटे के साथ वोट डालने पहुंचे थे, जहां उन्हें धक्का दिया गया, बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप: चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ के आरोप भी लगे। भाजपा ने डायमंड हार्बर के फालता क्षेत्र में ईवीएम के बटन पर टेप लगाए जाने का आरोप लगाया। वहीं कुछ जगहों पर बटन पर इंक के निशान मिलने की शिकायत भी सामने आई, जिसे बाद में साफ किया गया। चुनाव आयोग ने कहा है कि जहां शिकायतें सही पाई जाएंगी, वहां पुनर्मतदान कराया जाएगा।

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर में विरोध का सामना करना पड़ा। टीएमसी समर्थकों ने उन्हें घेरकर 'चोर-चोर' और 'गो बैक' के नारे लगाए, जिस पर उन्होंने 'जय श्री राम' के नारे लगाकर जवाब दिया।

ऑफ बीट

मैराथन में साड़ी पहन दौड़ी, बना रिकॉर्ड

साड़ी भारतीय महिलाओं की पहचान है, जो उन्हें सशक्त बनाती है। इस बात को इंग्लैंड में रहने वाली भारतीय मूल की महिला ने एक बार फिर सच साबित कर दिखाया है। 46 वर्ष की मधुस्मिता जेना दास ने साड़ी पहनकर मैराथन दौड़ में भाग लिया और सबसे तेज दौड़कर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। उस्टॉकपोर्ट की रहने वाली मधुस्मिता रविवार को मैनचेस्टर मैराथन का हिस्सा बनी थीं। उन्होंने इस दौड़ को 3 घंटे और 45 मिनट का समय लेकर पूरा कर दिखाया। इस दौरान उन्होंने एक खूबसूरत-सी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर फूलों वाला प्रिंट था। उन्होंने अपने इस प्रयास से पिछले रिकॉर्ड को 12 मिनट से भी अधिक के अंतर से तोड़ दिया। इस कमाल के चलते उनका नाम गिनीज बुक में शुमार हो गया है। मधुस्मिता को लोगों का खूब समर्थन मिला।

आईपीएल में आज

मुंबई बनाम हैदराबाद
समय : रात 7.30 बजे से
प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर

परिणाम: हैदराबाद ने मुंबई को 6 विकेट से हराया।

धार जिले के इंदौर-अहमदाबाद एनएच पर दर्दनाक हादसा

मजदूरों से भरी पिकअप स्कॉर्पियो से टकराई, 12 की मौत, 10 गंभीर

पीएम और सीएम ने हादसे पर जताया शोक, मुआवजे का ऐलान

जागरण, धार। प्रदेश के धार जिले के तिरला थाना क्षेत्र में इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार रात दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 10 गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में महिला-पुरुष के अलावा दो बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी अनुसार चिकलिया फाटे के पास मजदूरों से भरे पिकअप का टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। पिकअप ने 3-4 बार पलटी खाई और सड़क के दूसरी ओर जाकर एक स्कॉर्पियो से जा टकराया। पिकअप वाहन में क्षमता से अधिक करीब 40 से 45 मजदूर सवार थे, जो अमझेरा की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। धार जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर छत्रपाल सिंह ने बताया कि 10 घायलों को गंभीर हालत में इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर किया है। वहीं एसपी मयंक अवस्थी के मुताबिक पिकअप वाहन तेज रफ्तार में था। ड्राइवर के नियंत्रण छूटने से वाहन तीन-चार बार पलटा। इसी दौरान सड़क के दूसरी तरफ जाकर स्कॉर्पियो से टकरा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजन को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। वहीं सीएम ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख, गंभीर घायलों को 1-1 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर इंदौर संभागायुक्त और आईजी घायलों के इलाज की व्यवस्था के लिए रात में ही धार पहुंच गए।

जरूरत पड़ी तो निजी अस्पतालों में भेजेंगे: कलेक्टर

हादसे को लेकर कलेक्टर अभिषेक चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। गंभीर रूप से घायल कुछ मरीजों को बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया है। सभी घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मिले, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही 108 एंबुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय किया है। इंदौर जिला प्रशासन, वहां के सीएमएचओ और स्वास्थ्य टीम से समन्वय स्थापित कर लिया है। जरूरत पड़ने पर मरीजों को इंदौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में रेफर किया जाएगा।

मानहानि केस से हाईकोर्ट नाराज

पहले मामला 2046 तक टाला फिर आदेश पलटा

मुंबई, जेएनएन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मानहानि के एक मामले को 2046 तक स्थगित करने के एक दिन बाद बुधवार को अपना आदेश संशोधित करते हुए मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2026 में तय कर दी। जस्टिस जितेंद्र जैन की पीठ ने मंगलवार को इस मामले को पक्षकारों के बीच अहंकार की लड़ाई बताते हुए सुनवाई की तारीख 2046 में दे दी थी। साथ ही पीठ ने कहा था कि इस तरह के मामले न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करते हैं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि ऐसे विवाद न्याय प्रणाली को जाम कर देते हैं। इस पर बुधवार को वादी तारिणीबेन देसाई की ओर से आवेदन दाखिल कर मंगलवार के आदेश में उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया।

सीएम ने जलूद में किया 60 मेगावॉट सोलर प्लांट का लोकार्पण

बिजली उत्पादन में ग्रीन एनर्जी का नवाचार सर्वोत्तम: मुख्यमंत्री

विशेष संवाददाता, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को खरगोन जिले के जलूद में 60 मेगावाट के सोलर पॉवर प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सबसे सस्ती बिजली देने वाला राज्य है। बिजली उत्पादन में ग्रीन एनर्जी का नवाचार सर्वोत्तम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन बॉन्ड स्कीम के माध्यम से इस परियोजना में देश की जनता को भागीदार (पार्टनर) बनाया है। पीपीपी मोड में कार्य करने वाला यह अपनी तरह का देश का प्रथम संयंत्र है। इस तरह से नाते इस राष्ट्रीय उपलब्धि का श्रेय मध्यप्रदेश को जाता है। उन्होने कहा कि इस परियोजना की लागत 10 साल में निकल जाएगी, अगले 10 साल सिर्फ लाभ के होंगे। डॉ. यादव ने कहा कि इस परियोजना में कोई भी व्यक्ति एक-एक लाख के 10 बॉन्ड खरीद सकता है। एक लाख पर लगभग 8 प्रतिशत की बचत होगी, जिसका लाभ 20 साल तक मिलेगा। अगर जरूरत पड़े तो इस बॉन्ड को बेचा भी जा सकता है। इस प्रकार से राज्य सरकार ने घर बैठे लोगों को पैसे कमाने का अवसर दिया है। उन्होंने बताया कि जलूद सोलर पॉवर प्लांट का भूमि-पूजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2023 में किया था। डॉ.यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश बदल रहा है। एक समय था, जब रात में बिजली कटौती होती थी, दिन में बिजली तो मिलती ही नहीं थी, ■ शेष पृष्ठ 7 पर

बकायादारों ने पूर्व राज्यमंत्री को शादी समारोह में घेरा, चार घंटे चला हंगामा

भिंड का मामला: 10 दिन में पैसे लौटाने को कहा तब शांत हुए लोग

जागरण, भिंड। जिले में भारौली रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में चल रहे शादी समारोह में हंगामा हो गया। यहां मप्र सरकार में पूर्व राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त और बीज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. राजकुमार कुशवाहा को बकायादारों ने घेर लिया। करीब चार घंटे तक चले इस घटनाक्रम में स्थिति बिगड़ती देख मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। मालूम हो कि डॉ. कुशवाहा रात के करीब 9 बजे एक शादी समारोह में पहुंचे थे। शादी के कार्ड में उनके बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का उल्लेख किया गया था। इसके बाद शहर और गांवों से दो दर्जन से अधिक लोगों कुशवाह को घेर लिया।

पुलिस के सामने भी अड़े बकायादार

शादी समारोह में पहले तो डॉ. कुशवाहा ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ का आक्रोश बढ़ता गया। रात 12 बजे तक खुद को घिरा देख उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम और देहात थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कुशवाहा को थाने ले जाना उचित समझा। बकायादार भी उनके पीछे-पीछे थाने पहुंच गए। यहां उन्होंने 10 मई तक बकाया राशि लौटाने का आश्वासन दिया। इसके बाद मामला शांत हो गया।

ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीय डिपोर्ट, इनमें 11 पंजाबी

चंडीगढ़, जेएनएन। ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि इनमें 11 पंजाबी हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वह रात में दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि वह उन्हें दिल्ली से रिसीव करने जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि अब तक जो सूची मिली है, उसमें केवल होम स्टेट पंजाब लिखा हुआ है। कुल 15 लोगों की सूची है, जिनमें 2 तेलंगाना, 1 हरियाणा और 1 उत्तराखंड के रहने वाले हैं। सीएम ने कहा जब से ट्रंप जहाज भेजा अमेरिका से डिपोर्टेशन शुरू हुआ था। उस समय से हम अपनी तरफ से उनके पुनर्वास में लगे हुए हैं। सीएम ने कहा जो लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में हम इनसे सारी जानकारी हासिल करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी खारिज

तीस्ता सीतलवाड़ का पासपोर्ट देने से इनकार

नई दिल्ली, जेएनएन। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने फिलहाल उनका जब्त पासपोर्ट वापस करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस विदेश यात्रा योजना के पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई निश्चित यात्रा कार्यक्रम पेश किया जाता है, तो इस अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। तीस्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि विदेश यात्रा के लिए उन्हें पासपोर्ट की आवश्यकता है।

बदलाव | एफएसएसएआई ने पेश किया ड्राफ्ट, स्टेकहोल्डर्स से मांगी दावा-आपत्ति

गुटखा के प्लास्टिक पाउच पर रोक लगेगी

इको-फ्रेंडली मटेरियल से पैकिंग अनिवार्य करने की तैयारी

नई दिल्ली, जेएनएन। अब जल्द ही आपको गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के प्लास्टिक पाउच नजर नहीं आएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने कहा कि पान मसाला की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक मटेरियल को अब कागज, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज और अन्य इको-फ्रेंडली मटेरियल से बदला जाएगा।

इसके लिए एफएसएसएआई ने मंगलवार को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियमन 2018' में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट 'प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2026' पर अगले 30 दिन तक स्टेकहोल्डर्स से राय और आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद इस नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को होने वाले भारी नुकसान को रोकना है। पान मसाला और तंबाकू के छोटे-छोटे प्लास्टिक सैशे अक्सर नालियों और सड़कों पर कचरे का बड़ा अंबार खड़े कर देते हैं, जिन्हें डिस्पोज करना नामुमकिन होता है। प्राकृतिक सामग्री के इस्तेमाल से इस कचरे को कम करने में मदद मिलेगी।

प्लास्टिक या विनाइल का किसी भी रूप में उपयोग नहीं होगा

नए प्रस्ताव के अनुसार, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के किसी भी पैकेज में किसी भी रूप में प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसमें 'विनाइल एसीटेट-मेलिक एसिड-विनाइल क्लोराइड कोपोलिमर' जैसे केमिकल युक्त मटेरियल पर भी पाबंदी होगी।अब जल्द ही आपको गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के प्लास्टिक पाउच नजर नहीं आएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने कहा कि पान मसाला की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक मटेरियल को अब कागज, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज और अन्य इको-फ्रेंडली मटेरियल से बदला जाएगा। इसके लिए एफएसएसएआई ने मंगलवार को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियमन 2018' में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट 'प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2026' पर अगले 30 दिन तक स्टेकहोल्डर्स से राय और आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद इस नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा।

कागज और सेल्युलोज से बने पाउच का ऑप्शन

एफएसएसएआई ने सलाह दी है कि अब प्लास्टिक पाउच की जगह कागज, गत्ते (पेपरबोर्ड) और सेल्युलोज जैसे नेचुरल सामान का इस्तेमाल किया जाए। रेगुलेटर का कहना है कि ये चीजें खाने-पीने का सामान पैक करने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। साथ ही, कंपनियों के लिए भी इन नए मटेरियल को अपनाना और इस्तेमाल करना आसान होगा।

टीन और कांच के कंटेनर्स का विकल्प रहेगा बरकरार

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, जो निर्माता पाउच के बजाय टीन या कांच के कंटेनर्स का उपयोग कर रहे हैं, वे उसे जारी रख पाएंगे। इससे मैन्युफैक्चरर को कमर्शियल जरूरतों के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी।

चीफ जस्टिस ने वर्चुअल सुनवाई रोकी, जांच के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में चला अश्लील वीडियो

दावा: अमेरिका से हैक किया गया अकाउंट

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को वर्चुअल सुनवाई के दौरान अश्लील वीडियो चल गया। उस वक्त चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस खरिया की बेंच सुनवाई कर रही थी। यह मामला दोपहर 12:56 बजे का है।

यह साफ नहीं हुआ है कि वारदात के वक्त बेंच किस मामले में सुनवाई कर रही थी। जैसे ही पोर्न वीडियो चला, फौरान सुनवाई रोक दी गई। कुछ मिनट बाद सुनवाई दोबारा शुरू हुई, फिर पोर्न वीडियो चलने लगा। मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट को दी गई है। वर्चुअल सुनवाई के दौरान कई लोग जुड़े

हुए थे। इनमें एक क्षितिजीत सिंह थे। शुरुआती पूछताछ में क्षितिजीत ने दावा किया कि उसका अकाउंट अमेरिका से हैक किया गया था। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सुनवाई के दौरान वह अश्लील वीडियो कैसे चला।

बुधवार को सुनवाई के दौरान वीडियो चलने के बाद 'आपका सिस्टम हैक हो गया है', का मैसेज भी स्क्रीन पर दिखाई दिया। दो बार पोर्न वीडियो चला और तीसरी बार म्यूजिक वीडियो चला। कोर्ट में 100 से ज्यादा जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी।

रिहायशी क्षेत्र में ही फेंक दिया मेडिकल कचरा

समान तिराहे की घटना, लोगों ने की नगर निगम में शिकायत

जागरण, रीवा। शहर के समान तिराहे पर स्थित एक निजी अस्पताल से निकलने वाला मेडिकल कचरा यहां के सफाई कामगारों ने सड़क पर ही डाल दिया, जिसे डालते देख उक्त क्षेत्र के रहवासियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें दोबारा यहां कचरा न डाले जाने की हिदायत दी और नगर निगम में इसकी शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की। समान तिराहा के लोगों ने बताया कि यहां स्थित बालाजी हॉस्पिटल से निकलने वाला मेडिकल कचरा पन्नियों में भरकर यहां सफाई करने वाले सड़क पर ले आए और सड़क पर ही कचरे का ढेर लगा दिया। जिन्हें कचरा फेंकते हुए यहां के रहवासियों ने देख लिया और उनसे पूछा कि यह कचरा फेंकने की जगह है, जिसका वे कोई जवाब नहीं दे पाए। लोगों ने बताया कि मेडिकल कचरा सड़क पर डाले जाने से आसपास के रहवासियों को इन्फेक्शन का खतरा है वहीं सड़क पर डाले गए कचरे में आवारा मवेशी व श्वान आदि भी मुंह मारने से बीमार हो सकते हैं, यह क्षेत्र रिहायशी क्षेत्र है जानते हुए भी हॉस्पिटल वालों द्वारा सड़क पर ही कचरा डाला जा रहा है। समान क्षेत्र के रहवासियों ने नगर निगम में शिकायत कर सड़क पर मेडिकल कचरा फेंकने व फिकवाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की है, और दोबारा यहां कचरा न फेंके, इसकी भी व्यवस्था की जाए।

PIONEERS SCHOOL OF EXCELLENCE
Behind Vrindawan Colony Near Janta College Anantpur, Rewa (M.P.)
ADMISSION FEES में विशेष छूट 30.04.2026 तक
Nursery to 10th Class An English Medium School
CBSE Pattern Formerly shemrock
National School Award 2021 Winner
Vacancy For - Pre-Primary teacher, PRT (science/mathematics) & office reception.
ADMISSION OPEN Now
Session : 2026-27
Phone No.: 8370073017, 9109143141

अभी कर रहे कचरा एकत्रित, ढेर लगने पर लगा देंते हैं आग

जागरण, रीवा। शहर से निकलने वाला अधिकांश कचरा या तो वार्डों में पड़ा उड़ता रहता है अथवा हटाया भी जाता है तो नगर निगम के वाहन चालक कचरा पहड़िया प्लांट पर भेजने की बजाय लाडली लक्ष्मी पथ पर बीहर नदी के किनारे डाल देते हैं, जब यहां अच्छा खासा कचरे का ढेर लग जाता है तो उसमें आग लगा दी जाती है। गत वर्ष यहां डाले गए कचरे में आग लगाने के कारण आग सड़क किनारे स्थित नर्सरी के अंदर तक पहुंच गई थी, जिस पर काबू करने के लिए तीन-चार फायर ब्रिगेड मंगवाना पड़े थे, उक्त घटना से सबक न लेते हुए अभी भी यहां कचरा डाला जा रहा और कचरे के ढेर में आग लगा दी जाती है। पहड़िया में कचरा प्लांट से बिजली उत्पादन और खाद निर्माण किया जा रहा है, जब कचरा वहां तक पहुंच ही नहीं रहा तो कौन से कचरे से खाद बन रही है और किस कचरे से बिजली उत्पादन हो रहा, ये जांच का विषय है।

बीहर नदी के दोनों किनारे पर हो रहे अवैध निर्माण चिन्ताजनक

एमआईसी सदस्य धनेन्द्र सिंह ने लिखा कलेक्टर को कार्यवाही के लिए पत्र

जागरण, रीवा। जिला प्रशासन के अनदेखी के चलते शहर में बेतरतीब निर्माण के कारण मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ रही हैं। अगर इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो बररसात के मौसम में शहर को जलमग्न होने से कोई नहीं बचा पाएगा। एमआईसी सदस्य धनेन्द्र सिंह ने पत्र लिखकर कलेक्टर को जानकारी दी है कि बीहर नदी के दोनों किनारों पर जिस तरह से निर्माण चल रहा ह, इसमें रोक नहीं लगाई गई तो बरसात के समय रीवा शहर को डूबने से कोई नही बचा नही पाएगा। उन्होंने कलेक्टर को लिखे पत्र में बताया है कि बीहर नदी के किनारे हो रहे अवैध निर्माण चिन्ताजनक हैं। अतिक्रमण हट नहीं रहा अपितु बढ़ता ही जा रहा है। वार्ड 6 झिरिया, एवं बांसघाट एवं रीवा शहर मे बाढ़ की समस्या अधिक है। एमआईसी सदस्य धनेन्द्र सिंह ने जानकारी दी है कि रीवा शहर के मास्टर प्लान के अनुसार बीहर व बिछिया नदी के किनारे दोनों तरफ 50 मीटर तक ग्रीन बेल्ट निर्धारित किया गया है, जहां किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होना है और यह बाढ़ क्षेत्र सुरक्षा के लिये कांक्रीट निर्माण, मकान, ना ही कोई व्यावसायिक नो कंस्ट्रक्शन जोन के रूप मे चिन्हित है, पर प्रायःयह देखा जा रहा है कि मास्टर प्लान को एवं निगम प्रशासन, जिला प्रशासन दरकिनार कर आये दिन कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। पहले रिवर फ्रंट, ईको पार्क सहित बीहर नदी के किनारे से बिल्कुल सट कर वार्ड 6 के अपोजिट साइड लगभग 100 पक्के मकानों का निर्माण हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस पर प्रशासन मूकबधिर बना है, करहिया पुल एवं घर के किनारे के आसपास आलीशान विवाह घर एवं कॉटेज आदि के बिना मंजूरी के निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर अगर रोक नही लगाई गई तो आगामी बरसात में रीवा शहर को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा।

संजय गांधी अस्पताल में पानी के लिए तरस रहे मरीज-अटेंडर, प्रबंधन बेपरवाह

जागरण, रीवा। शहर के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में इस भीषण गर्मी के दौरान अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। यहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी तरसना पड़ रहा है। अस्पताल के तीसरी और चौथी मंजिल के वार्डों में पानी की व्यवस्था पूरी तरह ठप है, जिससे अटेंडर को पानी लेने के लिए बार-बार ग्राउंड फ्लोर तक भागना पड़ रहा है। अस्पताल की ऊपरी मंजिलों पर लगे वाटर कूलर महीनों से खराब पड़े हैं। कई जगह तो नल से बूंद भर पानी नहीं टपक रहा। भीषण गर्मी में मरीजों और परिजनों को प्यास बुझाने के लिए 3-4 मंजिल सीढ़ियां उतरनी और चढ़नी पड़ रही हैं। बीमार मरीज को अकेला छोड़कर परिजन पानी के लिए भटक रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि दिन में तो किसी तरह जुगाड़ हो जाता है, लेकिन रात के समय ग्राउंड फ्लोर तक जाना जान जोखिम में डालने जैसा है। मजबूरी में कई परिजन बाहर से महंगी पानी की बोतलें खरीद कर पीने को मजबूर हो रहे हैं। गरीब मरीजों के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन गया है। मरीजों के परिजनों ने बताया कि लगातार शिकायतों के बाद भी अस्पताल प्रबंधन सुध लेने को तैयार नहीं है। पूछने पर सिर्फ तकनीकी खराबी और जल्द समाधान का रटा-रटाया जवाब मिलता है। सवाल यह है कि जब सबसे बड़े अस्पताल में पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिलेगी तो आम आदमी कहां जाए? प्रबंधन की इस लापरवाही से मरीजों की परेशानी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

तीसरी और चौथी मंजिल पर एक बूंद पानी नहीं, ग्राउंड फ्लोर तक लगानी पड़ रही दौड़

कलेक्टर ने विलंब से पहुंचने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों की लगाई क्लास

समय पर न आने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्यवाही

रीवा। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कलेक्टर कार्यालय के गेट में विलंब से पहुंचने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की क्लास लगाई। उन्होंने स्वयं मुख्य गेट में खड़े होकर देरी से कार्यालय आने वालों को लाइन से खड़ा किया तथा सख्त लहजे में हिदायत दी कि समय पर कार्यालय आएं। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा सुबह 10 बजे कार्यालय खुलने का समय निर्धारित किया गया है अतः सभी नियत समय पर आएं और अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने विलंब से आने वालों को चेतावनी दी कि यह पहला अवसर है अतः आज उनका आधे दिन का अवकाश स्वीकृत होगा। भविष्य में देरी से आने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी व कर्मचारी अब डिजिटली अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उन्होंने इस संबंध में तत्काल व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। सूर्यवंशी ने कहा कि सभी कार्यालय में अधिकारी से कर्मचारी शासन के हित में अनुशासित होकर कार्य करें व निर्धारित समय तक कार्यालय में उपस्थित रहें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

चार पर कार्यवाही के निर्देश : कलेक्टर ने जिला पंचायत कार्यालय का किया औचक निरीक्षणः कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला पंचायत कार्यालय का सुबह 10.05 बजे आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मात्र चार अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने अनुपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।

नगरीय निकायों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय

रीवा। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि पुनरीक्षण के लिए 30 अप्रैल को कंट्रोल टेबल चेकलिस्ट वेंडर द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाएगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसमें 2 मई तक आवश्यक संशोधन करके 5 मई तक डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन करेंगे। वेंडर 15 मई तक प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण करके रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। पुनरीक्षण के लिए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 15 मई को होगा। मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियाँ 25 मई को दोपहर 3 बजे तक दर्ज की जाएंगी। इनका निराकरण 30 मई तक किया जाएगा। दावे-आपत्तियों की चेकलिस्ट 6 जून तक तैयार करके रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसे 8 जून तक वेण्डर को उपलब्ध कराएंगे। फोटो युक्त अंतिम मतदाता सूची का मुद्रण वेण्डर 16 जून तक करेंगे। अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन 18 जून को किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 20 जून तक मतदाता सूची की सीडी और डीवीडी बिक्री के लिए उपलब्ध कराएंगे। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को 22 जून तक मतदाता सूची की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

पेयजल टंकी होने के बादजूद एक समय वह भी आधा घंटा मिल रहा पानी

पड़रा क्षेत्र के रहवासी पानी के लिए हो रहे परेशान

जागरण, रीवा। शहर के वार्ड क्रमांक 5 पड़रा के रहवासियों की कुएं के पास प्यासे वाली स्थिति बनी हुई है, कहने तो यहां पेयजल टंकी बनी है, जिससे यहां पानी की कमी नहीं होना चाहिए, किन्तु वार्ड में टंकी होने के बावजूद यहां के रहवासियों को इसका भरपूर लाभ नहीं मिल रहा। वार्ड में पीएचई द्वारा प्रतिदिन एक समय ही महज आधा घंटा के आसपास जल प्रदाय किया जा रहा है, जिससे लोगों की पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, सीवरेज लाइन डाली जाने से इस क्षेत्र में भी कई स्थानों पर पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिससे वार्ड के सभी लोगों को पानी नहीं मिल रहा। वार्ड के रहवासियों ने बताया कि शुरुआत से ही इस क्षेत्र के लोग पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए मशक्कत कर रहे हैं, वार्ड के प्रवेश द्वार पर पेयजल टंकी बनी है, जिससे वार्ड में तो पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाना चाहिए, किन्तु यहां के लोगों को शाम के समय आधा घंटा पानी प्रदाय किया जा रहा है, जल प्रदाय होने पर लोगों के घरों तक पानी पहुंचने में ही दस मिनट लग जाता है, पानी भर भी नहीं पाते और बंद कर दिया जाता है, बड़ी मुश्किल से पीने के लिए दो-चार बर्तन भर पाते हैं। पीने का पानी तो भर लेते हैं, किन्तु नहाने, कपड़े धोने व अन्य उपयोग के लिए आसपास से या अन्य जल स्रोतों से व्यवस्था करना पड़ रही है, लोग अपने कामकाज छोड़ पानी की जुगाड़ में लगे रहते हैं। कई लोगों के घरों में बोरिंग है तो लोग उनसे आग्रह कर चार-छः पानी के बर्तन भर लेते हैं, वार्ड में कोई हैंडपंप भी नहीं और न ही अन्य कोई स्रोत है।

प्रजापति कुंभकार महासंघ ने दीं पंचूलाल को शुभकामनाएं

रीवा। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ जिला इकाई के संरक्षक डॉ. आर.बी. प्रजापति द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मनगवां के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ समाजसेवी डॉ. पंचूलाल प्रजापति को विंध्य विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ जिला इकाई के महावीर प्रजापति डॉ. जयरामदास प्रजापति डॉ. बुद्धि लाल प्रजापति डॉ दिनेश प्रजापति शिवानंद प्रजापति शशिकांत प्रजापति सुखनंदन प्रजापति सुरेश प्रजापति डॉ. तपन प्रजापति राममिलन प्रजापति संतोष कुमार प्रजापति बालमहेंद्र प्रजापति सुशील कुमार प्रजापति सुनीता प्रजापति नीतू प्रजापति सविता प्रजापति मोरध्वज प्रजापति शिवराज प्रजापति मदन प्रजापति बबलू प्रजापति पदाधिकारियों एवं समाजजनों ने डॉ. पंचूलाल प्रजापति को इस महत्वपूर्ण दायित्व हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की है।

समर्थन मूल्य पर 24651 मी. टन हुई गेहूं की खरीद

रीवा। किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पंजीकृत किसानों से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है। अब तक 7928 किसानों से 24651 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी कमलेश तांडेकर ने बताया कि गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 19891 किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं। उपार्जित गेहूं में से 8201 मीट्रिक टन का परिवहन कराकर सुरक्षित भण्डारण करा दिया गया है। अब तक किसानों को 72 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उपार्जन के लिए सभी खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिले में 76 खरीदी केन्द्रों में गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है। अब सभी किसान उपार्जन के लिए अपनी सुविधा के अनुसार स्लॉट बुक कर सकते हैं। उपार्जन के लिए साफ-सुथरा और गुणवत्तापूर्ण गेहूं उपलब्ध कराएं।

शिक्षा में मूल्यों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है: प्रो.तिवारी

भारतीय शिक्षण मंडल के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन

जागरण,रीवा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में भारतीय शिक्षण मंडल के 57वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्व. का बोध रहा। जिसमें शिक्षा के भारतीयकरण मूल्य आधारित शिक्षा और राष्ट्र निर्माण पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय शिक्षण मंडल के ध्येय वाक्य एवं ध्येय श्लोक के साथ हुआ, जिसके उपरांत सभी अतिथियों का शाल-श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में डॉ.सतीश मिश्रा ने भारतीय शिक्षण मंडल का परिचय एवं विषय प्रवेश प्रस्तुत किया। इसके पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.रवीन्द्र नाथ तिवारी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा में मूल्यों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें संस्कार, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का समावेश भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भारत केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर ही मूल्य आधारित शिक्षा का पुनर्निर्माण और नवाचार संभव है। डॉ. तिवारी ने यह भी कहा कि आज समाज में विचारों का विखंडन दिखाई दे रहा है, जिसका प्रमुख कारण मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भावी पीढ़ी के समग्र विकास बौद्धिक नैतिक और सांस्कृतिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। साथ ही, उन्होंने भारतीय शिक्षण मंडल के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संगठन भारतीय संस्कृति और ज्ञान पर आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है, जिससे राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त कर पुनः विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित सके। डॉ. कमलेश मिश्रा ने भारतीय शिक्षण मंडल को एक वैचारिक संगठन बताते हुए कहा कि शिक्षा में भारतीयता का समावेश ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आचार्य निर्माण और परिवर्तन के वाहक होते हैं, इसलिए समाज में जाकर शिक्षा की एकता पर कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने फिनलैंड में गुरुकुल पद्धति के प्रारंभ का उदाहरण देते हुए भारतीय शिक्षा पद्धति की वैश्विक स्वीकार्यता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ.श्रीनारायण तिवारी, जिला संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत की आर्थिक मजबूती का प्रमुख आधार कृषि रहा है लेकिन मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने भारत को भीतर से कमजोर करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि भारतीय शिक्षण मंडल का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने समाज के समग्र विकास हेतु पाँच प्रमुख बिंदुओं सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन स्व की भावना पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्य पर विशेष जोर दिया। मुख्य वक्ता डॉ.हरिश्चंद्र द्विवेदी प्रांत संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय इतिहास और संस्कृति की प्राचीनता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विष्णुपुराण सहित अनेक ग्रंथ हमारे गौरवशाली अतीत के प्रमाण हैं। उन्होंने रामसेतु के कार्बन डेटिंग परीक्षण का उल्लेख करते हुए भारत की प्राचीन वैज्ञानिक समृद्धि को रेखांकित किया। गीता, महाभारत और आचार्य चाणक्य के उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने स्व की भावना को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत ने हजारों वर्षों के आक्रमणों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी संस्कृति और मूल्यों को सुरक्षित रखा है। गुरु तेगबहादुर जैसे महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए 'स्व' की भावना को समझना आवश्यक है। अपने देश, संस्कृति और समाज के प्रति समर्पण ही स्व का वास्तविक अर्थ है। डॉ. द्विवेदी ने आगे कहा कि जीवन में विशिष्टता, मृदुता, व्यवहार कुशलता और भारतीयता का समावेश आवश्यक है। भारतीय वेशभूषा, भाषा और संस्कृति का ज्ञान हमें अपनी पहचान से जोड़ता है। उन्होंने संस्कृत भाषा की समृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ज्ञान और विविधता का अद्भुत संगम है। अंत में डॉ.जीएन सिंह अध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल जिला रीवा ने सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं सहभागियों का आभार व्यक्त किया।

विवेकानंद स्पीच एण्ड हियरिंग सेन्टर
• बच्चों का कम बोलना
• बोलते समय हकलाना
• बच्चों की सुनने की जांच
• ऑटिज्म बच्चों की स्पीच थैरेपी
• डिजिटल कान की मशीन (सभी उम्र के लोगों के लिए)
• स्पीच थैरेपी
• ऑटिज्म थैरेपी
VIVEKANAND PANDEY
Audiologist & Speech Language Pathologist
पता: यादवेन्द्र टॉवर, अंगूरी बिल्डिंग के सामने, सुभाष चौक, युनिवर्सिटी रोड, रीवा (म.प्र.) मोबा. 7800687955

विंध्य की एक मात्र महिला चर्म रोग विशेषज्ञ
समय-प्रतिदिन सुबह 10 से 2 एवं शाम 4 से 7 बजे तक रविवार अवकाश
डॉ. कोम्पल अग्रवाल
MBBS, MD (Dermatology & STD)
चर्म, सौंदर्य, नाखून, बाल, यौन, एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ
अत्याधुनिक Laser द्वारा Hair Removal, Tatto Removal एवं Facial की सुविधा उपलब्ध
परामर्श:- दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस, सफेद दाग, चेहरे की कील, मुहांसे, बालों का झड़ना, गंजापन, इत्यादि समस्त चर्म, नाखून, बाल एवं यौन संबंधी समस्याएं।
विशेष:- Co2 एवं MNRF LASER के द्वारा पिम्पल के गढ्ढे, दाग, झुर्रियाँ Stretch Marks, आदि के लिए इलाज की सुविधा
मो.-7247097637
परामर्श शुल्क 300/-
परामर्श क्लीनिक: शॉप नं. 86 तानसेन कॉम्प्लेक्स कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम के सामने सिरमौर चौराहा रीवा (म.प्र.)

THE BRAIN SHAPER SENIOR SECONDARY SCHOOL
ISO 9001:2015 Certified
Nursery to 12th | English Medium | Math | Bio | Com.
Director - Coach B.M. SHARMA
For : 12th, IIT (JEE), MBBS, Nursing and CA
पढ़ाई की सर्वोत्तम क्वालिटी
संपूर्ण व्यक्तित्व विकास
योग, संगीत एवं कराटे की नियमित कक्षाएं.
कम सीटें उपलब्ध, शीघ्र संपर्क करें
समान बांध, रीवा 9300607071
Website-www.thebrainshapers.com

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास क्रमांक-T2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2026-27 (C-18)

(मध्यप्रदेश राज्य शासन के शासकीय, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) एवं निजी पोलीटेक्निक संस्थान)

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

डिप्लोमा आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम

एकलव्य/डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु

प्रथम चरण	
गतिविधियां	**दिनांक/समय**
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन निरस्त	04.05.2026 से 29.05.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) (सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पश्चात केवल एक बार उपलब्ध रहेगी)	30.05.2026 से 31.05.2026 सायं 5:30 बजे तक
संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी)	15.05.2026 से 02.06.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	03.06.2026
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति (आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश)	08.06.2026 से 13.06.2026 सायं 6:30 बजे तक
द्वितीय चरण	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन निरस्त	09.06.2026 से 18.06.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) (सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पश्चात केवल एक बार उपलब्ध रहेगी)	19.06.2026 से 20.06.2026 सायं 5:30 बजे तक
संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी)	10.06.2026 से 22.06.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	23.06.2026
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति (आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश)	27.06.2026 से 03.07.2026 सायं 6:30 बजे तक
संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) (काउंसलिंग के केन्द्रीयकृत चरण उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये)	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	**प्रवेश के अवसर का दिनांक/समय**
04.07.2026 से 12.08.2026	दिनांक 06 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
13.08.2026 से 14.08.2026 अंतिम तिथि को रजिस्ट्रेशन दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा	14.08.2026 प्रातः 10:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी के लिये महत्वपूर्ण निर्देश, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग में **इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये** निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।

प्रवेश निरस्त

➢ काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक तथा संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में, प्रवेश का अवसर प्राप्त करने की दिनांक को, प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

- **संपर्क :- 0755-6720205, 2660441, ईमेल :- dte.helpcenter@mp.gov.in**

अतिरिक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

म.प्र. माध्यम/125551/2026

दैनिक जागरण
रीवा, 30 अप्रैल, 2026
www.dainikjagranmpcg.com

रीवा जागरण

03

शहर का तापमान/मौसम
अधिकतम 42.0°c न्यूनतम 26.0°c
जिले भर में तेज धूप के साथ लू चलने की संभावना

11 राज्य 31 संस्करण
मध्य प्रदेश • उत्तर प्रदेश • दिल्ली • हरियाणा • उत्तराखंड • पंजाब • जम्मू-कश्मीर • बिहार • झारखंड • हिमाचल प्रदेश • पश्चिम बंगाल से प्रकाशित

डाक विभाग की योजनाओं का लाभ उठाएं: कलेक्टर

रीवा। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा है कि भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा डाक जीवन बीमा तथा अन्य आकर्षक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सभी अधिकारी और कर्मचारी इन योजनाओं से लाभ उठाएं। डाक बीमा योजना में बीमा की सीमा न्यूनतम 20 हजार रुपए तथा अधिकतम 50 हजार रुपए निर्धारित है। सभी 19 से 55 आयु वर्ग के कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं। डाक जीवन बीमा में निवेश करने पर आयकर की धारा 80 सी के तहत आयकर छूट का लाभ मिलता है। कम प्रीमियम पर पूर्ण रिस्क कवर और अधिक बोनस का लाभ दिया जा रहा है। इस आकर्षक योजना से कर्मचारियों के लिए निश्चित आर्थिक सुरक्षा का लाभ और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रखने की सुविधा मिल रही है। डाक बीमा योजना में ऑनलाइन प्रीमियम जमा करने की भी सुविधा है। योजना का लाभ उठाने के लिए विकास अधिकारी डाक विभाग के मोबाइल नम्बर 9993872638 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त
कामता सोनोग्राफी सेन्टर
(अल्ट्रासाउण्ड)
डॉ. रश्मी शुक्ला
M.D. (Radio Diagnosis) G.S.V.M. Medical College Kanpur
Ex. J.R. AIIMS New Delhi
Ex. Consultant Radiologist Alpha Imaging & MRI Kanpur
Ex. Consultant Radiologist Noble Hospital Kanpur
ए-ब्लॉक, समदड़िया सेन्टर प्वाइन्ट, न्यू बस स्टैण्ड, रीवा (म.प्र.) 07662-451599,9399312433

केसीसी कंपनी की मनमानी से इटौरा विश्वविद्यालय मार्ग बिना डायवर्सन बंद

प्रोजेक्ट मैनेजर के बयान से भड़का जनाक्रोश, समाधान नहीं तो होगा जनांदोलन

जागरण, रीवा

शहर में रतहरा से चोरहटा तक निर्माणाधीन फोरलेन सड़क अब वाहनों के साथ-साथ स्थानीय जनता के लिए भी रोज की परेशानी का कारण बनती जा रही है। निर्माण एजेंसी केसीसी कंपनी की लापरवाही के कारण इटौरा-विश्वविद्यालय मार्ग कंपनी ने बिना किसी वैकल्पिक डायवर्सन के मुख्य मार्ग को अचानक बंद कर दिया, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण एजेंसी की लापरवाही और मनमानी ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह सड़क न केवल शहर बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी एक प्रमुख संपर्क मार्ग है। रोजाना हजारों भारी वाहन के साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन केसीसी कंपनी द्वारा सड़क पर मलबा डालकर और खोदाई कर मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है। हालात इतने खराब हैं कि सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे, पानी भरा हुआ और किनारे निर्माण सामग्री के ढेर लगे हुए हैं जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि कंपनी ने न तो कोई पूर्व सूचना दी और न ही कोई वैकल्पिक मार्ग (डायवर्सन) तैयार किया। अचानक रास्ता बंद होने से लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं और कई बार उन्हें लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे, नौकरीपेशा लोग और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। बताया गया है कि जब स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर केसीसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से संपर्क किया तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने साफ शब्दों में कहा कि सड़क नहीं खोलेंगे। इस बयान ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है और अब मामला प्रशासन तक पहुंच चुका है। ग्रामीणों और शहरवासियों ने संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराते हुए तत्काल सड़क खोलने और उचित डायवर्सन की व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि विकास कार्य का मतलब जनता को परेशानी देना नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासन ने जल्द हस्तक्षेप नहीं किया तो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है जब केसीसी कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता, धूल प्रदूषण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर कई बार शिकायतें सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इस बार सख्त कदम उठाएगा या फिर जनता को इसी तरह परेशानियों के बीच जीना पड़ेगा। फिलहाल रीवा में विकास के नाम पर चल रहा यह निर्माण कार्य आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है और लोगों की नजरें अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण में अभी एक महीना और

बीहर नदी के क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण में हो रही देरी के कारण सारा ट्राफिक शहर से होकर गुजर रहा रहा है। लेकिन जिस तरह से निर्माण में देरी चल रही है उसमें अभी पुल के नीचे बेस का निर्माण चल रहा है। अगर निर्माण में देरी हो रही है तो इसके लिए निर्माण एजेंसी को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता है। जो कंपनी पुल की मरम्मत कर है, उसके मुताबिक इसमें अभी एक महीना लग सकता है।

रात्रि में जाम से नहीं मिल रही निजात ओवरटेक करने में फंस जाते हैं वाहन

रात्रि 11 बजे बाद से छोटे वाहन चालकों का चलना मुश्किल

जागरण, रीवा। शहर के समीप बायपास में स्थित बीहर नदी के क्षतिग्रस्त हुए पुल के कारण रात्रि 11 बजे बाद से बायपास से निकलने वाले वाहनों को शहर से गुजारा जाता है, वाहन आगे निकालने की होड़ में शहर के अंदर ही इतनी तेज गति से वाहन दौड़ाए जाते हैं कि आसपास से निकलने वाले वाहन चालकों को भी नहीं देखते, कई बार ओवरटेक के चक्कर में वाहन फंस जाते हैं, जिससे रास्ता जाम हो जाता है। रात्रि में प्रतिदिन इस प्रकार की स्थिति बरकरार होती है। ओवरलोड व भारी वाहनों की रफ्तार के चलते रात्रि 11 बजे के बाद छोटे वाहन चालकों के लिए अपने वाहन निकालना किसी करतब से कम नहीं। मंगलवार रात्रि भी रतहरा में जाम लग गया, जिससे यहां ओवरलोड सहित छोटे, बड़े वाहनों की भीड़ लग गई। शहर में सीवरेज लाइन निर्माण के चलते जगह-जगह सड़क खुदी है, सड़क पर ही खोदे गए मलबे के ढेर लगे हैं, जिससे इन स्थानों पर एक वाहन से अधिक वाहन नहीं निकल पाते, इस कारण भी बार-बार जाम लगता है।

शादी समारोह में शामिल होने आए वृद्ध बस छूटने से भटके

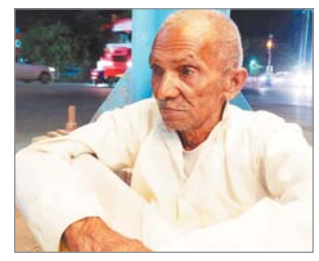

जागरण, रीवा। शादी समारोह में शामिल होने आए एक 80 वर्षीय वृद्ध बस छूटने से रास्ता भटक गए और काफी देर तक परेशान होते रहे। आखिरकार उन्होंने सिविल लाइन थाना स्थित कनौडिया पेट्रोल पंप के समीप खंभे के पास आश्रय लिया और रात वहीं गुजारी। वृद्ध अधिक जानकारी दे पाने में असमर्थ थे, उन्होंने अपना नाम पंचम जोगी, पत्नी का नाम रामरजिया व पुत्र का नाम उपेंद्र जोगी निवासी नईगढ़ी मऊलिया ग्राम बताया। वृद्ध ने बताया कि 27 अप्रैल को शादी में शामिल होने वे घर से निकले थे।

बाणसागर तलैया भवन अनुज्ञा मामले में निगम को दिया जवाब

हितग्राही ने लिखा- नहीं थी हाईकोर्ट के प्रकरण की जानकारी

अनुज्ञा के लिए लगाए गए दस्तावेजों में बताई जा रही कमी पर नहीं दिया जा रहा ध्यान

जागरण,रीवा। नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा में हुए फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्यवाही नगर निगम करने की तैयारी में है, बाणसागर तलैया भवन अनुज्ञा मामले में हितग्राही में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन पाए जाने के बाद हितग्राही को नोटिस जारी किया गया था। जिसका जबाव हितग्राही ने दे दिया है, हालांकि हितग्राही ने जबाव में एक बार फिर यही लिखा है उनको हाईकोर्ट में विचाराधीन की जानकारी नहीं है। हालांकि हितग्राही के जबाव को संतोषप्रद नहीं माना जा रहा है। वजह यह भी है कि कहा जा रहा है कि नगर निगम को दिए गए एक शपथ पत्र में हितग्राही ने बिना हस्ताक्षर के ही शपथ पत्र दे दिया। जब दस्तावेज पूरे नहीं किए गए तो किस आधार पर अनुज्ञा दे दी गई। हालांकि नगर निगम द्वारा मामले में विधिक राय लॉ ऑफिसर से ली गई है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

यह है मामला

मामला लगातार चर्चा में बने हुए बाणसागर तलैया में भवन अनुज्ञा का है, बताया गया कि बीते 30 दिसंबर 2025 को नगर निगम के सहायक यंत्री अंबरीश सिंह द्वारा अपने सेवानिवृत्त के ठीक एक दिन पहले बाणसागर स्थित आराजी क्रमांक 631/2 रकबा 04050 हे. में से 2030 वर्गमीटर रकवा मौजा समान पटवारी हल्का समान तहसील हूजूर में विश्वनाथ सिंह पिता रामजी सिंह निवासी वार्ड क्रमांक 25 समान रीवा को मंजूरी दी गई है। जहां एक ओर इस भूमि का प्रकरण हाई कोर्ट में होने की जानकारी छुपाए जाने की बात सामने आई है। वहीं इस मंजूरी के संबंध में लगाए दस्तावेजों में कमी बताई जा रही है, नगर निगम में हो रही चर्चा के अनुसार अनुज्ञा के लिए जो एक शपथ पत्र दिया गया है उसमें आवेदक के हस्ताक्षर तक नहीं हैं। न ही शपथ पत्र में गवाह के हस्ताक्षर हैं, यह शपथ पत्र दिनांक 28 नवंबर 2025 की तारीख का बना है। आनन-फानन में अधिकारी ने हितग्राही को लाभांवित करने अनुज्ञा दे डाली।

बाणसागर तलैया में कब्जे की मंशा

बता दें कि बाणसागर तालाब में पिछले लंबे समय से लगातार निर्माण कार्य किए जा कर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, इसके ऊपरी सहित निचले हिस्से में अवैध कब्जा है लेकिन इस ओर फिलहाल निगम प्रशासन का ध्यान नहीं है। मोटी कमाई अवैध कब्जा कर की जा रही है, कइयों द्वारा दुकानें बनाकर किराए पर दे दी गई हैं, झोपड़ी का किराया पांच हजार तक वसूला जा रहा है।

सड़क हादसे में दो मौसेरी बहनों की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदली

जागरण, रीवा। जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो मौसेरी बहनों की मौत हो गई। दोनों सतना जिले की रहने वाली थीं और एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने कुल्लू गांव गई थीं। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं। अस्पताल चौकी पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान प्रीतू साकेत पति अरुणेश (25) निवासी करही कला थाना कोटर एवं प्रिया साकेत पिता रामबली (15) निवासी बकिया थाना रामपुर बघेलान के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि दोनों रिश्ते में मौसेरी बहनें थीं। बताया गया कि मंगलवार को दोनों शादी समारोह में शामिल होने कुल्लू गांव गई थीं, जहां सड़क हादसे का शिकार हो गईं। गंभीर हालत में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। बुधवार सुबह दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की डायरी संबंधित थाने को भेजने की बात कही है।

नरवाई की आग से गृहस्थी जलकर खाक

- बेटियों के विवाह की तैयारी में लगा था परिवार
- सेमरिया थाना क्षेत्र के बवैया गांव की घटना

रीवा। सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बवैया में खेत में नरवाई की आग ने एक परिवार की गृहस्थी का उजाड़ दिया। बेटियों की शादी के लिए जुटाई गई सामग्री आग में स्वाहा हो गई। बताया गया कि खेत से आग की लपटें घर तक पहुंची और इसके बाद घर सहित गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया और एक परिवार सड़क पर आ गया। घटना के संबंध में पीड़ित अशोक तिवारी निवासी ग्राम बवैया थाना सेमरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पूर्व उनके घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर किसी ने खेत में नरवाई जलाने के लिए आग लगाई थी। लेकिन भीषण गर्मी और तेज हवाओं के चलते आग की लपटें धीरे-धीरे उनके घर के पीछे तक पहुंच गईं। जब तक वह आग पर काबू पाते तब तक आग की लपटों ने उनके घर को चपेट में ले लिया और देखते ही देखते उनका घर सहित गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने बताया कि दोपहर 12 बजे लगी आग की सूचना पुलिस सहित प्रशासनिक अमले और दमकल की टीम को दी गई लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी ही व्यवस्थाओं से शाम तकरीबन 5 बजे तक आग पर काबू पाया लेकिन उससे पहले गृहस्थी का सारा सामान सहित मकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया था। पीड़ित परिवार द्वारा शासन से मुआवजे की मांग की गई है और आम जनता से भी आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। बताया गया है कि परिवार में तीन बेटियां हैं और एक बेटा है जिनकी शादी करनी थी, जिनकी तैयारी में परिवार लगा था लेकिन आगजनी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया।

ई-केवाईसी नहीं कराने पर बंद हो जाएगी ग्राहक को मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी

फर्जी कनेक्शनों को खत्म करने आधार कार्ड के जरिए करनी होगी पहचान की पुष्टि

जागरण, रीवा। एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए सरकार द्वारा ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिये जाने के बाद भी बड़ी संख्या में अभी भी कनेक्शनधारियों ने ई-केवाईसी के प्रत लापरवाही बरत रहे हैं। बार-बार चेतावनी के बाद भी ई-केवाईसी नहीं कराने वालों की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य एलपीजी सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना और फर्जी कनेक्शनों को खत्म करना है। एलपीजी ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत ग्राहकों को अपने आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान की पुष्टि करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को ही एलपीजी सिलेंडर मिल रही है और सब्सिडी का सही तरीके से उपयोग हो रहा है। एलपीजी ई-केवाईसी की शुरुआत के साथ सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और रसोई गैस वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना है। एलपीजी गैस ई-केवाईसी एक इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी प्रक्रिया है, जिसके तहत ग्राहकों को अपने आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करनी होती है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन या गैस वितरक एजेंसी के कार्यालय में जाकर पूरी की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी कनेक्शनों को खत्म करना और एलपीजी सब्सिडी का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना है। एलपीजी ई-केवाईसी को अनिवार्य बनाने के लिए मुख्य उद्देश्य फर्जी कनेक्शनों की पहचान, आधार कार्ड के माध्यम से ग्राहकों की पहचान सत्यापित करके फर्जी कनेक्शनों को पूरी तरह से खत्म करना है। सरकार का प्रयास है कि सब्सिडी का सही वितरण केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही सब्सिडी मिलनी चाहिए, जिससे सरकार के वित्त की बचत होगी। सरकार ने अभी तक अंतिम तिथि घोषित नहीं की है। अगर कोई ग्राहक केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसकी गैस सिलेंडर आपूर्ति बंद हो सकती है और उसे सब्सिडी भी नहीं मिलेगी।

ई-केवाईसी का उद्देश्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना

एक ही परिवार में एक से अधिक कनेक्शन होने के कारण सरकार को वित्तीय क्षति उठानी पड़ रही है। वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए एलपीजी ई-केवाईसी 2024 को अनिवार्य इसलिए बनाया गया है क्योंकि भारी मात्रा में फर्जी कनेक्शन पाए गए हैं, जिससे सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। कई लोग एक से अधिक कनेक्शन लेकर घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे थे, जिससे सब्सिडी का दुरुपयोग हो रहा था। आधार आधारित ई-केवाईसी से इन समस्याओं को रोका जा सकता है।

कैसे करें एलपीजी गैस ई-केवाईसी :
ऑनलाइन केवाईसी करने की प्रक्रिया को पूरा करने के तीन तरीके हैं जिसके माध्यम से इसे तीन चरणों में पूरा किया जा सकता है। एलपीजी के ग्राहक अपने गैस प्रदाता एजेंसी इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं। अपना एलपीजी उपभोक्ता नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी द्वारा अपनी जानकारी सत्यापित करें। सफल सत्यापन के बाद आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।

तेज रफ्तार बल्कर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

जागरण, रीवा। तेज रफ्तार बल्कर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना बीती रात गुढ़ थाना क्षेत्र के चौड़ियार के पास हुई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया इसके चलते करीब तीन घण्टे आवागमन बाधित रहा। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक महासांव के चौड़ियार मोड़ पर बीती देर रात तकरीबन 3 बजे हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद गुढ़ पुलिस ने मृतक के शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। बताया गया कि बाइक सवार मनोज कोल अपने साले की बारात पड़ोस में ही आई थी। बताया गया है की बारात में शामिल होने के बाद रात्रि तकरीबन 3 बजे वह अपने दो अन्य साथियों के साथ बाइक से सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बल्कर ट्रक ने मनोज को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बल्कर सहित चालक मौके से फरार हो गया। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने रीवा-सीधी मार्ग पर चकाजाम कर दिया। हालांकि गुढ़ पुलिस ने परिजनों को समझाइस देकर जाम खुलवाया। पुलिस मर्ग कायम कर अज्ञात बल्कर सहित चालक की तलाश में लगी हुई है।

सोसायटी से गेहूं तौलाकर लौट रहे किसान से मारपीट कर लूट

फाइल फोटो

जागरण, रीवा। गढ़ थाना क्षेत्र के सिरैया निवासी किसान दिवाकर सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह 34 वर्ष के साथ मारपीट और लूट की घटना सामने आई। 24 अप्रैल की शाम करीब सात बजे वो गढ़ सोसायटी में गेहूं की तौल कराकर अपना ट्रैक्टर लेकर वापस अपने घर सिरैया लौट रहे थे, जैसे ही वो ट्रैक्टर लेकर मंडी मोड़ के पास पहुंचे छोटू साकेत पिता शिवकुमार साकेत सहित दर्जनभर युवकों ने उन्हें घेर लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर सोने की चेन लूट ली। पीड़ित के अनुसार बीते 24 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे मंडी में गेहूं की तौल चल रही थी। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ मजदूरों ने बचे हुए करीब 5 किलो गेहूं मुफ्त में देने की मांग की। मना करने पर विवाद शुरू हो गया। पीड़ित का आरोप है कि मंडी से बाहर निकलने के बाद आरोपियों ने ट्रैक्टर के सामने वाहन लगाकर रास्ता रोक लिया। इसके बाद छोटू साकेत पिता शिवकुमार साकेत निवासी लौरी नंबर 3 सहित 10 से अधिक लोगों ने ट्रैक्टर पर चढ़कर हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने पत्थर, डंडे और बेल्ट से मारपीट की, जिससे गले सहित शरीर में गंभीर चोटें आईं। पीड़ित ने बताया कि घटना के दौरान उसके गले में पहनी करीब 2 तोले की सोने की चेन और 12 हजार रुपये नकद भी छीन लिए गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। घटना की शिकायत पीड़ित ने गढ़ पुलिस से की है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत के बाद अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की वहीं शिकायत वापस लेने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं।

भावपूर्ण संवाद और अभिनय ने दर्शकों का जीता दिल

रीवा। सूत्रधार इंदौर के आमन्त्रण पर शस्त्र के जाल सभागार में दिल्ली और रीवा की प्रासंगिक संस्था द्वारा आलोक शुक्ला द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक उसके साथ को प्रस्तुत किया गया। क़रीब एक घंटे का ये नाटक एक सत्य घटना पर आधारित था। नाटक में 1997 की एक घटना को आधार बनाया गया, जिसमें एक मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को दिखाया गया। समाज में बढ़ती ऐसी घटनाओं को लेकर कलाकारों ने दर्शकों को झकझोरने का प्रयास किया। नाटक में यह भी दिखाया गया कि किस तरह महिला, बच्ची और युवती सुरक्षित नहीं हैं। जब वह घर से बाहर निकलती हैं, तो हर कदम पर उन्हें डर का सामना करना पड़ता है। धर्म, संस्कृति और समाज के नाम पर हो रहे पाखंड को भी उजागर किया गया। नाट्य प्रस्तुति में मुख्य भूमिका निभा रहीं कविता और उनका साथ दे रहे टेकचन्द, विजय लक्ष्मी, प्रताप सिंह, विनय शर्मा और आलोक शुक्ला के भावपूर्ण संवादों और अभिनय ने दर्शकों के दिल को छू लिया।

कुएं में गिरी गौवंश को रेस्क्यू कर पुलिस ने बचाया

जागरण, रीवा। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में कुएं में गिरी गाय को बचाने बीती रात पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 28-29 अप्रैल की दरमियानी रात पुलिस ने बेजुबान जानवर को बचाकर पुलिस ने अपनी कर्तव्यपरायणता की मिसाल दी। बताया गया कि एक गाय अचानक गहरे कुएं में गिर गई। सूचना मिलते ही नईगढ़ी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। चारों तरफ घुप्प अंधेरा, गहराई का अंदाजा नहीं और संसाधन बेहद सीमित, सबसे बड़ी बात, कुएं में उतरने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। तभी थाना प्रभारी नईगढ़ी ऋषि द्विवेदी ने बिना एक पल गंवाए खुद कुएं में उतरने का फैसला लिया, यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाकर इंसानियत निभाने का जज्बा था। उनकी अगुवाई में पुलिस टीम और ग्रामीणों ने मिलकर घंटों तक संघर्ष किया। आखिरकार करीब रात 2 बजे कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। यह घटना सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, बल्कि उस जज्बे की मिसाल है, जो पुलिस को आम लोगों से अलग बनाता है। नईगढ़ी पुलिस ने दिखा दिया कि वर्दी सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि संवेदनाओं और जिम्मेदारी की भी पहचान है। इस साहसिक कार्य की सराहना करते हुए मऊगंज पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने थाना प्रभारी ऋषि द्विवेदी और उनकी टीम की खुलकर प्रशंसा की।

NIFTEM KUNDLI
National Institute of Food Technology Entrepreneurship & Management, Kundli
www.niftem.ac.in
MOFPI
ADMISSIONS OPEN 2026-27
An Institute of National Importance
where Students Innovate, Create and Elevate
WHY CHOOSE NIFTEM-K ?
Strong Industry Collaborations | State-of-the-art Labs & Pilot Plants | Excellent Placements | National & International Collaborations
Focus on Entrepreneurship & Startups
PROGRAMS OFFERED
UNDERGRADUATE
BTech (FTM) BBA (Hons)
BTech (FT)+MBA
POSTGRADUATE
MTech MSc MBA
Exec. MBA For Working Professionals
RESEARCH
PhD For Students & Working Professionals
BE A PART OF INDIA'S FOOD INNOVATION REVOLUTION!
Build a rewarding career that feeds the nation and the world.
DOWNLOAD PROSPECTUS 2026-27
Scan the QR code or visit our website
Plot No. 97, Kundli, Sonepat, Haryana -131018
0130-2281101 admission@niftem.ac.in
JOIN NIFTEM-K - WHERE KNOWLEDGE DRIVES INNOVATION AND OUTREACH CREATES IMPACT

संस्थापक ▸ गुरुदेव गुप्त

संपादकीय

ड्यूटी या कर्मचारियों की जान का जोखिम?

पूरे भारत में लू से होने वाली मौतों और काम के बोझ से जुड़े तनाव की घटनाओं के सामने आने के बीच, जनगणना और चुनावी ड्यूटी के दौरान शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया हो, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव हों या फिर जनगणना जैसे विशेष अभियान, इनका जिम्मा शिक्षकों तथा अन्य विभागीय कर्मियों पर थोप दिया जाता है। उन्हें बिना किसी त्रुटि या हड़बड़ी के पूरी सटीकता के साथ इस कार्य को अंजाम देना होता है। मगर इस दौरान उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर शायद ही सरकार और प्रशासनिक स्तर पर पहले कोई चर्चा होती हो या कोई समाधान तलाशने की कोशिश की जाती हो। यानी स्थिति-परिस्थिति चाहे जो भी हो, इन कर्मियों को हर हाल में काम पूरा करना होता है।

ऐसे में कई बार काम का बोझ या चुनौतीपूर्ण हालात न केवल शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों को बढ़ा देते हैं, बल्कि संबंधित कर्मी की जान तक चली जाती है। ओडिशा में ऐसे ही दो स्कूली शिक्षकों की लू लगने से मौत हो गई, जिन्हें जनगणना के कार्य में नियुक्त किया गया था। खबरों के मुताबिक, अलग-अलग घटनाओं में जब ये शिक्षक घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के बाद स्कूल लौटे, तो बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

गौरतलब है कि पिछले दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में तैनात कई खंड स्तरीय अधिकारियों की मृत्यु हो जाने की खबरें आई थीं। पीड़ित पक्षों का दावा था कि काम का अत्यधिक बोझ और मानसिक परेशानी मौत का कारण बना, हालांकि अधिकांश मामलों में आधिकारिक स्तर पर व्यक्तिगत समस्या का ही हवाला दिया गया। चुनाव के दौरान भी इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। अब देश में जनगणना का कार्य शुरू हुआ है और अभी से ऐसी घटनाएं सामने आने लगी हैं। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी और हीट वेव के बीच जनगणना ड्यूटी को लेकर शिक्षकों में असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। वहीं, 1 मई से शुरू होने वाले जनगणना के पहले चरण को लेकर शिक्षक इसे स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा बता रहे हैं। राज्य में जनगणना का पहला चरण 1 मई से 30 मई तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के तहत हर घर, परिवार और उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत डेटा जुटाया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों सहित कर्मचारियों को डोर टू डोर जाकर जानकारी जुटानी होगी। जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। जाहिर है ऐसे हालात में घर-घर जाकर सर्वे करना बेहद कठिन और खतरनाक है। शिक्षक संगठनों की इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए कि इस कार्य को मई की बजाय जून से शुरू किया जाए।

दरअसल इसके पीछे स्कूलों के ग्रीष्म अवकाश का मामला भी सर उठा रहा है। मई-जून प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी वाले महीने होते हैं और इसी दौरान स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश भी रहता है। ऐसे में छुट्टियों के बीच फील्ड ड्यूटी देना अनुचित है। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार अवकाश का इस्तेमाल कर उनसे जबरन काम करा रही है। शिक्षकों की ओर से लंबे समय से यह मांग की जाती रही है कि उनकी जिम्मेदारी को शिक्षण कार्य तक ही सीमित रखा जाए, क्योंकि इससे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। सवाल है कि इस तरह के विशेष सरकारी अभियानों में तैनात किए जाने वाले कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? शासन-प्रशासन को इस बात पर गंभीरता से ध्यान देना होगा कि ऐसे कर्मियों को पेश आने वाली परेशानियों का तत्काल निराकरण किया जाए, ताकि उनकी जान को किसी तरह का खतरा न हो।

प्रसंगवश

हास्य-व्यंग्य पर बंदिश अभिव्यक्ति पर शिकंजा

आज सूचना क्रांति और सोशल मीडिया के दौर में पूरी दुनिया में गहरे तंज करती डिजिटल सामग्री का उफान है। जो दुनिया की भौगोलिक सीमाओं और सत्ता के शिकंजे से मुक्त होकर स्वतंत्र प्रवाह लिए हुए है। लेकिन इसके बावजूद देश में स्टैंडिंग कॉमेडियनों और व्यंग्यकारों के लिए राजनेताओं पर व्यंग्य करना तलवार की धार पर चलने जैसा बना हुआ है।

'नाक पर मक्खी न बैठने देने' वाले सत्तारूढ़ राजनेता कॉमेडियनों पर शिकंजा कसने को तैयार बैठे होते हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद के कॉमेडियन शरत उदय के बेंगलुरु स्थित स्टैंड-अप शो में शनिवार को तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के समर्थकों के एक समूह ने मंच पर आकर जो उत्पात मचाया, निस्संदेह वह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। टीडीपी के समर्थकों ने मंच पर आकर उन्हें तेलुगु देशम पार्टी के नारे लगाने को बाध्य किया। इस हुड़दंग से यह कार्यक्रम बाधित हो गया। इसके चलते न केवल उदय को अपना कार्यक्रम रोकना पड़ा, बल्कि एक बार फिर माफी मांगनी पड़ी। दरअसल, दो साल पहले उदय के व्यंग्यात्मक चुटकुलों के जरिये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे राज्य मंत्री नारा लोकेश को लक्षित किया गया था। निस्संदेह,यह अभिव्यक्ति व रचनात्मकता पर अंकुश लगाने का कुत्सित प्रयास ही कहा जाएगा। सही मायनों में यह घटनाक्रम हास्य-व्यंग्यपूर्ण असहमति के प्रति बढ़ती असहनशीलता का एक और उदाहरण है। गाहे-बगाहे विभिन्न राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी अलोकतांत्रिक प्रतिक्रियाएं सामने आती ही रहती हैं। जबकि हकीकत यह है कि हास्य का संसार बड़े लोगों की सहिष्णुता व उदारता से ही फलता -फूलता है। खासकर उस भारतीय समाज में जहां अकसर कबीरदास की यह उक्ति दोहरायी जाती है - 'निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाय। बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।' उनका कहना था कि आलोचक हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को शुद्ध और निर्मल बना देते हैं। सही मायनों में व्यंग्य व हास्य इंसान की सहज अभिव्यक्ति के तौर पर लिया जाना चाहिए।

निश्चित रूप से यदि हमारे राजनेता व बड़े लोग व्यंग्य या आलोचना को सहजता से लेते हैं तो इससे समाज में हास्य-विनोद भरपूर फलता-फूलता है। विशेष रूप से राजनीतिक व्यंग्य भारत में लंबे समय तक सत्ता को आईना दिखाता रहा है। पंडित नेहरु जैसे नेता कार्टूनिस्टों की तल्ख अभिव्यक्ति को सहजता से लेते थे और व्यंग्यकारों का सम्मान करते थे। धीर-गंभीर राजनेता आलोचना को जनता की नसीहत मानते रहे हैं। कालांतर राजनेताओं की इस सोच में पराभव देखा गया है। विडंबना ही है कि वर्ष 2024 में नायडू व लोकेश पर किए गए व्यंग्य के लिये उदय को फिर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को मजबूर किया गया। यह अशोभनीय प्रयास यही दर्शाता है कि वर्ग विशेष में असहमति को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उदय प्रकरण भी इसी दुखद स्थिति के सिलसिले का हिस्सा है। हाल ही में कॉमेडियन अनुदीप कटिकाला और रफीक मोहम्मद को आंध्र प्रदेश पुलिस ने उन वीडियो के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण पर व्यंग्य किया था। बीते साल मार्च में, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के एक होटल में तब तोड़फोड़ की थी, जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पक्षद्रोही कहा था।

निर्विवाद रूप से यदि व्यंग्य-विनोद पर पाबंदी लगायी जाती है और कलाकारों की अभिव्यक्ति को बाधित किया जाता है तो इसका प्रभाव सिर्फ एक शो को ही बाधित नहीं करता बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत पर ही चोट करता है। सही मायनों में यह दिक्कत कॉमेडी करने वालों से नहीं है, बल्कि राजनेताओं के असुरक्षाबोध में है, जो उन पर लोगों का हंसना बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे में राजनेताओं का नैतिक दायित्व है कि वे लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मर्म को समझें। इसके लिये वे अपने अति-उत्साही समर्थकों पर लगाम लगाएं। लेकिन विडंबना यह भी है कि पुलिस भी सत्ता की राजनीति के आगे नतमस्तक नजर आती है। कायदे से उसे संविधान में वर्णित अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करनी चाहिए। यदि पुलिस दायित्वों का ईमानदारी से पालन करती तो उदय जैसे कलाकारों को माफी न मांगनी पड़ती।

जलवायु परिवर्तन

देश में बढ़ती तपिश को अल नीनो के रुख ने और घातक बना दिया

खेती-किसानी में बढ़ सकती हैं मुश्किलें

पंकज चतुर्वेदी

भोपाल- 43 डिग्री, खजुराहो- 45 डिग्री, भटिंडा- 43 डिग्री, कानपुर- 45 डिग्री, दिल्ली एनसीआर- 43 डिग्री! अप्रैल के चौथे सप्ताह में मौसम का यह मिजाज देख कर डर लगता है कि आने वाले दो महीने न जाने सूरज कैसी और कितनी आग बरसायेगा। भारत में बढ़ती तपिश और उससे भी जानलेवा होती लू के पीछे छिपे जलवायु परिवर्तन के गहरे संकट को अल नीनो के रुख ने और घातक बना दिया है। मौसम विज्ञान के नवीनतम आंकड़े भविष्य की जिस भयावहता को रेखांकित कर रहे हैं, उसकी बानगी अप्रैल के दूसरे सप्ताह से देखने को मिल गयी। दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में भारतीय शहरों का दबदबा एक गंभीर पर्यावरणीय चेतावनी है। यह महज एक मौसमी बदलाव नहीं, बल्कि वायुमंडल में बनते 'हीट डोम' और कंकरीट के फैलते जंगलों का नतीजा है, जिसने शहरों को 'अर्बन हीट आइलैंड' में बदल दिया है।

स्काइमेट वेदर की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट इस स्थिति को और अधिक चिंताजनक बनाती है, जिसके अनुसार इस वर्ष भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान है। यह भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक संकेत है। अल नीनो, जो वर्तमान में फिलहाल अपनी प्रारंभिक अवस्था में दिखाई दे रहा है, मॉनसून के शुरुआती दौर में विकसित होकर अगस्त और सितंबर के दौरान और मजबूत होगा। हालांकि, जून में मॉनसून की शुरुआत 101 प्रतिशत दीर्घावधि औसत (एलपीए) के साथ सामान्य रह सकती है, पर जुलाई (95 प्रतिशत) से स्थिति बिगड़नी शुरू होगी। इसका सर्वाधिक खतरा मध्य भारत के वर्षा आधारित क्षेत्रों और उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर मंडरा रहा है।

इस वर्ष मॉनसून पर अल नीनो का साया मंडराता दिख रहा है, जिसके चलते कुल वर्षा लंबी अवधि के औसत, यानी एलपीए का केवल 94 प्रतिशत रहने का अनुमान है। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति तेजी से विकसित हो रही है और इसके मई से जुलाई के बीच सक्रिय होने की प्रबल आशंका है, जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय मॉनसून को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। हालांकि, मॉनसून की शुरुआत जून के महीने में सामान्य रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, अल नीनो का प्रभाव गहराता जायेगा। विशेष रूप से अगस्त और सितंबर के महीनों में वर्षा के स्तर में भारी गिरावट आने की आशंका है, जो रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए संकट पैदा कर सकता है।

नीति आयोग के मुताबिक देश के कुल फसल रकबे का केवल 55 फीसदी सिंचित है और 45 प्रतिशत खेती मॉनसून पर निर्भर है। सीडब्ल्यूएमआई के अनुसार, लगभग 74 प्रतिशत गेहूं और 65 प्रतिशत चावल की खेती वाले क्षेत्र पहले से ही भारी जल-संकट का सामना कर रहे हैं। व्यावसायिक फसलों और औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ते रुझान से भारत में मॉनसून की वर्षा पर निर्भरता बढ़ी है। अब अल-नीनो के खतरे और कमजोर मॉनसून की आशंका से जलाशय के सूखने और खेती के लिए पानी की कमी की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय जल आयोग देश में कुल 183.565 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) क्षमता वाले 166 प्रमुख जलाशयों के भंडारण पर नजर रखता है। इस समय इन जलाशयों में कुल क्षमता का 44.71 प्रतिशत है। हाल में इसमें तेजी से कमी आई है।पिछले आंकड़े बताते हैं कि सामान्य से कम मॉनसून वाले वर्षों में जब बारिश का समय, वितरण और फैलाव लगभग समान रहा तब खरीफ के उत्पादन में अधिक कमी नहीं हुई किन्तु गैर-सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली दलहन-तिलहन फसलों के लिए जोखिम हो सकती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी की इस बढ़ती आवृत्ति का सीधा संबंध वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि से है। वर्ष 1981 से 2020 के बीच भारत का औसत तापमान लगभग एक डिग्री बढ़ चुका है। भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है। तभी पहले जिस लू का प्रभाव केवल गंगा के मैदानी इलाकों तक सीमित था, अब उसका दायरा बढ़कर 18.11 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया है।

शहर, यानी आलीशान भवन और कंकरीट व डामर की सड़कें, ये प्राकृतिक मिट्टी की तुलना में कई गुना अधिक गर्मी अवशोषित करती हैं। रात के समय जब ग्रामीण क्षेत्र ठंडे होने लगते हैं, तब शहरों की ये इमारतें अपनी जमा की हुई गर्मी छोड़ती हैं। इसे 'अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट' कहा जाता है, जिससे शहरों का तापमान आसपास के गांवों से पांच से सात डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना रहता है। यहां अल नीनो और ला नीना के बारे में भी समझना होगा कि ये हैं क्या? अल नीनो मध्य और पूर्व-मध्य भूमध्यरेखीय समुद्री सतह के तापमान में नियमित अंतराल के बाद होने वाली वृद्धि है, जबकि ला नीना इसके विपरीत तापमान कम होने की मौसमी घटना है। दक्षिणी अमेरिका से भारत तक के मौसम में बदलाव के सबसे बड़े कारण अल नीनो और ला नीना प्रभाव ही होते हैं। अल नीनो का संबंध भारत व ऑस्ट्रेलिया में गर्मी व सूखे से है, वहीं ला नीना अच्छे मॉनसून का वाहक है। इसे भारत के लिए वरदान कहा जा सकता है। भले भारत में इसका असर हो, पर अल नीनो और ला नीना घटनाएं पेरू के तट (पूर्वी प्रशांत) और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट (पश्चिमी प्रशांत) पर घटित होती हैं। हवा की गति इन प्रभावों को दूर तक ले जाती है।

सामान्य परिस्थिति में भूमध्यरेखीय हवाएं पूर्व से पश्चिम (पछुआ) की ओर बहती हैं और गर्म हो चुके समुद्री जल को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी समुद्री तट की ओर बहा ले जाती हैं। गर्म पानी से भाप बनता है और उससे बादल बनते हैं। परिणामस्वरूप, पूर्वी तट के आसपास अच्छी बरसात होती है। वहीं अल नीनो परिस्थिति में पछुआ हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं व समुद्र का गर्म पानी लौटकर पेरू के तटों पर एकत्र हो जाता है। इस तरह समुद्र का जल स्तर 90 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वाष्पीकरण होता है व इससे बरसात वाले बादल निर्मित होते हैं। इससे पेरू में तो भारी बरसात होती है, लेकिन मॉनसूनी हवाओं पर इसके विपरीत प्रभाव के चलते ऑस्ट्रेलिया से भारत तक सूखा हो जाता है। इस अंधकारमय परिदृश्य के बीच एकमात्र उम्मीद 'इंडियन ओशन डिपोल' (आइओडी) से है। विशेषज्ञों का मानना है कि मॉनसून के अंत तक एक 'पॉजिटिव आइओडी' विकसित हो सकता है, जो अल नीनो के नकारात्मक प्रभावों को कुछ हद तक कम करने में सहायक हो सकता है।

खुला मंच

सुर्खियों की सरताज झालमुड़ी और मतमूढ़ि

अशोक गौतम

बंधुओ! बाजारी जीव होने के चलते इन दिनों मैं बाजार-बाजार मीडिया चर्चित झालमुड़ी को वैसे ही ढूंढ़ रहा हूं जैसे कस्तूरी मृग वन-वन भटकता कस्तूरी ढूंढ़ता रहता है, पर एक झालमुड़ी है कि न वह मुझे बाजार में कहीं मिल रही है, न उसको बनाने वाला मसाला। दोनों बाजार से पता नहीं कहां गायब हो गए हैं? मसाले के बिना कुछ भी स्वाद नहीं बनता। न चाय, न चुनाव! दोनों को मसाला ही जायकेदार बनाता है।

जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ! आखिर बड़ी दौड़धूप के बाद झालमुड़ी मृग को झालमुड़ीश्री मिल ही गई। वाह! क्या इतराती हुई! क्या बलखाती हुई! उसके अंग-अंग से ललचाता स्वाद टपक रहा था। हिंदी सिनेमा की किसी हिट नायिका की तरह। जिस तरह सिने जगत में किसी को भी हिट होते देर नहीं लगती उसी तरह चुनावी दिनों में किसी भी चीज को हिट होते देर नहीं लगती।

वो मेरे सामने तो मैं उसके सामने! मतलब हम दोनों एक-दूसरे के सामने। तब उसे देख मत पूछो मेरे क्या हाल! आखिर बड़ी देर तक मैं घबराता, शरमाता उसे एकटक निहारता रहा तो उसने मुझसे पूछा, 'वोटर लाल! क्या चाहिए?' मैं चुप! अब गूंगा गुड़ उच्चारे तो कैसे उच्चारे? बहुत देर बाद, बहुत कोशिश के बाद मेरे उसके बंधे होंठ खुले तो सबसे पहले उसे नमन किया। 'हे झालमुड़ी! तुम धन्य हो गई। तुम्हारे दर्शन पा मैं भव बाजार पार हो गया।'

'जल्दी बोलो! देखो, मेरे पास टाइम नहीं। मीडिया वाले मेरे पीछे पड़े हैं। क्या चाहते हो?'

'झालमुड़ी,' कह मैं उसका एकटक दमकता चेहरा निहारने लगा।

'कौन-सी? पेट भरने वाली या चुनाव जीतने वाली?' उसने मीडिया वालों की तरह मुझसे प्रश्न किया तो मैं सन्नाटे में रह गया। फिर किसी कुशल अदाकारा की तरह नैन मटकाते बोली, 'देखो वोटर लाल! हर चीज दो तरह की होती है। एक दिखाने वाली, दूसरे खाने वाली। तुम्हें कौन-सी चाहिए?'

'वोटर को कहां चुनाव सों काम! मैं तो पेट भरने वाली चीजों पर ही विश्वास करता हूं! जो जनता का पेट भर दे उसके लिए तो वही अमृत।' मैंने कड़वा सच कहा तो उसे पता नहीं क्यों मेरे देशभक्ति के पसीने से देशद्रोह की बू आई और मेरी तरफ से यों मुंह फेर लिया जैसे किसी की बड़े समय तक प्रेमिका रही किसी और से विवाह हो जाने के बाद सरे बाजार उससे मुंह फेर लेती है।

खाद्य सुरक्षा

उत्पादों पर लगे लेबल से यह पता चल सकेगा कि खाने-पीने का सामान पौष्टिक है या नहीं

भारत में क्यों नहीं की जाती जंक फूड की स्टार रेटिंग ?

संकेत उपाध्याय

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है, जो कुछ पैमानों पर एक मानक प्रस्तुत करेगा कि उत्पाद शरीर के लिए कितना सही है और कितना नहीं। हम सब लोगों की आदत में अब एक चीज शामिल हो चुकी है। कोई भी बिजली का उपकरण खरीदते वक्त दुकानदार हमेशा उसकी पांच सितारा रेटिंग बताता है कि वह उपकरण कितनी बिजली इस्तेमाल करेगा। हम ऐसे उपकरण खरीदने में रुचि दिखाते हैं, ताकि बिजली का बिल कम आए। लेकिन यही सोच हम अपने शरीर और खाने-पीने पर क्यों नहीं अपनाते?

सोचिए, अगली बार जब आप दुकान पर जाएं, या ब्लिंकिट अथवा जेप्टो से ऑनलाइन कुछ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि मंगवाएं, और उन्हें खरीदने से पहले उनकी पांच सितारा रेटिंग देखें! तो, क्या यह अद्भुत बात नहीं होगी! बेशक यह सिगरेट की वैधानिक चेतावनी जैसा तो नहीं है, लेकिन यह आपको कुछ पैमानों पर एक मानक प्रस्तुत करेगा कि उत्पाद शरीर के लिए कितना सही है और कितना नहीं। कहीं इसमें चीनी या नमक की मात्रा बहुत ज्यादा तो नहीं? और क्या उत्पाद में मैदा या अल्ट्रा प्रोसेस्ड केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है या नहीं? असल में, एक ऐसा ही प्रस्ताव भारत सरकार की एक एजेंसी लाना चाह रही है। लेकिन बड़ी-बड़ी कंपनियां नहीं चाहतीं कि उनकी असलियत आप तक पहुंचे।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), जो खाने-पीने के उत्पादों को सर्टिफिकेट देती है, एक प्रस्ताव लेकर आया है कि हर जंक फूड के आगे एक पांच सितारा लेबल लगे। इसको 'फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रीशन लेबलिंग' (एफओपीएनएल) कहा गया है। अब तक खाने-पीने का सामान पौष्टिक है या नहीं, वह हमेशा एक सारणी के माध्यम से पैकेट के पीछे छपा रहता है, जिसे कोई पढ़ता भी नहीं। इसी के चलते हेल्थ स्टार रेटिंग का यह एक नया फॉर्मूला लाया गया है।

एफओपीएनएल एक चेतावनी लेबल होगा। यदि उत्पाद में नमक या चीनी की मात्रा तय मानक से अधिक है, तो यह लेबल लाल रंग का होगा। इसके अलावा, एक न्यूट्री-स्कोर भी प्रस्तावित है। मसलन, गहरे हरे-सबसे स्वस्थ, हरे-स्वस्थ, पीले-मध्यम, नारंगी-मध्यम से थोड़ा ज्यादा हानिकारक, गहरे नारंगी-अत्यधिक हानिकारक एवं सुर्ख लाल- बेहद खतरनाक। इसके अलावा, हेल्थ स्टार रेटिंग (एचएसआर) एक और प्रावधान है। यहां 0.5 से फाइव स्टार तक दिए जाएंगे। यानी, जितने ज्यादा स्टार होंगे, उतना स्वस्थ वह उत्पाद होगा।

यह सब इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत हर तरह के रोग की राजधानी बनता जा रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मधुमेह की समस्या वाला देश है। एक अनुमान के हिसाब से 11.4 फीसदी भारतीय मधुमेह से पीड़ित हैं, जो वैश्विक स्तर से ज्यादा है। इसके अलावा, मोटापा भी एक भयावह समस्या है। महिलाओं में यह समस्या 2005-06 में 12.6 फीसदी से बढ़कर 2019-21 में 24 फीसदी हो गई, जबकि पुरुषों में 9.3 फीसदी से बढ़कर 22.9 फीसदी। भारत में 2.7 करोड़ से अधिक बच्चे और किशोर मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं। दरअसल, इन सब के पीछे पैकेट बंद खाना और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। पैकेट बंद खाना जल्दी से भूख तो मिटा देता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम हमारी सेहत पर भी दिखाई देते हैं।

मोटापा कम करने की दवाई भी हिंदुस्तान में अब धड़ल्ले से बिक रही है। ओजेंपिक और मौंजारो के इंजेक्शन इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी हम मूल समस्या से भी जूझ रहे हैं और उसके इलाज व दवाई का बोझ भी झेल रहे हैं। यह अच्छी आदत नहीं है। ऐसे में, रेटिंग और लेबल लगाना अच्छा कदम है। लेकिन उद्योग जगत इस कदम के खिलाफ है। उसका मानना है कि यह रेटिंग सिस्टम हिंदुस्तान के लिए नहीं बना है। उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित लेबलिंग प्रणाली फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, चिली, इस्राइल, मेक्सिको और पेरू जैसे देशों के मॉडल से प्रेरित है, जो भारत की विविध आहार आदतों और वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखती। उनका यह भी कहना है कि पश्चिमी देशों में लोग ज्यादा प्रोसेस्ड (तैयार पैकेट वाले) फूड खाते हैं। वहीं भारत में ऐसा कम होता है। यहां कुल कैलोरी का 12 फीसदी से भी कम हिस्सा ही प्रोसेस्ड और रेडी-टू-ईट फूड से आता है। बाकी लगभग 88 प्रतिशत खाना घर पर बना हुआ या पारंपरिक तरीके से बनाया गया पर बाहर का होता है। तर्क यह दिया जा रहा है कि तमाम हिंदुस्तानी आदतें, जैसे अचार, मिठाई व मक्खन कम मात्रा में खाया जाता है। अगर विदेशी नियम लगाए गए, तो इसके दुष्प्रभाव बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाएंगे, जबकि वास्तविक सेवन कम होगा। पर यह तर्क कोई भी डॉक्टर मानने को तैयार नहीं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और पोषण वैज्ञानिक कहते हैं कि एफओपीएनएल उपभोक्ताओं की मदद करेंगे। कई लोग पैकेट पर विस्तृत पोषण जानकारी पढ़ने में समय नहीं लगाते। ऐसे में, सरल चेतावनी लेबल तुरंत उन्हें सूचित कर सकते हैं। वे मानते हैं कि हमारी खान-पान की परंपराएं अलग होती हैं, लेकिन उनका कहना है कि ज्यादा चीनी नुकसान करती है। अगर लोग सिर्फ एक चम्मच चीनी भी कम कर दें, तो इससे बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन खाना जैसा भी हो, यदि वह हानिकारक है, तो चेतावनी क्यों न दी जाए? सुप्रीम कोर्ट सहित कई संस्थाएं इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रही हैं। कोर्ट यह तक कह चुका है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्योग के हितों से ऊपर है। एफएसएसएआई को बिना देरी के स्पष्ट, प्रभावी एफओपीएनएल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। अगर जरूरी हुआ, तो कोर्ट खुद भी हस्तक्षेप कर सकता है। फिर भी एफएसएसएआई 2022 से अब तक आगे नहीं बढ़ पाया, यह चिंताजनक है।

बहरहाल, ऐसे में, देश को और आप (उपभोक्ता) को तय करना है कि आप किसका साथ देना चाहेंगे। जंक फूड वाली कंपनी का या अपनी सेहत का, क्योंकि सेहत तभी फाइव स्टार होगी, जब आपका खाना पांच सितारा होगा। स्वस्थ भोजन सबका अधिकार होना चाहिए और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा उपभोक्ताओं की सुरक्षा तो है ही, यह देश के सामाजिक-आर्थिक हितों के लिए भी बेहद फायदेमंद है।

जीवन दर्शन

प्रेम का अर्थ विस्तार है न कि अधिकार...

प्रेम की खासियत यह है कि वह मनुष्य को पूर्ण नहीं करता, बल्कि उसे अपूर्णता का बोध कराता है। यही बोध उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति जितना देता है, उतना ही वह स्वयं को खोजता भी है।

प्रेम उस शाश्वत स्वरूप की तरह है, जो मानव हृदय की गहराई में उतरकर उसे नया जीवन देता है। इसलिए, प्रेम जब भी पुकारे, तो उसके पीछे हो लेना चाहिए, भले ही उसके मार्ग कठिन और दुर्गम क्यों न हों। प्रेम व्यक्ति को अपने अधिकार में नहीं लेता, बल्कि उसे मुक्त करता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव बंधन नहीं, विस्तार है। यह विस्तार ही जीवन का सच्चा सौंदर्य बनता है। इसलिए, प्रेम के पंख जब आलिंगन करें, तो स्वयं को उसे सौंप देना चाहिए। प्रेम रूपी साधना में सुख और पीड़ा, दोनों साथ चलते हैं, क्योंकि प्रेम केवल आनंद देने के लिए नहीं आता, बल्कि आत्मा को तराशने के लिए भी आता है। जिस प्रकार वृक्ष अपने बीज को मिट्टी में दबाकर ही अंकुरित होता है, ठीक उसी तरह मनुष्य को भी अपने अहंकार को छोड़कर ही प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझना पड़ता है। जब कोई प्रेम करता है, तब वह अपने भीतर की अनेक परतों को खोलता है और इसी से उसकी सच्ची पहचान जन्म लेती है। सच्चा प्रेम न तो किसी का स्वामित्व स्वीकार करता है और न ही स्वयं किसी का दास बनता है। वह दो आत्माओं के बीच एक ऐसा सेतु है, जहां दोनों अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए एक-दूसरे के साथ चलते हैं। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि दो लोग एक ही हो जाएं, बल्कि यह है कि वे अलग-अलग रहते हुए भी एक ही दिशा में आगे बढ़ें और एक-दूसरे के जीवन को समृद्ध करें। इस प्रकार प्रेम में दूरी भी आवश्यक है, क्योंकि यही दूरी निकटता को अर्थ देती है और यही संतुलन संबंधों को स्थायी बनाता है।

प्रेम अपूर्णता का बोध कराता है। क्योंकि प्रेम में व्यक्ति जितना देता है, उतना ही वह स्वयं को खोजता भी है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें पाने की इच्छा धीरे-धीरे देने के आनंद में बदल जाती है और यही परिवर्तन प्रेम को आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाता है। यह एक सतत प्रवाह है, जो बिना किसी अपेक्षा के बहता रहता है और इसी बहाव में जीवन का संगीत छिपा होता है। प्रेम का स्वभाव अनंत है और इसे किसी परिभाषा में नहीं समेटा जा सकता। इसलिए, जब कोई ?मनुष्य उसे समझने के बजाय नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तब वह उसके सार से दूर हो जाता है। प्रेम को महसूस करने के लिए खुला हृदय चाहिए।

दरअसल, प्रेम एक ऐसी अनुभूति है, जो मनुष्य को स्वयं से जोड़ती है और उसे यह समझने में मदद करती है कि वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक व्यापक चेतना का हिस्सा है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करता है, तब उसका प्रेम सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समस्त सृष्टि तक फैल जाता है और यही विस्तार जीवन का सर्वोच्च अनुभव बन जाता है। प्रेम को महसूस करने की कला सीखें। प्रेम हमें बांधता नहीं, बल्कि भीतर से विस्तृत करता है और हमें स्वयं से मिलाता है। जब हम अपेक्षाओं को छोड़कर देने का आनंद सीखते हैं, तभी प्रेम अपनी सच्ची शक्ति दिखाता है। **खलील जिब्रान**

गीता ज्ञान

श्लोक

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः!
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः !!

भावार्थ

दुनिया में कोई भी काम सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता बल्कि कठिन परिश्रम से पूरा होता है. कभी भी सोते हुए शेर के मुँह में हिरण खुद नहीं आता।

शाला जाने योग्य हर बच्चे का शाला में प्रवेश कराएं: मुख्य सचिव

स्वास्थ्य सेवाओं की कलेक्टर्स संवेदनशीलता से मॉनिटरिंग करें

मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को दिए निर्देश

जागरण, रीवा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कलेक्टर्स तत्परता से प्रयास करें। शाला जाने योग्य प्रत्येक बच्चे का शाला में प्रवेश सुनिश्चित करें। ऐप के माध्यम से प्रदेश में 6 साल की आयु पूरा करने वाले 10.45 लाख बच्चे चिन्हित किए गए हैं। इनका शाला में प्रवेश कराएं। आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा स्कूलों के कोलोकेशन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करें। आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के लिए जमीन बस्ती के आसपास चिन्हित करें। आवश्यक होने पर कलेक्टर मद परिवर्तन करके स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए जमीन उपलब्ध कराएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की कलेक्टर संवेदनशीलता से मॉनिटरिंग करें। माह में कम से कम दो बार समीक्षा बैठक आयोजित कर मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण की समीक्षा करें। गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, अति कुपोषित बच्चों के एनआरसी में भर्ती, सीवियर एनिमिक गर्भवती महिलाओं की उचित देखभाल तथा हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा की समीक्षा करें। कलेक्टर्स अस्पतालों तथा दवा स्टोर का निरीक्षण करें। विकासखण्ड स्तर तक बैठक आयोजित कर स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले को सचेत करें। सबके सहयोग से ही स्वास्थ्य सूचकांक बेहतर होंगे।

मुख्य सचिव ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत पाण्डुलिपियों का सर्वे करके उन्हें संरक्षित कराएं। सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। इसमें सौ दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करें। लोक सेवा गारंटी योजना में चिन्हित सेवाएं तय समय सीमा में दें। समय सीमा का पालन न करने वालों पर कार्यवाही करें। स्वामित्व योजना के प्रकरण केवल कुछ जिलों में ही शेष हैं। इनका 15 दिवस में निराकरण कराएं। सभी कलेक्टर्स स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों की समीक्षा करें। श्रम विभाग की संबल योजना तथा मानधन योजना के लिए पात्र श्रमिकों का पंजीयन कराएं।

सभी खरीदी केन्द्रों व्यवस्थाएं पुख्ता हों

मुख्य सचिव ने कहा कि गेहूं उपार्जन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश का कोटा बढ़ा दिया गया है। सभी खरीदी केन्द्रों में उपार्जन के लिए बारदाने, तौलकांटे तथा अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। अब किसान 23 मई तक उपार्जन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। प्रत्येक खरीदी केन्द्र में तैनात नोडल अधिकारी के माध्यम से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। वृंदावन ग्राम योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस कराएं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की सतत निगरानी करें। पूर्ण एकल नलजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कराकर इनका नियमित संचालन कराएं।

डॉ. अरुणा ने बढ़ाया एसएस मेडिकल कॉलेज का मान

रीवा। शासकीय श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के शरीर क्रिया विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अरुणा सिंह ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन MEDIC ALTRUISM – A Single Yes Countless Tomorrow में विशिष्ट सहभागिता करते हुए अपने संस्थान का गौरव बढ़ाया। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन लखीमपुर खीरी स्थित ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया। इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक मंच पर डॉ. अरुणा सिंह को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया, जहाँ उन्होंने अपने ज्ञान एवं अनुभव से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पैनलिस्ट के रूप में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा में सक्रिय सहभागिता निभाई। डॉ. सिंह की इस उपलब्धि ने न केवल उनके व्यक्तिगत शैक्षणिक कौशल को प्रदर्शित किया, बल्कि श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की शैक्षणिक प्रतिष्ठा को भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ किया है। महाविद्यालय परिवार एवं विभाग के समस्त सदस्यों ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए डॉ. अरुणा सिंह को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं।

120 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती

बैठक में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक एवं दुर्घटना रोकने के अलग-अलग प्रयासों के कारण प्रदेश में सड़क दुर्घटना एवं इससे होने वाली मौतों में कमी आई है। राहवीर योजना, प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना राहत योजना तथा ई डॉर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करें। नशामुक्त भारत अभियान के तहत लगातार कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। जनवरी से अप्रैल माह तक नशे के अवैध व्यापार के 818 प्रकरण दर्ज कर 120 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती की गई है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए एनकोर समिति की हर माह बैठक करें। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, जनमन योजना, निक्षय भारत अभियान, पंचायतों की आय के स्रोत बढ़ाने, वनाधिकार अधिनियम के तहत सामूहिक दावों के निराकरण, मिशन अंकुर, जल गंगा संवर्धन अभियान तथा धरती आबा अभियान की समीक्षा की गई। कमिश्नर कार्यालय के एनआईसी केन्द्र से कमिश्नर बीएस जामोद, आईजी गौरव राजपूत, सीसीएफ राजेश राय तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान, आयुक्त नगर निगम अक्षत जैन, सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर, डीएफओ लोकेश निरापुरे तथा अन्य अधिकारी शामिल हुए।

5वीं-8वीं की दूसरी परीक्षा में बच्चों को केन्द्र तक पहुंचाने का जिम्मा स्कूल का

वाहनों पर होने वाला खर्च स्कूल के कंटिजेंसी मद से दिया जाएगा

जागरण,रीवा। सरकारी स्कूलों में शायद पहली बार ऐसा होगा कि बच्चों को परीक्षा केन्द्र तक ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था होगी और इसके लिए स्कूल के कंटिन्जेंसी मद से राशि दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था पहले चुनावों में होती थी और उम्मीदवार अपने समर्थकों और चिन्हित मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करते थे। हालांकि बाद में ये व्यवस्था बंद कर दी गई क्योंकि इसे मतदाताओं को लुभाने का प्रयास माना गया। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यह व्यवस्था मिलने से उनमें खुशी देखी जा रही है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि समस्त शासकीयए मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के छात्रों की पुनः परीक्षा सत्र 2025 26 का आयोजन 1 से 6 जून की अवधि में किया जाएगा। पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा के आयोजन से पूर्व शाला स्तर पर विषयवार अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र गतवर्षानुसार ही केवल जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर रहेंगे। अगर किसी जिले में किसी परीक्षा केन्द्र पर 500 से ज्यादा परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हों तो उस स्थिति में राज्य शिक्षा केन्द्र से अनुमति उपरांत दूसरा परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जा सकेगा।

केन्द्र में कम्प्यूटर और लैपटॉप जरूरी

परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए जाने से पहले यह देखा जाए कि केन्द्र में न्यूनतम 2 कम्प्यूटर-लैपटॉप, 2 कार्यशील प्रिंटर, इंटरनेट, पर्याप्त ए4 साइज पेपर, टोनर की उपलब्धता एवं विद्युत व्यवस्था हो। साथ ही प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग हेतु एक तकनीकी सहायक की व्यवस्था की जाए। इस हेतु जिले की किसी भी संस्था में उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का प्रयोग किया जा सकेगा।

प्रश्नपत्रों को डाउनलोड किया जाएगा

परीक्षा दिनांक को परीक्षा प्रारंभ होने से 3 घंटे पूर्व परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके उस दिवस को आयोजित की जाने वाली परीक्षा के प्रश्नपत्र, परीक्षा केन्द्राध्यक्ष व सहायक परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के लॉगिन से डाउनलोड किए जा सकेंगे। डाउनलोड किए गए प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के लॉगिन पर उपलब्ध कराए गए डॉकेट में प्रदर्शित संख्या के अनुसार की जाना है। कक्षा 5 व 8 के प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग अलग-अलग प्रिंटर से की जाएगी।

गलत उपाधि प्राप्त करने की कुलगुरु से हुई शिकायत

जागरण, रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से पीएचडी की गलत उपाधि लिए जाने की शिकायत कुलगुरु डॉ.राजेन्द्र कुड़रिया से की गई है। शिकायत में उपेन्द्र उपाध्याय निवासी निवासी वार्ड नंबर 15 ओम नगर ने बताया है कि मेनका पाण्डेय पुत्री केशव प्रसाद पाण्डेय वर्ष 2012 से 2015 तक एलएलबी में विधि महाविद्यालय रीवा से नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत रही, जिसका अवधेश प्रताप सिह विवि रीवा से माइग्रेशन बीकॉम में वर्ष 2009 से रहा। इसी माइग्रेशन के आधार पर एलएलबी का नामांकन 132021630229 है। इसी दौरान मेनका पाण्डेय द्वारा वर्ष 2013-14 में विश्व विद्यालय रीवा जिला बदलकर महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय कटनी जबलपुर मप्र से नियमित विद्यार्थी के रूप में पीजीडीसीए की उपाधि प्राप्त की गई, इसी संस्थान से डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा वर्ष 2013-14 में एमकॉम की उपाधि प्राप्त की है जिसका इनरोलमेंट नं.डीई/12219550 है इसी दौरान पुनश्च अवधेश प्रताप सिंह विश्व विद्यालय रीवा के अधीन ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय से नियमित छात्रा के रूप में सितम्बर 2015 में एमफिल की डिग्री प्राप्त की जिसका इनरोलमेन्ट नम्बरः1520100380001 रहा। इस प्रकार जून 2014 से सितम्बर 2015 तक में चार डिग्री हासिल कर विश्व विद्यालय को धोखे में रखा जबकि नियमतः एक संस्थान में नामांकन होने के पश्चात विद्यार्थी बिना माइग्रेशन के किसी दूसरे संस्थान में नामांकित नहीं हो सकता। एक साथ दो अलग-अलग जिले के विश्व विद्यालय में बिना माइग्रेशन के नामांकित होना विद्यार्थी द्वारा धोखे में रखना है, यदि पहले जिस संस्थान में विद्यार्थी दाखिला ले चुका था तो दूसरे संस्थान में किस आधार पर विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा किस आधार पर विद्यार्थी को बिना माइग्रेशन के अपनी संस्थान में दाखिला दिया। यह जानते हुए कि एक संस्थान में माइग्रेशन लगाने के बाद बिना माइग्रेशन दूसरे संस्थान में दाखिला के लिए आवेदन कर ही नहीं सकती, फिर भी उसने जानबूझकर आपराधिक कृत्य किया।

कर्मचारी कल्याण महासंघ की बैठक में कार्यकारिणी का गठन

रीवा। मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ की सामान्य सभा की दो दिवसीय बैठक में विभिन्न प्रकार के केन्द्रीय और राज्य कर्मचारी अधिकारी समुदाय के हितों से संबंधित एजेंडा बिंदुओं पर व्यापक चर्चा और निर्णय पारित हुए। जिसमें अंतिम और महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु महासंघ की कार्यकरिणी भंग कर नई कार्यकरिणी का पुनर्गठन शामिल रहा। देश के समस्त राज्यों से समान्य सभा में प्रतिनिधि कर्मचारी अधिकारी शामिल होकर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का गठन किया गया। मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मू.भूपेंदर सिंह उत्तराखंड की घोषणा की गई और राष्ट्रीय महासचिव के रुप में मू. कमलेश कबीर एमपी को चयन किया गया। 27 सदस्यीय नई सीईसी ने अपने संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई शर्तों व पद की शपथ ली। रीवा एमपी से श्रवण कुमार को राष्ट्रीय संगठन सचिव के रुप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ तो वहीं बालाघाट एमपी से जीतेंद्र सूर्यवंशी को सदस्य के रुप में राष्ट्रीय स्तर के कर्मचारी अधिकारी महासंघ मे जगह मिली।

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, एवं पुनर्वास अनुभाग-सिरमौर जिला-रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 97 भू-अर्जन/कार्य/2026 सिरमौर, दिनांक 21.04.2026

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग-सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-थनवरिया पटवारी हल्का-थनवरिया तहसील-सेमरिया जिला-रीवा	837/1	0.123	
2		837/2	0.123	
3		837/3	0.123	0.001
4		837/4	0.123	
5		837/5	0.123	
6		836/1	0.013	
7		836/2	0.013	
8		836/3	0.013	0.002
9		836/4	0.013	
10		836/5	0.013	
11		835/1	0.150	
12		835/2	0.150	
13		835/3	0.151	0.016
14		835/4	0.151	
15		835/5	0.151	
16		834	0.425	0.020
17		555	0.279	0.010
18		557/1	0.024	0.001
19		557/2	0.024	
20		558	0.125	0.001
21		579	0.085	0.008
22		578	0.061	0.008
23		576	0.049	0.003
24		522/1	1.494	0.002
25		522/2	0.202	
26		502	0.028	0.003
27		499/1	0.073	0.017
28		499/2	0.202	
29		497/1	0.238	0.006
30		497/2	0.243	
31		509/1/1/1	0.106	
32		509/1/1/2	0.214	
33		509/1/2	0.125	
34		509/1/3	0.129	0.012
35		509/1/4	0.065	
36		509/2	0.324	
37		509/3	0.324	
38		510/1/1	0.097	
39		510/1/2/1	0.344	
40		510/1/2/2	0.344	0.019
41		510/2/1	0.057	
42		510/2/2	0.056	
43		495/1	0.045	0.003
44		495/2	0.045	
45		494/1	0.045	
46		494/2/1	0.020	0.002
47		494/2/2	0.010	
48		494/2/3	0.010	
49		493/1	0.696	
50		493/2/1	0.348	0.028
51		493/2/2	0.174	
52		493/2/3	0.174	
53		492	1.052	0.023
54		469/1/1	0.202	
55		469/1/2/1	0.393	
56		469/1/2/2	0.789	
57		469/1/2/3	0.396	
58		469/1/3	1.559	0.081
59		469/1/4	0.669	
60		469/1/5/1	0.204	
61		469/1/5/2	0.100	
62		469/1/6	0.393	
63		469/1/7	0.786	
64		469/2/1	0.393	
65		469/2/2	0.393	
66		455/1/1/1	0.004	
67		455/1/1/2	0.291	0.016
68		455/1/2	0.065	
69		455/2	0.429	
70		452/1/1	0.095	
71		452/1/2	0.095	0.006
72		452/2	0.073	
73		452/3	0.194	
74		453/1	0.365	0.002
75		453/2	0.121	
76		454	0.611	0.005
77		438	0.906	0.029
78		426	0.563	0.001
79		428	0.486	0.011
80		430	1.052	0.024
81		434	0.644	0.001
82		433/1/1	0.283	
83		433/1/2	0.287	0.022
84		433/2	0.570	
85		827	0.275	0.005
86		821	0.012	0.001
87		823/1	0.323	
88		823/2	0.322	0.017
89		823/3	0.323	
90		823/4	0.323	
91		824/1	0.137	0.003
92		824/2	0.071	
93		817/1/1	0.004	
94		817/1/2/1	0.202	
95		817/1/2/2	0.032	
96		817/2/1	0.049	0.012
97		817/2/2	0.049	
98		817/3/1	0.401	
99		817/3/2	0.401	
100		811/1	0.024	
101		811/2	0.061	
102		811/3	0.061	
103		811/4	0.077	
104		811/5	0.069	
105		811/6	0.198	
106		811/7	0.255	
107		811/8	0.032	0.011
108		811/9	0.081	
109		811/10	0.077	
110		811/11	0.186	
111		811/12	0.429	
112		811/13/1	0.186	
113		811/13/2	0.754	
114		811/14/1	0.645	
115		811/14/2	0.646	
116		220/1	1.619	
117		220/2/1	0.093	
118		220/2/2/1	0.215	
119		220/2/2/2	0.190	
120		220/2/3	0.097	
121		220/2/4	0.093	
122		220/2/5	0.202	
123		220/2/6	0.085	0.023
124		220/2/7	0.089	
125		220/2/8/1	0.216	
126		220/2/8/2	0.201	
127		220/2/9	0.138	
128		220/2/10/1	0.202	
129		220/2/10/2	0.040	
130		220/3	0.405	
131		220/4	0.405	
132		193	0.441	0.011
133		136/1	0.369	
134		136/2	0.365	0.009
135		136/3/1	0.185	
136		136/3/2	0.184	
137		137/1	0.405	0.015
138		137/2	0.758	
139		182	0.016	0.003
140		138	0.263	0.005
141		139	0.263	0.004
142		180	0.045	0.001
143		149	1.291	0.026
144		150	0.267	0.007
145		151	0.987	0.008
146		152	0.065	0.001
147		153	0.045	0.002
148		154	0.615	0.007
149		155/1	0.619	
150		155/2/1	0.377	0.017
151		155/2/2	0.381	
152		155/3	0.486	
153		28/1/1	0.053	
154		28/1/2	0.057	0.004
155		28/2/1	0.028	
156		28/2/2	0.024	
157		27/1/1	0.766	
158		27/1/2	0.762	0.014
159		27/2/1	0.381	
160		27/2/2	0.381	
161		19/1/1	10.927	
162		19/1/2/1	0.020	
163		19/1/2/2	0.183	
164		19/1/2/3	0.202	
165		19/1/2/4	0.202	
166		19/1/2/5	0.202	
167		19/1/2/6	0.202	
168		19/1/2/7	0.203	
169		19/1/3	0.809	0.066
170		19/1/4	0.405	
171		19/1/5	0.809	
172		19/1/6	0.405	
173		19/2	4.047	
174		19/3/1	0.305	
175		19/3/2	0.302	
176		19/4	2.428	
	(अ) निजी भूमि का योग-	176 किता	66.725	0.655
1		844	0.190	0.003
2		553	1.821	0.020
3		556	0.858	0.023
4		593	1.380	0.008
5		573	0.271	0.009
6		829/1	0.263	0.001
7		829/2	0.809	
8		828	1.072	0.002
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	8 किता	6.664	0.066
	अ + ब का योग-	कुल 184 किता	73.389	0.721

अनुविभागीय अधिकारी
अपर सी0डब्ल्यू0सी0 उप संभाग क्र.-3
गोविंदगढ रीवा (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री,
क्योटी नहर संभाग
रीवा (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं
पुनर्वास अनुभाग सिंरमौर
जिला-रीवा (म.प्र.)

G-12173/26

पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शुरू हुई शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना

सैन्य बलों में भर्ती हेतु मिलेगा निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण

जागरण, रीवा। मध्यप्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा युवाओं को सैन्य और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार करने के लिए महत्वाकांपहल शुरू की गई है। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि जिले में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का आगाज किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान युवक-युवतियों को थल सेना, पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना है।

जिले से होगा 200 अभ्यर्थियों का चयन : इस योजना के तहत रीवा जिले से कुल 200 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिनमें 100 बालक और 100 बालिकाएं शामिल होंगी। यह पूरी तरह से एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसकी अवधि 45 दिन निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को न केवल शारीरिक दक्षता के लिए तैयार किया जाएगा, बल्कि उन्हें सैद्धांतिक विषयों का भी गहन ज्ञान दिया जाएगा।

प्रदेश का रंगमंच भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का संवाहक

जागरण, रीवा। मध्य प्रदेश का रंगमंच भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का सशक्त संवाहक है, जो प्राचीन संस्कृत नाट्य परंपरा से लेकर आधुनिक प्रयोगधर्मी रंगमंच तक एक निरंतर विकसित होती धारा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश का रंगकर्म लोकजीवन, लोककलाओं, साहित्य, सामाजिक सरोकार और सौंदर्यबोध का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। उक्त बातें विख्यात लेखक, निर्देशक एवं वरिष्ठ रंगकर्मी आलोक शुक्ला ने कही, वे विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के पत्रकारिता विभाग में आयोजित थिएटर सर्टिफिकेट कोर्स के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। अपने व्याख्यान में उन्होंने महान संस्कृत नाटककार कालिदास , सेठ गोविंद दास, हिन्दी के प्रारंभिक नाटक आनंद रघुनन्दन के रचयिता महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव, वेंकटरमण सिंह जूदेव ,हबीब तनवीर, बंशी कौल,बी. वी. कारंत तथा अलकनंदन जैसे रंगपुरोधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी ने मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के रंगमंच को समृद्ध किया है। उन्होंने प्रदेश के लोक रंगमंच को आधुनिक रंगमंच की आधारशिला बताते हुए इंदौर,ग्वालियर जबलपुर और भोपाल जैसे प्रमुख रंगकेंद्रों की विशेष चर्चा की। साथ ही मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों के विविध लोकनाट्य रूपों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये नाट्य परंपराएँ लोकभाषा, गीत-संगीत और सामाजिक कथाओं पर आधारित रही हैं, जिन्होंने आधुनिक रंगमंच को गहराई और आधार प्रदान किया है। व्याख्यान के अंत में उन्होंने वर्तमान रंगकर्मियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मध्य प्रदेश के रंगमंच के भविष्य को उज्ज्वल बताया। हालांकि, उन्होंने संसाधनों की कमी, महंगे होते सभागार और कलाकारों के जीविकोपार्जन से जुड़ी समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस दिशा में सरकार और वरिष्ठ रंगकर्मियों को मिलकर ठोस पहल करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं प्रसिद्ध लेखक एवं निर्देशक सतीश दवे तथा उपस्थित छात्रों ने आलोक शुक्ला को अंगवस्त्र एवं महाकाल की पेंटिंग भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर उनकी नाट्य टीम के सदस्य प्रताप सिंह, विजय लक्ष्मी, टेकचंद, विनय शर्मा एवं सुश्री कविता को भी पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया गया।

आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें

कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर समयबद्ध क्रियान्वयन करें सुनिश्चितः उप मुख्यमंत्री

शहर में जल प्रदाय योजना एवं सीवरेज सिस्टम कार्यों की वृहद समीक्षा की

जागरण, रीवा। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में रीवा शहर में संचालित जल प्रदाय योजना एवं सीवरेज सिस्टम से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, समय-सीमा तथा वित्तीय प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएँ, ताकि आम नागरिकों को समय पर सुविधाओं का लाभ मिल सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे, आयुक्त संकेत भोंडवे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने जल प्रदाय व्यवस्था के शेष सभी कार्य, विशेषकर ओवरहेड वाटर टैंक के निर्माण एवं जल वितरण नेटवर्क का विस्तार, आगामी वर्षा ऋतु से पहले हर स्थिति में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों के दौरान नागरिकों की दैनिक जीवनचर्या प्रभावित न हो, इसके लिए कार्यों को सुनियोजित एवं चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाए। आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर उन्होंने बल दिया।

सीवरेज सिस्टम पर देरी न हो : सीवरेज सिस्टम की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने शेष पाइपलाइन बिछाने के कार्य तथा हाउस सर्विस कनेक्शनों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीवरेज नेटवर्क का समय पर पूर्ण होना शहरी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है ।

कार्यालय नगर परिषद गुढ़ जिला- रीवा (म.प्र.)

cmogudh@mpurban.gov.in

क्र.603/(E.T.)/न.परि./2026 — गुढ़ दिनांक 28.04.2026

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

नगर परिषद् गुढ़ द्वारा निर्माण कार्य हेतु म.प्र. लोक निर्माण विभाग में नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत पंजीकृत सप्लायरों/ठेकेदारों से ई-टेण्डर के माध्यम से तालिका में वर्णित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा के आधार पर दरें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र क्रय डाउनलोड करने एवं निविदा से संबंधित समस्त शर्तें एवं जानकारी वेबसाइट http://www.mptenders.gov.in से एवं कार्यालय नगर परिषद गुढ़ से प्राप्त की जा सकती है।

क्र.	निविदा क्र. एवं दिनांक	सिस्टम टेण्डर क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य की समयावधि
1	603/ 28.04.2026	2026_UAD_ 503605_1	SUPPLY AND DELIVERY OF ELECTRIC MATERIALS AT NAGAR THE STORE OF PARISHAD GURH IN FINANCIAL YEAR 2026-27.	10.00	10000.00	2000.00	31 मार्च 2027

शर्तें-
1. ईनिविदा प्रपत्र वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर ऑनलाइन भुगतान करने पर प्राप्त हो सकेगा एवं दिनांक 28.04.2026 को समय 5:30 सायं बजे से दिनांक 13.05.2026 को समय 5:30 सायं बजे तक ऑनलाईन क्रय कर सकते हैं। निविदा में संसोधन की सूचना वेवसाईट पर ही प्रकाशित की जावेगी, समाचार पत्र पर संशोधन की सूचना प्रकाशित नही की जावेगी।
2. ठेकेदारों को जीवित पंजीयन पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. में पंजीयन का प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. कार्य समय पर पूर्ण न होने में अनुबंध की शर्तो के तहत 10% सकल देयक के कटौती की जावेगी।
4. ऐसे सप्लायर जो किसी निकाय, नगर पालिका, नगर निगम से या अन्य संस्था से ब्लेक लिस्टेड है वह इस निविदा में भाग नहीं ले सकता है।

(मोहित शुक्ला)
मुख्य नगर पालिक अधिकारी
नगर परिषद गुढ़
जिला-रीवा (म.प्र.)

आम सूचना

रीवा दिनांक 29.04.2026 सर्व साधारण को सूचित किया जाता अनिल कुमार सिन्हा पिता श्री स्व. रविचन्द्रबहादुर सिन्हा एवं मंजू सिन्हा पत्नी अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा शिल्पी सिटी रीवा भवन क्रमांक W11 चोरहटा स्थित आवासीय कालोनी शिल्पी सिटी के भूखण्ड क्रमांक-19 टाइप-बी पर घर निर्मित है जिसको दोंनों ने जमुना प्रसाद गुप्ता तनय स्व. विश्नाथ गुप्ता निवासी फुटबाल मैदान के पास जिला सतना म.प्र. से दिनांक 21.03.2023 को क्रय किया था, उक्त मकान को क्रय करते समय जमुना प्रसाद गुप्ता तनय श्री विश्वनाथ गुप्ता निवासी फुटबाल मैदान के पास नागौद जिला सतना ने दिनांक 28 मार्च 2014 को ग्रंथ क्रमांक-9778, सीरियल क्रमांक-12670 के माध्यम से पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कराकर क्रय किया था। जिसकी मूल रजिस्ट्री ग्रंथ क्रमांक-9778, सीरियल क्रमांक-12670 गुम गयी है जो काफी तलाश करने पर भी नही मिल रही है। जिसकी शिकायत थाना चोरहटा मे की गयी है शिकायत का पंजीयन किया गया है जिसकी पंजीकरण संख्या-213457260006 दिनांक 16.04.2026 को कराया गया है। उक्त सम्पत्ति को वर्तमान भूमिस्वामी विक्रय कर रहे है जिसमे क्रेता अपने नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा ताला जिला सतना शाखा कोड-64781 से लोन कराना चाहता है, अगर किसी वित्तीय संस्था, बैंक सोसायटी या आमजन को अगर कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अंदर भारतीय स्टेट बैंक शाखा ताला जिला सतना ब्रांच कोड-64781 या थाना चोरहटा जिला रीवा मे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

अमित कुमार सिंह
अधिवक्ता
जिला एवं सत्र न्यायालय,
रीवा (म.प्र.)
मो.: 9630092670, 8717839062

RN-85045

GENERAL INFORMATION

Rewa dated 29/04/2026 It is informed to the general public that Anil Kumar Sinha, son of Shri Late Ravichandra Bahadur Sinha and Manju Sinha, wife of Ashok Kumar Sinha, have constructed a house on plot number 19 Type-B of Shilpi City residential colony situated at Shilpi City Rewa building number WII Chorhata, which both of them had purchased from Jamuna Prasad Gupta, son of late Vishnay Gupta, resident near football ground, district Satna, M.P. on 21/03/2023. While purchasing the said house, Jamuna Prasad Gupta, son of Shri Vishwanath Gupta, resident near football ground, Nagaud, district Satna, had executed a registered sale deed from the Registrar's office on 28 March 2014 through Grant number-9778, Serial number-12670. The original registry of which Grant number-9778, Serial number-12670 has been lost and is not found even after a lot of searching. A complaint has been lodged at the Chorhata police station and the complaint has been registered with registration number 213457260006 dated 16/04/2026. The current landowner is selling the said property, in which the buyer wants to get a loan in his name from the State Bank of India, Tala, District Satna, Branch Code-64781. If any financial institution, bank society or the general public has any objection, they can register their objection within 15 days at the State Bank of India, Tala, District Satna, Branch Code-64781 or at the Chorhata Police Station, District Rewa.

Amit Kumar Singh
Advocate
Distt. & Session Court,
Rewa (M.P.)
Mob.: 9630092670, 8717839062

RN-85045

सूचना

जागरण पब्लिकेशन प्रा. लि. किसी तृतीय पार्टी के उत्पादकों वस्तुओं या सेवाओं का समर्थन नहीं करती है और न ही किसी तृतीय पार्टी के विज्ञापनों में छपी किसी जानकारी की सच्चाई या विश्वसनीयता की पुष्टि करती है। जागरण पब्लिकेशन प्रा. लि. पाठकों को प्रेरित करती है कि वे ऐसे किसी भी विज्ञापनदाता के साथ कोई भी लेन-देन करने की कार्रवाई से पहले उचित व जरुरी समझे जाने वाली जांच पड़ताल कर लेवे।

लोन

लोन फाईनेंस सर्विस रीवा संभाग में विशेष लोन व्यवस्था मुद्रा लोन, आधार कार्ड, मार्कशीट, पर्सनल, कृषि लोन और सभी प्रकार के लोन 2% ब्याज 50% छूट (एजेंट आमंत्रित) संपर्क - 8962086944

कार्यालय नगर पालिका परिषद् गंजबासौदा

जिला विदिशा (म.प्र.)

नगर पालिका भवन, पुराना मेला ग्राउण्ड, शा. राजीव गांधी जनचिकित्सालय के पीछे, वार्ड क्र. 15 गंजबासौदा
Email cmoganjbasoda@mpurban.gov.in ☎ 07594-221104

ई -निविदा आमंत्रण सूचना

क्र./स्था/2026/2184 — गंजबासौदा दिनांक 29/4/2026

नगर पालिका परिषद् गंजबासौदा द्वारा निम्न कार्य हेतु ई-निविदा का आमंत्रण किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

ई-निविदा क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	ई-निविदा क्रय अंतिम दिनांक
2026_UAD_ 503486_1	40 संविदा कर्मचारी की सेवाएँ प्रदान करना	45,00,000.00	100000.00	10000.00	12.05.2026

निविदा प्रपत्र क्रय, डाउनलोड करने एवं निविदा से संबंधित समस्त शर्तें एवं जानकारी mptenders.gov.in से एवं नगर पालिका परिषद् गंजबासौदा की स्था. शाखा से प्राप्त की जा सकती हैं। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन होने पर वेबसाईट पर या कार्यालय से जानकारी प्राप्त होगी संशोधन का प्रकाशन समाचार पत्र में नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् गंजबासौदा

कार्यालय नगर पालिका परिषद, आष्टा, जिला-सीहोर, म.प्र.

क्रमांक/225/ई-टेण्डरिंग/तक.शा./ न.पा./ 2026 — आष्टा दिनांक 24.04.2026

-:: ई-निविदा आमंत्रण सूचना ::-

एतद् द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन (Online) निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट- www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

कार्य का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	ऑनलाईन टेंडर नं.	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_ 503204_1	नगरीय क्षेत्र आष्टा में हेण्डपम्प का गड्ढे पुनर्भरण निर्माण कार्य ।	1 माह 1485042/-	5000/- 11140/-	09.05.2026 सायं 17:30 तक
2	2026_UAD_ 503204_2	नगरीय क्षेत्र आष्टा में घरेलू वर्षा जल संचयन कार्य।	1 माह 1613547/-	5000/- 11140/-	09.05.2026 सायं 17:30 तक
3	2026_UAD_ 503204_3	वार्ड क्र. 16 में सेमनरी रोड से जगन्नाथपुरा ग्राम की पुलिया तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य ।	12 माह 27764783/-	10000/- 208240/-	28.05.2026 सायं 17:30 तक
4	2026_UAD_ 503204_4	निकाय क्षेत्रांतर्गत इन्दौर नाका से महाराणा प्रताप चौराहा भोपाल तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	12 माह 38193211/-	10000/- 286450/-	28.05.2026 सायं 17:30 तक
5	2026_UAD_ 503204_5	पार्वती नदी के दोनों किनारे एवं Up Stream/Down Stream के संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य ।	12 माह 24278410/-	10000/- 286450/-	28.05.2026 सायं 17:30 तक
6	2026_UAD_ 503204_6	वार्ड क्र. 04 एवं 05 में किले की रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	6 माह 12235751/-	10000/- 91770/-	28.05.2026 सायं 17:30 तक
7	2026_UAD_ 503204_7	निकाय क्षेत्रांतर्गत फायर स्टेशन के पास कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य ।	8 माह 17180933/-	10000/- 128860/-	28.05.2026 सायं 17:30 तक

नोट- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। जी.एस.टी. पृथक से देय होगी। निकाय की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।

विनोद कुमार प्रजापति	कमलेश जैन	सिद्धीका बी भूरू भाई	हेमकुंवर रायसिंह मेवाड़ा
मुख्य न.पा. अधिकारी	प्रभारी	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
न.पा.प. आष्टा	लो.नि. विभाग, न.पा. आष्टा	न.पा.प. आष्टा	न.पा.प. आष्टा

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, एवं पुनर्वास अनुभाग-सिरमौर जिला-रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 99 भू-अर्जन/कार्य/2026 — सिरमौर, दिनांक 21/04/2026

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए। अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग-सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-भटिगवां पटवारी हल्का- भटिगवां तहसील-सेमरिया जिला-रीवा	148/1/105	0.405	
2		148/2/1/105	0.223	
3		148/2/2/105	0.222	
4		148/3/105	0.405	0.019
5		148/4/1/105	0.162	
6		148/4/2/105	0.081	
7		148/4/3/105	0.081	
8		148/4/4/105	0.081	
9		105/1/1	0.186	
10		105/1/2	0.186	
11		105/1/3/1	0.737	
12		105/1/3/2	0.365	0.025
13		105/1/4	0.084	
14		105/1/5/1	0.171	
15		105/1/5/2	0.171	
16		105/2	0.283	
17		100/1	0.771	0.03
18		100/2	0.771	
19		106	0.097	0.002
20		95	0.065	0.002
21		38/1	1.161	
22		38/2/1/1	0.061	
23		38/2/1/2	0.061	
24		38/2/1/3	0.062	
25		38/2/2	0.099	
26		38/2/3	0.184	
27		38/2/4	0.100	
28		38/3	0.040	
29		38/4	0.085	0.013
30		38/5/1/1	0.009	
31		38/5/1/2	0.008	
32		38/5/1/3	0.009	
33		38/5/2	0.025	
34		38/5/3	0.025	
35		38/5/4	0.025	
36		38/6	0.040	
37		38/7/1	0.056	
38		38/7/2	0.069	
39		29/1/1	0.081	
40		29/1/2	0.081	0.019
41		29/2	0.202	
42		29/3	0.040	
43		31/1	0.603	
44		31/2	0.304	
45		31/3	0.061	0.012
46		31/4	0.060	
47		31/5	0.182	
48		27/1	0.223	0.014
49		27/2	0.223	
50		27/3	0.223	
51		26	0.174	0.005
52		24	0.089	0.006
53		23	0.166	0.002
54		9/1/1/1	0.336	
55		9/1/1/2/1	0.107	
56		9/1/1/2/2	0.107	
57		9/1/1/2/3	0.106	
58		9/1/1/3	0.251	
59		9/1/2	0.255	0.034
60		9/2	0.002	
61		9/3	0.125	
62		9/4	0.129	
63		9/5	0.149	
64		9/6	0.121	
65		9/7	0.040	
66		9/8	0.040	
67		8/1	0.263	
68		8/2	0.202	
69		8/3	0.405	0.006
70		8/4	0.190	
	(अ) निजी भूमि का योग-	70 किता	13.206	0.189
1		97	0.906	0.007
2		92	0.805	0.003
3		1	0.793	0.004
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	3 किता	2.504	0.014
	अ+ब का योग-	कुल 73 किता	15.710	0.203

अनुविभागीय अधिकारी
अपर सी.डब्ल्यू.सी. उप संभाग क्र.-3
गोविंदगढ रीवा (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री,
क्योटी नहर संभाग
रीवा (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग सिरमौर जिला-रीवा (म.प्र.)

G-12145/26

प्रदेश कार्यसमिति में 33 प्रतिशत महिलाओं की होगी भागेदारी

विस में संकल्प पारित होने के बाद महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की तैयारी, दिल्ली से पहले मप्र भाजपा की कार्यसमिति होगी घोषित

विशेष संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संकल्प पारित होने के बाद मध्यप्रदेश भाजपा अब संगठन में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में है। पार्टी प्रदेश कार्यसमिति में 33 प्रतिशत महिलाओं को सदस्य बना सकती है। इसके लिए पिछले दो दिनों से कार्यसमिति सदस्य बनाने महिलाओं की सूची तैयार की जा रही है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश भाजपा की प्रदेश टीम घोषित हो चुकी है,लेकिन अभी तक कार्यसमिति का गठन नहीं किया गया है। जबकि अगले माह ओरछा में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक करने का निर्णय हो चुका है। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व को बैठक से पहले अपनी कार्यसमिति की घोषणा करनी होगी। पार्टी से जुड़े जानकारों का कहना है कि मई के प्रथम सप्ताह में पार्टी की राष्ट्रीय टीम की घोषणा हो जाएगी,जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पहली कार्यसमिति की बैठक भी आहुत होगी। इसके बाद मध्यप्रदेश कार्यसमिति की बैठक बुलाई जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रीय टीम की घोषणा से पहले मध्यप्रदेश भाजपा कार्यसमिति का एलान कर दिया जाएगा। संगठन से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि पार्टी मध्यप्रदेश में ये संदेश देना चाहती है कि भाजपा महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है,इसलिए संगठन के भीतर महिलाओं की भागेदारी बढ़ाने नई रणनीति अपनाई जा रही है। यह क्रम जिला और मंडल स्तर तक जारी रहेगा।

निगम-मंडलों की नियुक्तियां में भी बढ़ेगी हिस्सेदारी

बुधवार को प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व के बीच हुए मंथन से यह बात भी सामने आ रही है कि निगम मंडलों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। हालांकि निगम मंडलों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन की सूची पर केन्द्रीय नेतृत्व की मुहर लग चुकी है, लेकिन कुछ पदों पर नाम बदले जा सकते हैं। ऐसा कर संदेश देना चाहता है कि नारी सशक्तीकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

महिला मंत्रियों का बढ़ेगा कद

मध्यप्रदेश में जब भी मंत्रिमण्डल में फेरबदल या विस्तार होगा,उसमें कुछ मौजूदा मंत्रियों का कद बढ़ाया जा सकता हैं। विस्तार होने पर एक दो महिला विधायको को शपथ भी दिलाई जा सकती हैं।

50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का पंचायती क्षेत्रों में होगा प्रचार

इसी तरह प्रदेश भाजपा ने महिला आरक्षण के विषय पर कांग्रेस को बेनकाब करने के लिए अलग से रणनीति तैयार की है। पार्टी के निकायों और पंचायती क्षेत्रों में प्रचार के दौरान जनता को यह बताएंगे कि उनके दल ने पिछले चुनावों को दौरान महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टर व अन्य माध्यमों से यह बताया जाएगा कि मौजूदा समय में राज्य की 313 जनपद पंचायतों में से179 में महिलाएं अध्यक्ष है,इसी तरह प्रदेश की आधी जिला पंचायतों की भी महिलाओं के हाथों में कमान है। पंच सरपंच,जनपद और जिला पंचायत सदस्य भी महिलाएं हैं।

सरकार की योजनाओं पर भी किया जा रहा फोकस

इसी तरह लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूहों सहित उन योजनाओं के बारे में भी ग्रामीण स्तर पर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा, जो महिलाओं के लिए संचालित की जा रही हैं।

बंद कमरे में बनी रणनीति मंत्री अहिरवार को बुलाया

बुधवार को प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने प्रदेश कार्यसमिति सहित दूसरे संगठनात्मक निर्णयों को लेकर बंद कमरे में मंत्रणा की। दोनों नेता खंडेलवाल के निवास पर तकरीबन अकेले में इन विषयों पर मंथन करते रहे। इससे पहले प्रदेशाध्यक्ष ने सुबह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उनके निवास पर भेंट की थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई है। इसमें सबसे अहम मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अटकी सूची पर चर्चा हुई है। इस पर महिला और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों के नामों की जल्द घोषणा करने पर सहमति बनने की खबर सामने आ रही है। सरकार के वन राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार को पार्टी कार्यालय बुलाया। यहां से अहिरवार अपना वाहन छोड़कर प्रदेशाध्यक्ष के साथ रवाना हुए। उनके साथ प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, कार्यालय मंत्री श्याम महाजन और उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बरुआ भी मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो ये सभी नेता क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के निवास पहुंचे थे,जहां उनकी बुंदेलखण्ड से जुड़े विषय पर चर्चा हुई है। इसमें बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण के अलावा दूसरे विषय चर्चा के बताए जा रहे हैं।

संक्षिप्त खबरें

दो विकास प्राधिकरणों में सरकार ने की नियुक्तियां

विशेष संवाददाता, भोपाल। राज्य सरकार ने बुधवार को दो विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी। मनोहर पोरवाल रतलाम विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह विजय यादव को चित्रकूट विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पोरवाल के साथ गोविंद काकाणी और प्रवीण सोनी को प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आदेश में रतलाम विकास प्राधिकरण के सदस्यों की भी नियुक्ति की गयी है। इनमें राजेन्द्र सिंह गोयल, राजेन्द्र मौर्य,धीरज व्यास, श्रीमती राखी व्यास और श्रीमती किरण महावर के नाम शामिल हैं। इसी तरह एक अन्य आदेश में राज्य शासन ने चित्रकूट विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पूर्व सतना जिलाध्यक्ष इन्द्रराज सिंह यादव के परिवार के सदस्य विजय यादव को सौंपी है।

उपार्जन केंद्रों का मुख्यमंत्री करेंगे आकस्मिक निरीक्षण

विसं, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में उपार्जन केंद्र पर चल रही गेहूँ उपार्जन की प्रक्रिया का आने वाले दिनों में आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और किसानों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव निरीक्षण में देखेंगे कि निर्देशानुसार शासन-प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाएं किसानों को प्राप्त हो रही है या नहीं। आकस्मिक निरीक्षण के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव का हेलीकॉप्टर किसी भी समय, कहीं पर भी उतर सकता है। गेहूँ उपार्जन एवं स्लॉट बुकिंग की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी है।

19 मई को भोपाल में लगेगी डाक अदालत

जागरण, भोपाल। डाक विभाग के मप्र परिमंडल द्वारा 19 मई को भोपाल में डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें काउंटर सेवायें,बचत बैंक,मनी ऑर्डर सहित विभाग से जुड़ी शिकायत व याचिकाओं का निराकरण किया जाएगा। डाक अदालत में शिकायतों का निराकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसके विभाग ने अपनी ईमेल आईडी जारी की है। जिस पर आवेदक 8 मई तक अपनी शिकायतें या याचिका भेज सकते है।

राजस्थान पुलिस की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त

तीनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलग-अलग बयान दर्ज करने के दिए निर्देश

जागरण, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के समक्ष बुधवार को राजस्थान पुलिस द्वारा तीन युवकों को भोपाल से जयपुर ले जाकर गिरफ्तार करने के मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन के सामने पेश किये गए तीनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान पुलिस के दावों झूठा बताया। युवकों ने बताया कि हकीकत पुलिस के बयानों से एकदम उलट है। विरोधाभासी बयानों को देखते हुए कोर्ट ने तीनों युवकों के अलग-अलग बयान दर्ज कराने, संबंधित पुलिस अधिकारियों से शपथपत्र मंगाने और अगली सुनवाई पर सभी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 12 मई को होगी। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से वायरल कथित पत्र के मामले में कांग्रेस आईटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में युवकों के परिजन भोपाल के खिजर खान व अन्य की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता एचएस छाबड़ा ने कोर्ट को बताया कि 20 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग 3 बजे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भोपाल में पुलिस द्वारा कांग्रेस आईटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं (निखिल, बिलाल व इनाम) को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और उन्हें दो दिनों तक किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया। बुधवार को तीनों युवकों को हाईकोर्ट में पेश किया गया। राजस्थान पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि युवकों को अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा गया था। उन्हें 22 अप्रेल को दोपहर को गिरफ्तार किया गया तथा उसी दिन संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। उन्हें जयपुर की अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत प्रस्तुत नहीं होने के कारण वे अभी भी हिरासत में हैं। राजस्थान पुलिस ने यह भी कहा कि युवकों को भोपाल से गिरफ्तार कर नहीं लाया गया था, बल्कि वे मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारियों के साथ स्वयं जयपुर आए थे। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि किसी अधिकारी को नियुक्त कर तीनों युवकों के अलग-अलग बयान दर्ज करवाएं बयान में यह बताया जाए कि मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संपर्क किए जाने से लेकर जयपुर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने तक वास्तव में क्या हुआ।बयान के बाद युवकों को वापस जयपुर भेजने के निर्देश दिए गए ताकि वे जमानत की शर्तें पूरी कर सकें।

जयपुर ले जाने तक क्या-क्या हुआ, मांगी जानकारी

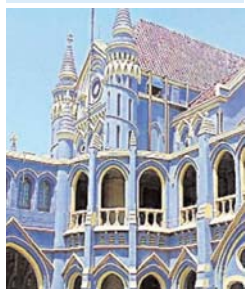

औषधीय फसलों को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराएगी सरकार: मुख्यमंत्री

समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने के दिए निर्देश

विशेष संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश के उद्यानिकी और मसाला उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह औषधि फसलों को भी विदेशी बाजार प्रदान करने के लिए सरकार सप्लाई चेन तैयार करेगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री बुधवार को मंत्रालय में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। हमारी उद्यानिकी एवं मसाला फसलों की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ रही है। पूर्ति के लिए अधिकारी बाजार तलाशें और उद्यानिकी उत्पादों की भरपूर ब्रांडिग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहां औषधीय गुणों से भरपूर फसलों की खेती भी बहुतायत में की जाती है। औषधि निर्माण के लिए जरूरी इन फसलों की इन्टरनेशनल मार्केट में मांग अनुसार आपूर्ति के लिए पूरी सप्लाई चेन तैयार की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को उद्यानिकी फसलों के पैदावार के लिए प्राकृतिक खाद का उपयोग कर जैविक खेती से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि उद्यानिकी फसलें छोटी जगह से बड़ी कमाई करने का प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि प्रदेश में हर साल नये-नये आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल खोले जा रहे हैं। इनमें देशी/आयुर्वेदिक दवाईयों की आपूर्ति में प्रदेश की औषधीय फसलों एवं उप-उत्पादों का भरपूर उपयोग किया जाए।

उज्जैन में खुलेगा फ्लोरीकल्चर: बैठक में अफसरों को बताया गया कि सिंहस्थ-2028 के मद्देनजर उज्जैन में फूलों की खेती को प्रोत्साहन एवं विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए उज्जैन में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फ्लोरीकल्चर की स्थापना की जा रही है। सेंटर स्थापना के लिए उज्जैन शहर के पास एक गांव में 19 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर समुचित समन्वय भी किया जा रहा है। बैठक में बताया गया गया कि वर्ष 2030 तक उद्यानिकी क्षेत्र का रकबा 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा।

अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय से समग्र पेंशन योजना के तहत हितग्रागियों को राशि अंतरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के जरुरतमंद व्यक्ति तक मदद पहुंचाना है। इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, यह सरकार के उस विश्वास का अंतरण है, जो इस बात का प्रतीक है कि सरकार हर परिस्थिति में हर घड़ी जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी निर्धन, निराश्रित, वृद्धजनों, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहिता एवं दिव्यांगजनों के कल्याण एवं आर्थिक सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है। इस मौके पर सीएम ने सिंगल क्लिक से राज्य के 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों के बैंक खातों में 200 करोड़ 71 लाख रुपये की पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की।

आतिशबाजी के बीच पदभार ग्रहण करने पहुंचे यादव और नगाइच

विशेष संवाददाता भोपाल। अपेक्स बैंक के नवनियुक्त प्रशासक महेन्द्र सिंह यादव और मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन अध्यक्ष संजय नगायच ने पदग्रहण कर लिए। इससे पहले दोनों नेता पार्टी मुख्यालय में हुई आतिशबाजी के साथ कार्यालयों के लिए निकले। दोनों नेता बोर्ड ऑफिस चौराहे तक साथ रहे। इसके बाद अपने कार्यालय के लिए रवाना हुए। अपेक्स बैंक के प्रशासक का पद भार ग्रहण करने से पहले महेन्द्र सिंह यादव ने सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्णा गौर और सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से भेंट की। सहकारिता मंत्री सारंग ने कहा कि महेन्द्र सिंह यादव संगठन एवं पार्टी के एक कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उनके द्वारा सहकारी आंदोलन को गति देने काम किया जाएगा। अपने संबोधन में प्रशासक यादव ने कहा कि वे स्वयं किसान पृष्ठभूमि से संबंध रखते है। ऐसे में उन्हें किसानों की समस्याओं का भान है। एक समय था जब गैर भाजपा सरकारें किसानों के 15 तो कभी 18 प्रतिशत के ब्याज पर बढ़ी मुश्किल से ऋण उपलब्ध करा पाती थी और किसान साहूकारों के चुंगल में फंसा रहता था,लेकिन वर्ष प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद सरकार ने किसानों को 0 प्रतिशत ऋण पर सरल प्रक्रिया के तहत ऋण उपलब्ध कराना शुरु किया। भाजपा सरकार हमेशा से ही सर्वहारा वर्ग के उत्थान का काम करती है।

नगाइच ने किया पदभार ग्रहण

नगायच ने पूजा कर वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर कॉर्पोरेशन की योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान एडीशनल एमडी बृजेश सक्सेना सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

जलती बस से यात्रियों की जान बचाने वाले 8 पुलिस कर्मियों को कैश रिवार्ड

मुख्य संवाददाता, भोपाल। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाणा ने ग्वालियर में बस हादसे के दौरान साहस दिखाने वाले ८ पुलिस कर्मियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है। घटना 26 अप्रैल की सुबह की है, जब जयपुर से छतरपुर के बागेश्वर धाम जा रही एसी स्लीपर बस का टायर ग्वालियर के झांसी रोड थाने के सामने फट गया था और बस के पिछले हिस्से में तेजी से आग लग गई। डीजीपी ने इन सभी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड में भी इसे दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। धमाके की आवाज सुनते ही थाने में मौजूद अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कांच तोड़कर अंदर फंसे 21 महिलाओं, बच्चों और अन्य यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस के इस एक्शन से बड़ा हादसा टल गया। डीजीपी के अनुसार, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीआई शक्ति सिंह यादव को 2500 रुपये, प्रधान आरक्षक शिव सिंह गुर्जर, रामवरन लोधी और सुशील चौहान को 1500-1500 रुपये तथा आरक्षक हरिओम जाट, सलमान खान, आकाश छारी और रवि भदौरिया को 1000-1000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया है।

बीना विधायक सप्रे मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

90 दिन की समय सीमा तो 720 दिन में मामले का निराकरण क्यों नहीं हो पाया

जागरण, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने बीना विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दलबदल मामले के निराकरण में देरी पर नाराजगी जताई। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि मामले की विधिवत सुनवाई विधानसभा स्पीकर द्वारा की जा रही है। उमंग सिंघार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच प्रक्रिया जारी है। इस पर चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब दलबदल मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों के भीतर निर्णय देने की समय सीमा तय की है, तो 720 दिनों में भी अभ्यावेदन का निराकरण क्यों नहीं हो पाया। कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन स्पीकर के संज्ञान में लाएं। वहीं उमंग सिंघार के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 90 दिन की समय सीमा का पालन सुनिश्चित किए जाने की मांग की। अगली सुनवाई 18 जून को होगी। दरअसल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका के जरिए दल-बदल कानून के तहत बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का निर्वाचन शून्य करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने 30 जून, 2024 को विधानसभा अध्यक्ष तोमर के समक्ष इस मामले में याचिका दायर की थी। लेकिन निर्धारित 90 दिन गुजरने के बावजूद कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। लिहाजा, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि विधायक निर्मला सप्रे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थीं। लोकसभा चुनाव के दौरान पांच मई, 2024 को राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थीं। याचिकाकर्ता का कहना है कि कांग्रेस विधायक सप्रे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। इसके बावजूद उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र नहीं दिया है। दलबदल कानून के प्रकाश में उनका यह रवैया गैर कानूनी है। इसलिए सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए।

उमंग सिंघार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच प्रक्रिया जारी

ओबीसी वर्ग अधिकारों से वंचित: सिंघार

विसं, भोपाल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि राज्य में 50 प्रतिशत होने के बाद भी ओबीसी वर्ग को अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक ओर महिलाओं को वर्ष 2029 में महिला आरक्षण का सपना दिखा रही है,तो वहीं बंद कमरों में फैसले लिए जा रहे हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंघार ने समान नागरिक संहिता(यूसीसी) को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि क्या 6-7 लोगों की कमेटी मध्यप्रदेश का भविष्य तय करेगी। क्या सरकार के लिए जनता की राय कोई मायने नहीं रखती। अब तक सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यूसीसी में दलित और आदिवासी समाज को शामिल किया जाएगा या नहीं। सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ओबीसी का वोट तो चाहती है,लेकिन उन्हें उनका हक देने को तैयार नहीं है। भाजपा ओबीसी चेहरों को आगे रखकर राजनीति कर रही है,जबकि उनके अधिकारों को अदालत के पाले में डाल दिया गया है।

नरसिंहपुर बीएमओ डॉ. रिचा मिश्रा को पद से हटाया

जागरण, नरसिंहपुर। जिला अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग में उस समय हलचल मच गई, जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) डॉ. रिचा मिश्रा को अचानक उनके पद से हटा दिया गया, उनकी जगह अब डॉ. गणेश भनारिया को नया बीएमओ नियुक्त किया है। अचानक हुए इस बदलाव ने विभाग के भीतर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉ. रिचा मिश्रा पिछले करीब एक साल से इस पद पर थीं। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह फैसला उनके लिए पूरी तरह चौंकाने वाला है। डॉ. मिश्रा के मुताबिक, उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और उनके कार्यकाल के दौरान ब्लॉक की प्रगति भी अच्छी रही। उन्होंने साफ किया कि अब तक उनके खिलाफ न तो कोई शिकायत हुई थी और न ही कोई आरोप लगा था। डॉ. मिश्रा ने बताया कि एक साल के दौरान उन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा साथ मिला। ब्लॉक का काम भी बेहतर ढंग से चल रहा था, इसलिए अचानक पद से हटाया जाना उनकी समझ से बाहर है।

प्रथम पृष्ठ के शेष

बंगाल में भाजपा, केरल में

...

आए हैं और सभी ने भाजपा की वापसी का अनुमान जताया है।

यहां भाजपा गठबंधन को करीब 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस+ को लगभग 29 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य दलों के खाते में करीब 7 सीटें जा सकती हैं। यह भाजपा के लिए लगातार मजबूत जनसमर्थन का संकेत है। हालांकि एग्जिट पोल रुझान जरूर देते हैं, लेकिन ये अंतिम नतीजे नहीं होते। पिछले चुनावों में कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। ऐसे में अंतिम फैसला मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा। कुल मिलाकर, इन एग्जिट पोल के अनुसार देश के पांच राज्यों में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के संकेत हैं, जिनका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है।

बिजली उत्पादन में ग्रीन..

लेकिन अब ऐसा नहीं है। जलूद सोलर पॉवर प्लांट से दोहरा लाभ मिलेगा। इंदौर नगर निगम को बिजली तो मिलेगी ही, साथ में कार्बन उत्सर्जन भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से प्राचीन ज्ञान के आधार पर राज्य सरकार ने वैदिक घड़ी तैयार की है। पहले उज्जैन और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक घड़ी स्थापित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी स्थित बाबा विश्वनाथ धाम में सम्राट विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अवलोकन किया है। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि आज इंदौर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को ग्रीन एनर्जी का हब बनाने का संकल्प लिया है और इसी को मुख्यमंत्री डॉ. यादव आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रीन बॉन्ड से जुटाए फंड से जलूद में देश का पहला सोलर प्लांट बनकर तैयार हुआ है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि भारत ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करने वाला दुनिया का अग्रणी देश है।

सख्ती — सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज

सिंहस्थ में बगैर परीक्षा पुलिस भर्ती का दावा फर्जी

मुख्य संवाददाता, भोपाल। सोशल मीडिया पर उज्जैन सिंहस्थ को लेकर बुधवार को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि सिंहस्थ मेले के लिए पुलिस में बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती की जा रही है। इस खबर के फैलते ही युवाओं में भारी हलचल मच गई। इंस्टाग्राम पर वायरल हुई इस रील को लगभग 1.2 मिलियन व्यूज मिले और 1600 लोगों ने इसे लाइक भी किया। इस रील के वायरल होने के बाद पीएचक्यू ने देर शाम ऐसी किसी भी भर्ती को सिरे से खारिज कर दिया। डीआईजी कम्यूनिटी पुलिसिंग विनीत कपूर ने प्रेस नोट जारी कर साफ किया कि यह महज अफवाह है और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। इस रील को रिपुदमन सिंह नाम के कंटेंट क्रिएटर ने अपलोड किया था और इसमें वर्दी पहने हुए एक युवक इस संबंध में जानकारी दे रहा था।

वॉलंटियर्स की तैनाती भर्ती का हिस्सा नहीं

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि सिंहस्थ पुलिस वॉलंटियर्स का चयन किसी भी तरह की सरकारी भर्ती की श्रेणी में नहीं आता है। इन वॉलंटियर्स को केवल सामुदायिक पुलिसिंग और जनसेवा के लिए एक वॉलिंटियर के रूप में चुना जाना है। इस संबंध में भर्ती के कोई भी आधिकारिक निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जहां तक इनके मानदेय यानी सेवा के बदले मिलने वाले पैसे की बात है, तो वह भी शासन स्तर पर विचाराधीन है और उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पीएचक्यू ने युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी किसी भी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें। पीएचक्यू ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की रील बनाकर वायरल करने वाले पुलिसकर्मियों की तलाश कर उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

यह है सच्चाई, शाम को डिलीट कर दी रील

चार दिन पहले उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारी को लेकर कार्यशाला हुई थी। इसमें जिलों के पुलिस अधिकारियों को नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों के नए सिरे से गठन के निर्देश दिए गए थे। योजना यह थी कि इन समितियों के सदस्यों को सिंहस्थ के दौरान च्फोर्स मल्टीप्लायरच यानी पुलिस की मदद करने वाले स्वयंसेवकों के रूप में तैयार किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर इस पूरी कवायद को गलत तरीके से पेश कर दिया गया और इसे बगैर परीक्षा के नई पुलिस भर्ती का नाम दे दिया गया। बाद में पीएचक्यू ने जब सफाई दी, तो शाम को इस रील को डिलीट कर दिया गया।

सिंहस्थ 2028, रेल पटरियों पर होगा सुरक्षा का अचूक घेरा

भोपाल। बुधवार को पीएचक्यू में हुई एक अहम बैठक में डीजीपी कैलाश मकवाणा ने साफ कर दिया है कि सिंहस्थ के दौरान रेल सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी और इसके पुख्ता इंतजाम वक्त से काफी पहले पूरे करने होंगे। डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि इस दौरान प्रदेश से गुजरने वाले रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। रेल पटरियों को हर हाल में अवरोधमुक्त रखा जाए ताकि ट्रेनों की आवाजाही में कोई बाधा न आए। इसके बाद अब रेलवे, जीआरपी और आरपीएफ मिलकर संवेदनशील रेलवे स्टेशनों की पहचान कर वहां सुरक्षा का विशेष घेरा तैयार करेगी। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी हेतु एआई आधारित तकनीक और सीसीटीवी कैमरों के जरिए सिक्योरिटी सिस्टम को और भी आधुनिक बनाया जाएगा।

और शराफत नहीं, जल्द सुधर जाओ राष्ट्रपति ट्रंप ने दी ईरान को धमकी

तेहरान/वॉशिंगटन डीसी जेएनएन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी देते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'ईरान अपनी स्थिति सुधार नहीं पा रहा है। उन्हें नहीं पता कि गैर-परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कैसे किए जाते हैं। बेहतर होगा कि वे जल्द समझदार बन जाएं!'

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनके परमाणु कार्यक्रम पर जल्द ही कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकला, तो अमेरिका और भी सख्त रुख अपनाएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ में असॉल्ट राइफल लिए हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिस पर 'नो मोर मिस्टर नाइस गाई' का नारा लिखा था। ट्रम्प की यह टिप्पणी क्षेत्रीय तनाव और कूटनीतिक गतिरोध के बीच आई है, जो वाशिंगटन द्वारा प्रस्तावित शर्तों का विरोध जारी रहने पर तेहरान के प्रति अधिक आक्रामक नीति का संकेत देती है।

परमाणु मुद्दे के बिना नहीं बढ़ेगी बातचीत

राष्ट्रपति ने हाल ही में एक 'ट्रम्प डील' पर बातचीत के प्रयास किए हैं, जो पिछले उन समझौतों की जगह लेगी जिन्हें वे वैश्विक सुरक्षा के लिए अपर्याप्त मानते रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक परमाणु मुद्दे को सीधे तौर पर नहीं सुलझाया जाता, वाशिंगटन बातचीत आगे नहीं बढ़ाएगा।

- **यूएई ने ओपेक छोड़ा:** संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई से तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक से 59 साल बाद बाहर निकलने की ऐतिहासिक घोषणा की है। ओपेक बड़े तेल उत्पादक देशों का समूह है।
- **ट्रम्प ने पेशकश ठुकराई:** ईरान ने अमेरिका को होर्मुज खोलने और जहाजों की आवाजाही शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद परमाणु मुद्दे पर बात होनी थी, लेकिन ट्रम्प ने प्रस्ताव ठुकरा दिया।
- **तीसरी बार पाक पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री:** ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची रूस की अपनी यात्रा खत्म करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे। पिछले 48 घंटों में यह उनका तीसरा पाक दौरा है।
- **10 लाख नौकरियां खत्म:** ईरान सरकार ने बताया कि जंग की वजह से देश में सीधेतौर पर कम से कम 10 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। भविष्य में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियों का खतरा है।
- **तेल के दाम बढ़े:** मंगलवार को भी कच्चे तेल की कीमतों में लगातार सातवें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई।

हमलों के द्वीपों पर तेल फैला

ईरान ने कहा है कि अमेरिकी-इजराइली हमलों के बाद फारस की खाड़ी के मारू और लावन द्वीपों पर कच्चा तेल फैल गया है। मुंबई स्थित ईरानी मिशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमलों के कारण एक तेल डिपो में विस्फोट हुआ, कच्चा तेल द्वीपों पर फैल गया।

जंग शुरू होने के बाद ईरान में 21 लोगों को फांसी, 4 हजार गिरफ्तार

यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद ईरान में कम से कम 21 लोगों को फांसी दी गई है। 4,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक ईरान में 21 लोगों को मौत की सजा देकर फांसी दी गई। इनमें से 9 लोगों को जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में फांसी दी गई।

भोपाल प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म शहर, 25 जिलों में बारिश की संभावना, मिलेगी राहत

मौसम का बदलने वाला है मिजाज, दो दिनों में 2 डिग्री तक पारा गिरने की जताई जा रही संभावना

मुख्य संवाददाता, भोपाल। मध्य प्रदेश में भीषण तपिश झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में सूरज के कड़े तेवरों के बीच अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश में एक साथ तीन मौसमी सिस्टम सक्रिय हो गए हैं, जिसके चलते आने वाले दो दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और कई जिलों में बारिश की फुहारें पड़ने की संभावना है। हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश के कई शहर तप रहे हैं। बुधवार को सीधी जिला राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां का तापमान 43.8 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल भी इससे पीछे नहीं रही और 43.7 डिग्री तापमान के साथ यह प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म शहर बना रहा। इसके अलावा रायसेन, खजुराहो और खंडवा जैसे जिलों में भी पारा 43 डिग्री के ऊपर रहा, जिससे लोग चिलचिलाती धूप और उमस से बेहाल हैं।

वाहन चालकों को धूप से बचाने के लिए अयोध्या चौराहे पर हरी नेट लगाई गई है।

बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा में भी बूंदाबांदी

बुंदेलखंड और बघेलखंड के जिलों जैसे निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी और सिंगरौली में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मालवा और निमाड़ के कुछ हिस्सों के साथ प्रदेश के दक्षिणी जिलों में भी राहत की बूंदें गिर सकती हैं। नीमच, मंदसौर, आगर मालवा और राजगढ़ के साथ ही पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में भी मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।

कश्मीर के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, राजस्थान व उप्र में चक्रवात

मौसम विभाग के अनुसार अब इस गर्मी से राहत मिलने का समय आ गया है। पाकिस्तान और कश्मीर के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ऊपरी हवाओं का चक्रवात यानी साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ है। इन तीनों प्रणालियों के प्रभाव से मध्य प्रदेश के वातावरण में नमी आएगी और बादल छाने लगेंगे। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले दो दिनों के भीतर तापमान में 2 डिग्री तक की कमी आएगी, जिससे गर्मी का असर कम होगा। प्रदेश के लगभग 25 जिलों में बारिश और बूंदाबांदी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर-चंबल संभाग सहित मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर जैसे इलाकों में बादल बरस सकते हैं, वहीं मुरैना, भिंड और श्योपुर में भी गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है।

हमारा जहाज जब्त करना समुद्री डकैती, यूएन एक्शन ले: ईरान

ईरान ने यूएन में अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईरानी मीडिया आउटलेट तसनीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरान के दूत आमिर सईद इरावानी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में ईरान ने अमेरिकी नौसेना द्वारा उसके जहाजों को पकड़े जाने को सीधे तौर पर 'समुद्री डकैती' करार दिया है। इरावानी ने कहा कि अमेरिका अपनी घरेलू नीतियों का हवाला देकर अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, जो पूरी तरह गैर-कानूनी है। ईरानी दूत ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ा खतरा है। तसनीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इरावानी ने इसे डराने-धमकाने वाली हरकत बताया है।

परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन का उपाध्यक्ष बना ईरान

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों से पैदा हुआ पश्चिम एशिया संकट 29 अप्रैल को 61वें दिन में प्रवेश कर गया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से ईरान के पक्ष में एक अहम कूटनीतिक खबर सामने आई है। ईरान को वर्ष 2026 की परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) समीक्षा सम्मेलन का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका और इजरायल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में जुटे हैं। इसे वैश्विक मंच पर वॉशिंगटन की अलग-थलग पड़ती स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी नाटो देशों ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की सीधी मदद या भागीदारी से दूरी बनाई थी।

महाराष्ट्र में बदला नियम, अब

दोषी माननीयों को विशेष सम्मान की जरूरत नहीं

मुंबई, जेएनएन। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक नया शासन निर्णय जारी किया है। इसके तहत सरकारी

अधिकारियों को अब उन जनप्रतिनिधियों के लिए अपनी कुर्सी से खड़े होने या उन्हें विशेष सम्मान देने की जरूरत नहीं होगी, जो अपराधी घोषित हो चुके हैं या किसी अदालती/विभागीय जांच के लिए सरकारी दफ्तर पहुंचे हैं। अमेंडमेंट के मुताबिक, कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें वे मामले शामिल हैं, जब कोई विधायक या सांसद किसी आपराधिक या अन्य मामले में दोषी पाया गया हो। इसके अलावा यदि किसी जनप्रतिनिधि को किसी जांच या सुनवाई में पक्षकार के तौर पर बुलाया गया हो, तब भी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। वहीं चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं, जैसे नामांकन दाखिल करने, छंटनी या सुनवाई के लिए सरकारी कार्यालय में उपस्थित होने पर भी अधिकारियों को विशेष प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी।

फलोदी सट्टा बाजार में भी पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के संकेत

"नई दिल्ली, जेएनएन। पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजों से पहले फलोदी का सट्टा बाजार पूरी तरह गर्म है। पश्चिम बंगाल में सट्टा बाजार में इस बार ममता बनर्जी से ज्यादा भरोसा सुवेंदु अधिकारी पर जताया जा रहा है। इसका संकेत साफ है कि ममता दीदी की कुर्सी पर खतरा हो सकता है।

प. बंगाल: परिवर्तन के संकेत

भाजपा	:	146-149
टीएमसी	:	140-143
कांग्रेस +अन्य	:	एक अंक में

तमिलनाडु: डीएमके की वापसी

डीएमके	:	140-143
एआईएडीएमके	:	45-65
टीवीके	:	07-09

तमिलनाडु में एम.के.स्टालिन को बढ़त। एआईएडीएमके का ग्राफ गिरता दिख रहा है।

असम में भाजपा+ का दबदबा

एनडीए	:	98-100
एएसएम	:	23-25

हिमंत को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखा रहा है।

पुडुचेरी में कांटे की टक्कर

एनडीए	:	14-18
आईएनडीआई	:	14-17
टीवीके	:	कुछ सीटें

एन.रंगास्वामी बढ़त में दिख रहे हैं, लेकिन मुकाबला बेहद करीबी।

केरल में यूडीएफ की वापसी

यूडीएफ	:	76-78
एलडीएफ	:	62-64
एनडीए	:	18-20

फलोदी सट्टा बाजार केरल में यूडीएफ की वापसी की ओर इशारा कर रहा है।

गौरतलब है कि पांचों राज्यों के विधानसभा चुनावों के फाइनल नतीजे चुनाव आयोग द्वारा चार मई को जारी किए जाएंगे। ये सिर्फ सट्टा बाजार के अनुमान हैं।

गुना लूटकांड: 4 पुलिसकर्मी दोषी कारोबारी का इंकार, मिला अभयदान

मुख्य संवाददाता, भोपाल। गुना के बहुचर्चित कारोबारी लूट कांड के आरोप में निलंबित चारों पुलिसकर्मियों को न तो जेल जाना पड़ेगा और न ही उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई हो पाएगी। मामले की जांच पूरी हो गई है। ग्वालियर रेंज के डीआईजी अमित सांघी के द्वारा गुना पहुंचकर प्रारंभिक जांच के बाद घटनाक्रम की पड़ताल का जिम्मा शिवपुरी जिले के करैरा में पदस्थ आईपीएस अधिकारी डॉ. आयुष जाखड़ को सौंपा था। जाखड़ की रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि कथित लूट के इस मामले में न केवल चारों पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका थी बल्कि इन सभी ने जानबूझकर इस वारदात को अंजाम दिया था। प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट पीएचक्यू भेज दी है और इस केस में निलंबित सब इंस्पेक्टर, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक को चार्जशीट दे दी गई है। डीआईजी अमित सांघी के अनुसार इस मामले में किसी तरह की शिकायत न होने के कारण पहले से निलंबित चारों पुलिसकर्मियों को लापरवाही और अन्य आरोपों में चार्जशीट सौंपी गई है और विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा।

अवहेलना और लापरवाही जैसे साधारण आरोप: पिछले माह गुना जिले के धरनावदा थाना की रुठियाई पुलिस चौकी क्षेत्र में 19 मार्च की रात एनएच 46 पर वाहन चेकिंग के दौरान सूरत के जीरा व्यापारी की गाड़ी से चेकिंग के दौरान एक करोड़ रुपये मिले थे। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने 20 लाख रुपये लेकर शेष 80 लाख के साथ गाड़ी और व्यापारी को छोड़ दिया था। 20 मार्च को गुजरात के एक सीनियर आईपीएस ने भोपाल में पीएचक्यू के अधिकारी को सूचना दी। पीएचक्यू तक मामला पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों ने व्यापारी को पैसा लौटा दिया और उसे गुजरात रवाना कर दिया। उसी रात पीएचक्यू के निर्देश पर ग्वालियर डीआईजी अमित सांघी रुठियाई पहुंचे और धरनावदा थाना प्रभारी प्रभात कटारे, चौकी प्रभारी साजिद हुसैन, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिकरवार, आरक्षक सुंदर रमन को निलंबित कर दिया। इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद चारों निलंबित पुलिसकर्मियों पर नियमों का पालन न करने, सरकारी आदेशों की अवहेलना, अनैतिक आचरण जैसे साधारण आरोप लगाए गए हैं। जवाब आने के बाद विभागीय जांच में इन पर कार्रवाई को लेकर फैसला होगा।

हेट स्पीच से निपटने पहले से प्रावधान मौजूद, संसद नए नियम बनाने स्वतंत्र : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मुद्दे पर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया कि वह इस मामले में कोई नए दिशानिर्देश जारी नहीं करेगी। कोर्ट का कहना था कि मौजूदा कानूनों में पहले से ही ऐसी स्थितियों से निपटने के प्रावधान मौजूद हैं, और अगर जरूरत महसूस होती है तो संसद नए कानून बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। दरअसल, ये याचिकाएं धर्म संसदों में दिए गए विवादित भाषणों और टीवी चैनलों पर प्रसारित भड़काऊ कार्यक्रमों को लेकर दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त गाइडलाइंस तय करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। देश के विभिन्न हिस्सों ने सांप्रदायिक आधार पर होने वाली भड़काऊ बयानबाजी (हेट स्पीच) से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से कोई आदेश पास करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान पहले से है , दिक्कत कानून की नहीं, इसके अमल न को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैसे भी नया कानून बनाना केवल संसद/विधायिका का काम है। अदालत कानून की व्याख्या कर सकती है, लेकिन वह सरकार को नया कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।

किंग चार्ल्स का ट्रंप पर तंज-हम न होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते

वॉशिंगटन डीसी, जेएनएन। किंग चार्ल्स अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार रात व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ स्टेट डिनर में हिस्सा लिया। किंग चार्ल्स तृतीय ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प पर हल्के-फुल्के अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश न होते तो आज अमेरिकी फ्रेंच बोल रहे होते। चार्ल्स ने कहा- आपने हाल ही में कहा था कि अगर अमेरिका नहीं होता तो यूरोपीय देश जर्मन बोल रहे होते। तो मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि अगर हम (ब्रिटिश) नहीं होते तो आप लोग फ्रेंच बोल रहे होते। करीब 250 साल पहले जब अमेरिका आजाद नहीं था, तब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों वहां अपनी-अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हुई कि उत्तरी अमेरिका पर किसका कब्जा रहेगा। आखिर में इस लड़ाई में ब्रिटेन जीत गया। किंग चार्ल्स का इशारा इसी तरफ था।

ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर कसा था तंज

इससे पहले जनवरी में दावोस समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प ने यूरोपीय देशों और उनके सहयोग को लेकर एक बयान दिया था। ट्रम्प ने कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध में अगर अमेरिका ने बड़ी भूमिका न निभाई होती तो आज यूरोप का नक्शा और वहां की भाषा दोनों अलग होते। उनके मुताबिक उस समय जर्मनी और जापान काफी ताकतवर थे। अगर उन्हें रोका नहीं जाता तो वे कई देशों पर कब्जा कर सकते थे। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा, 'अगर अमेरिका मदद के लिए नहीं आता तो आज आप लोग जर्मन और थोड़ा जापानी बोल रहे होते।'

साड़ी में नजर आईं पॉप सिंगर रिहाना

पॉप सिंगर रिहाना ने अपने मुंबई दौरे के बाद भारतीय साड़ी में फोटो शूट कराया है। रिहाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे ग्रीन और पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई हैं। इस देसी लुक साथ उन्होंने डायमंड और एमराल्ड (पन्ना) की हैवी ज्वेलरी भी पहनी है। वीडियो में रिहाना साड़ी पहनकर खुशी से पोज देती नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी ज्वेलरी को भी वीडियो में खास तौर पर फ्लॉन्ट किया है। रिहाना के इस लुक पर फैंस सोशल मीडिया पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा पारंपरिक साड़ी और ज्वेलरी में रिहाना को देखना किसी सपने जैसा है, वे वाकई काफी सुंदर लग रही हैं। अंबानी के घर भी पहुंची थीं रिहाना रिहाना हाल ही में अपने ब्यूटी ब्रांड के एक प्रमोशनल इवेंट के सिलसिले में मुंबई आई थीं। यहां उन्होंने एक पॉप-अप स्टोर लॉन्च और एक प्राइवेट इवेंट में हिस्सा लिया। रिहाना प्राइवेट जेट से मुंबई पहुंचीं। इस दौरान वे रविवार को मुकेश अंबानी के घर 'एंटीलिया' भी गईं। अंबानी परिवार ने रिहाना का स्वागत बिल्कुल देसी अंदाज में किया। रिहाना ने परिवार के साथ खास लंच किया और घर के सदस्यों के साथ डांस करती भी नजर आईं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को नोटिस

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कानूनी कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ईडी की उस अपील पर जारी हुआ है जिसमें निचली अदालत ने केजरीवाल को बरी किए जाने को चुनौती दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले भेजा गया नोटिस अभी तक तामील नहीं हुआ है, जिसके चलते दोबारा जवाब मांगा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि रजिस्ट्री के रिकॉर्ड के अनुसार, केजरीवाल को पहले जारी किया गया नोटिस अब तक सर्व नहीं हो सका है। इस स्थिति को देखते हुए अदालत ने एक बार फिर उन्हें नोटिस जारी कर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

उद्योग की मांग के अनुसार ट्रेड्स का प्रशिक्षण देकर प्लेसमेंट कराना सुनिश्चित करें : टेटवाल

अधिकाधिक युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही अवसर मिल सकें। विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मंत्री श्री टेटवाल ने हॉस्टल सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन, जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहयोग उपलब्ध कराने तथा ड्रॉपआउट युवाओं को पुनः प्रशिक्षण से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने आईटीआई में बेटियों के प्रवेश को बढ़ावा देने और उनके लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया।

मंत्री श्री टेटवाल ने कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री से भेंट का अवसर दिया जाएगा, जिससे युवाओं में प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी। मंत्री श्री टेटवाल ने कार्यक्रम में पहुंचे विद्यार्थियों का मिठाई खिलाकर स्वागत किया और उन्हें आईटीआई से जुड़कर अपने भविष्य को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। बैठक में डायरेक्टर बसंत कुर्रे और सीईओ गिरीश शर्मा ने जानकारी दी कि विगत वर्ष आई टी आई में 96.4 प्रतिशत सीटों पर विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ था। इस वर्ष सीटों की संख्या बढ़ाकर उन पर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें प्रशिक्षण शुल्क प्लेसमेंट के बाद लिया जाना, फीस की किस्तों में भुगतान की सुविधा तथा विभिन्न प्रकार के अनुदान शामिल हैं। ग्लोबल स्किल पार्क में 13 राज्यों के बच्चे भी विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण ले रहे हैं। जल्दी ग्लोबल स्किल पार्क में कट सिस्को और द्रोण का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि ड्रॉपआउट, दिव्यांग एवं अनाथ आश्रम के बच्चों को भी आईटीआई में पंजीयन कराकर कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे रोजगार के अवसरों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। मंत्री श्री टेटवाल ने आईटीआई के प्रतिभावान प्रशिक्षणार्थियों की सफलता की कहानियों पर आधारित फिल्म का विमोचन किया। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में बालिकाओं की सफलता पर आधारित ग्लोबल स्किल्स पार्क द्वारा निर्मित फिल्म का अवलोकन किया। इसके बाद उन प्रशिक्षणार्थियों की प्रेरणादायक फिल्म प्रदर्शित की गई जो प्रशिक्षण के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं।

मंत्री श्री टेटवाल ने 'आईटीआई चले हम' प्रवेश 2026 का किया शुभारंभ

भोपाल। कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल ने 'आईटीआई चले हम' प्रवेश 2026 अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रदेशभर में कौशल आधारित शिक्षा को जन-आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया। मंत्री श्री टेटवाल ने इस अवसर पर आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न जिलों के आईटीआई संस्थानों की प्रगति, प्रशिक्षण व्यवस्था, प्लेसमेंट और विद्यार्थियों की सहभागिता का समग्र मूल्यांकन किया। मंत्री श्री टेटवाल ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल प्रवेश प्रक्रिया नहीं, बल्कि युवाओं को कौशल, आत्मनिर्भरता और रोजगार से जोड़ने का व्यापक प्रयास है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आईटीआई संस्थानों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए तथा प्राचार्यों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार हो सके। समीक्षा के दौरान प्लेसमेंट की स्थिति पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्री श्री टेटवाल ने कहा कि उद्योगों की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रमों को अद्यतन किया जाए और प्रशिक्षण को पूरी तरह प्रैक्टिकल एवं जॉब-ओरिएंटेड बनाया जाए। मैन्युफै. रिंग, टेक्सटाइल, ब्यूटी पार्लर, फूड प्रोसेसिंग सहित अन्य उभरते सेक्टर्स में रोजगारोन्मुख कोर्सेस को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए, जिससे

चेतावनी चौंकाने वाला खुलासा: इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है एआई

एआई हम सबकी जान ले सकता है: एलन मस्क

नई दिल्ली, जेएनएन। कैलिफोर्निया की अदालत में एआई के भविष्य को लेकर गंभीर चेतावनियां दी है। उनका कहना है कि एआई या तो इंसानियत का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है या फिर उसके लिए सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। ओपन एआई के साथ चल रहे कानूनी लड़ाई के दौरान गवाही देते हुए टेस्ला और स्पेस-एक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह हमें किस दिशा में ले जा रही है। आधुनिक एआई सिस्टम के बारे में बात करते हुए मस्क ने अदालत से कहा कि यह हम सभी की जान ले सकता है। इतना ही नहीं, मस्क ने आगे ये भी कहा कि इंसानियत को टर्मिनेटर फिल्म जैसे किसी बुरे भविष्य से बचना चाहिए और इसके बजाय स्टार ट्रेक से प्रेरित होकर अच्छी उम्मीदों से भरे भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए।

हमें नहीं चाहिए टर्मिनेटर जैसे नतीजे: मस्क

एक रिपोर्ट के अनुसार, मस्क का कहना है कि हम टर्मिनेटर (साइंस-फिक्शन फिल्म) जैसा नतीजा नहीं चाहते। हम जीन रॉडेनबेरी जैसा नतीजा चाहते हैं, जैसा कि स्टार ट्रेक (पॉपुलर साइंस-फिक्शन सीरीज) में होता है। जेम्स कैमरन की फिल्म टर्मिनेटर जैसा बिल्कुल नहीं। बता दें कि मस्क ने ये बातें हाई-स्टेक्स मुकदमे के दौरान कहीं हैं। दरअसल, मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। मस्क का दावा है कि ओपन एआई अपने मूल नॉन-प्रॉफिट मिशन से भटक गई है, जिसका मकसद इंसानियत की भलाई के लिए एआई बनाना था और इसके बजाय वह कमर्शियल सफलता की ओर मुड़ गई है। ओपन एआई ने इन दावों को खारिज कर दिया है।

जोखिम को किया जा रहा नजरअंदाज

अपनी गवाही के दौरान एलन मस्क ने कहा कि एआई को लेकर उनके डर नए नहीं हैं। ये डर 2015 की गर्मियों में गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज के साथ हुई एक बातचीत से जुड़े हैं। पेज का मानना था कि एआई एक तरह का आदर्श समाज बनाएगा। मस्क ने इस जवाब ने उन्हें चिंतित कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे जुड़े जोखिमों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

इंसान सीधे बुद्धिमान मशीनों से जुड़ें

मस्क की गवाही में कानूनी दलीलों के साथ-साथ भविष्य को लेकर उनकी बड़ी सोच की झलक भी दिख रही थी। मस्क ने न्यूरालिंक के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इसका एक मकसद एआई की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर इंसान सीधे तौर पर बुद्धिमान मशीनों से जुड़ पाएं, तो इससे लोगों और एआई के बीच एक बेहतर संतुलन बन सकता है।

इंसान के तालमेल से होगा फायदा

मस्क ने कहा कि अगर एआई और इंसान के बीच तालमेल बिठा पाएंगे, तो ऐसा एआई बना सकते हैं जो पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद हो। मस्क की इन बातों को देखकर साफ लग रहा है कि एआई के भविष्य को लेकर काफी सावधान होने की जरूरत है ताकि एआई इंसानों के लिए खतरा नहीं बल्कि बरदान बन सके।

मैच 41: सनराइजर्स ने 244 रन का लक्ष्य 18.4 ओवर में हासिल किया, मुंबई को 6 विकेट से हराया

सनराइजर्स ने चेज किया चौथा सबसे बड़ा लक्ष्य मुंबई इंडियंस को हराकर लगाया जीत का 'पंजा'

जेएनएन, मुंबई

ट्रेविड हेड और हेनरिक क्लासेन के तूफानी अर्धशतक से सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के 41वें मैच में बुधवार को सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन के शतक पर पानी फेरते हुए मुंबई इंडियंस को छह विकेट से हराकर लगातार पांचवीं जीत दर्ज की। इस जीत से सनराइजर्स की टीम नौ मैच में 12 अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। मुंबई की टीम आठ मैच में चार अंक के साथ नौवें स्थान पर है। मुंबई के 244 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स ने हेड (76 रन, 30 गेंद) और अभिषेक शर्मा (45 रन, 24 गेंद) के बीच पहले विकेट की 8.4 ओवर में 129 रन की साझेदारी के बाद क्लासेन (नाबाद 65 रन, 30 गेंद) के अर्धशतक से 18.4 ओवर में चार विकेट पर 249 रन बनाकर जीत दर्ज की। यह आईपीएल का चौथा सबसे सफल चेज भी है। क्लासेन ने नीतीश कुमार रेड्डी (21) के साथ चौथे विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी भी की। सलील अरोड़ा ने अंत में 10 गेंद में नाबाद 30 रन बनाए।

रिकेल्टन ने इससे पहले अपने करियर और मुंबई के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 55 गेंद में नाबाद 123 रन बनाए, जिससे मुंबई ने पांच विकेट पर 243 रन का स्कोर खड़ा किया। रिकेल्टन ने विल जैक्स (46) के साथ पहले विकेट के लिए 93, नमन धीर (22) के साथ तीसरे विकेट के लिए 55 और कप्तान हार्दिक पंड्या (31) के साथ चौथे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी भी की।

स्कोर बोर्ड

मुंबई इंडियंसः 243/5 (20 ओवर)

	रन	गेंद	4	6
विल जैक्स का. इशान बो. नीतीश	46	22	5	3
रियान रिकल्टन नाबाद	123	55	10	8
सूर्यकुमार का. अभिषेक बो. मलिंगा	5	5	1	0
नमन धीर का. हर्ष बो. हिंगे	22	17	3	0
हार्दिक का. क्लासेन बो. साकिब	31	15	2	2
तिलक वर्मा का. क्लासेन बो. हिंगे	7	5	0	1
रॉबिन मिंज नाबाद	1	1	0	0

अतिरिक्तः 8, **कुलः** 20 ओवर में पांच विकेट पर 243 रन, **विकेट पतनः** 1-93, 2-110, 3-165, 4-221, 5-231, **गेंदबाजीः** पैट कमिंस 4-0-39-0, प्रफल हिंगे 4-0-54-2, इशान मलिंगा 4-0-29-1, हर्ष दुबे 3-0-50-0, साकिब हुसैन 3-0-39-1, नीतीश रेड्डी 2-0-31-1.

सनराइजर्स हैदराबादः 249/4 (18.4 ओवर)

	रन	गेंद	4	6
अभिषेक बो. बोल्ट बो. गजनफर	45	24	4	3
ट्रेविस हेड का. जैक्स बो. हार्दिक	76	30	4	8
इशान किशन बो. गजनफर	0	1	0	0
हेनरिक क्लासेन नाबाद	65	30	7	4
नीतीश का. सूर्यकुमार बो. बोल्ट	21	17	3	0
सलील अरोड़ा नाबाद	30	10	2	3

अतिरिक्तः 12, **कुलः** 18.4 ओवर में चार विकेट पर 249 रन, **विकेट पतनः** 1-129, 2-129, 3-133, 4-213, **गेंदबाजीः** ट्रेंट बोल्ट 4-0-41-1, बुमराह 4-0-54-0, विल जैक्स 1-0-19-0, एएम गजनफर 4-0-51-2, अश्वनी कुमार 2-0-41-0, हार्दिक पंड्या 3.4-0-39-1.

पिछली हार का बदला लेने उतरेगी गुजरात

अहमदाबाद, जेएनएन। निरंतरता हासिल करने के लिए बेताब गुजरात टाइटंस को गुरुवार को आईपीएल के 42वें मैच में शानदार फॉर्म में चल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब जबकि टूर्नामेंट का आधा चरण पूरा हो चुका है, तब गुजरात की टीम आठ मैचों में चार जीत और चार हार के साथ अंक तालिका में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है। दूसरी तरफ मौजूदा चैंपियन आरसीबी शानदार फॉर्म में है और उसने आठ मैचों में से छह में जीत दर्ज की है। आरसीबी अभी अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। इन दोनों टीम के बीच पिछले सप्ताह चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेला गया था, जिसमें आरसीबी ने 206 रन का लक्ष्य सात गेंद शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया था। गुजरात की टीम अभी तक अपने घरेलू मैदान पर दबदबा बनाने में नाकाम रही है।

चैंपियंस लीग में गोल की बारिश, पीएसजी ने सेमीफाइनल का पहला चरण 5-4 से जीता

जेएनएन, पेरिस

मौजूदा चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने शुरू में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके चैंपियंस लीग फुटबाल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले चरण में बायर्न म्यूनिख पर 5-4 से रोमांचक जीत हासिल की। चैंपियंस लीग के किसी सेमीफाइनल मुकाबले में यह सर्वाधिक गोल का नया रिकॉर्ड है। सेमीफाइनल का दूसरा चरण अगले सप्ताह खेला जाएगा। बायर्न की तरफ से हैरी केन ने 17वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन पीएसजी ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही 5-2 की बढ़त बना ली, जिसमें तेजतर्रार विंगर ख्विचा क्वारात्सखेलिया (24वें और 56वें मिनट) और औस्मान डेम्बेले (45वें और 58वें मिनट) ने दो-दो गोल किए। पीएसजी के लिए जोआओ नेवेस ने भी 33वें मिनट में गोल किया था। बायर्न की तरफ से केन के अलावा माइकल ओलिस (41वें), डेयोत उपामाकानो (65वें) और लुई डियाज (68वें मिनट) ने गोल दागे। बायर्न को 24 जनवरी के बाद किसी भी प्रतियोगिता में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। बायर्न म्यूनिख के मुख्य कोच विन्सेंट कोम्पनी निलंबित थे और स्टैंड से मैच देख रहे थे, इसलिए सहायक कोच आरोन डैंक्स ने कमान संभाली। यह पीएसजी की चैंपियंस लीग में 100वीं जीत थी। पीएसजी ऐसा करने वाला पहला फ्रेंच क्लब बना। लुइस एनरिक के कोचिंग करियर की 50वीं चैंपियंस लीग जीत है।

> हम जीतने के हकदार थे, हम हारने के हकदार थे, हम ड्रॉ के हकदार थे। यह एक असाधारण मैच था। मैंने कोच रहते हुए कभी इतना जबरदस्त मैच नहीं देखा। मैंने कभी ऐसा कड़ा मैच नहीं देखा। यह अविश्वसनीय था। सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं।
>
> **- लुइस एनरिक**, कोच, पीएसजी

आयुष शेट्टी और एचएस प्रणय जीते, लेकिन भारत थॉमस कप फाइनल में चीन से हारा

होर्सेंस (डेनमार्क), जेएनएन। आयुष शेट्टी और एचएस प्रणय ने बुधवार को जीत दर्ज की, लेकिन भारत थॉमस कप फाइनल के अंतिम ग्रुप-ए मुकाबले में चीन से 2-3 से हार गया। 2022 के चैंपियन भारत ने पहले ही क्वार्टरफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन लक्ष्य सेन और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी के करीबी मुकाबले में हारने से भारत बैकफुट पर आ गया था, जिससे चीन को 2-0 से बढ़त मिल गई थी। दबाव भरे हालात में आयुष ने शानदार प्रदर्शन किया और एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए वेंग होंग यांग को दूसरे एकल में 17-21, 21-13, 21-15 से हराकर अंतर कम किया। दूसरे युगल मैच में हरिहरन अमसकारुन्नन और एमआर अर्जुन की जोड़ी को ही जी टिंग और रेन जियांग यू से 17-21, 13-21 से हार मिली, जिससे चीन ने 3-1 की अजेय बढ़त बना ली।

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, एवं पुनर्वास अनुभाग-सिरमौर जिला-रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 101 भू-अर्जन/कार्य/2026 सिरमौर, दिनांक 21/4/2026

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए। अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग-सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-भरूहिया पटवारी हल्का-भटिगवां तहसील-सेमरिया जिला-रीवा	142/1/2	0.894	0.032
2		142/2	0.890	
3		143/1	0.634	0.014
4		143/2	0.159	
5		144/1	0.247	0.01
6		144/2	0.405	
7		145	0.267	0.007
8		148	0.789	0.002
9		147	0.295	0.01
10		134	0.142	0.002
11		133	3.035	0.05
12		122	0.202	0.002
13		128/1	0.159	
14		128/2	0.159	0.017
15		128/3	0.159	
16		128/4	0.159	
17		126/1	0.077	0.002
18		126/2	0.016	
19		125/1/1/1	0.065	
20		125/1/1/2	0.065	
21		125/1/1/3	0.068	
22		125/1/1/4	0.065	0.012
23		125/1/1/5	0.065	
24		125/1/2/1	0.163	
25		125/1/2/2	0.162	
26		125/2	0.129	
	(अ) निजी भूमि का योग-	26 किता	9.470	0.160
1		139	0.587	0.004
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.587	0.004
	अ+ब का योग-	कुल 27 किता	10.057	0.164

अनुविभागीय अधिकारी, अपर सी.डब्ल्यू.सी. उप संभाग क्र.-3 गोविंदगढ रीवा (म.प्र.) | कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म.प्र.) | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग सिरमौर जिला-रीवा (म.प्र.)

G-12154/26

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, एवं पुनर्वास अनुभाग-सिरमौर जिला-रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 94 भू-अर्जन/कार्य/2026 सिरमौर, दिनांक 21/04/2026

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए। अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग-सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	4	5	6
1	ग्राम-चवाई पटवारी हल्का- चवाई तहसील-सेमरिया जिला-रीवा	1179/1	0.299	
2		1179/2/1	0.051	
3		1179/2/2	0.051	
4		1179/3/1	0.318	
5		1179/3/2	0.121	
6		1179/4/1	0.142	
7		1179/4/2/1/1	0.045	
8		1179/4/2/1/2	0.218	0.048
9		1179/4/2/2	0.215	
10		1179/5/1	0.187	
11		1179/5/2	0.242	
12		1179/6	0.178	
13		1179/7	0.364	
14		1179/8	0.445	
15		1179/9	0.202	
16		1175	1.107	0.041
17		1174/1/1	0.082	
18		1174/1/2	0.082	
19		1174/1/3	0.082	
20		1174/1/4	0.083	0.024
21		1174/2/1	0.110	
22		1174/2/2	0.110	
23		1174/2/3	0.111	
24		1169	0.470	0.020
25		1159/1/1	0.133	
26		1159/1/2	0.125	
27		1159/1/3	0.064	0.014
28		1159/2/1	0.130	
29		1159/2/2	0.194	
30		1155/1	0.077	
31		1155/2	0.081	0.004
32		1155/3	0.077	
33		1156	0.028	0.005
34		1157/1	0.214	0.006
35		1157/2	0.182	
36		936/1/1/1	0.244	
37		936/1/1/2	0.243	
38		936/1/2	0.121	0.025
39		936/1/3	0.121	
40		936/2	0.089	
41		937/1	0.048	0.003
42		937/2	0.049	
43		941/1/1/1	0.555	
44		941/1/1/2	0.194	
45		941/1/2	0.607	0.038
46		941/2/1	0.101	
47		941/2/2	0.101	
48		942/1	0.040	0.001
49		942/2	0.040	
50		942/3	0.040	
51		942/4	0.012	
52		942/5	0.016	
53		942/6	0.016	
54		947/1	0.906	
55		947/2	0.902	
56		947/3	0.906	
57		947/4	0.129	
58		947/5/1	0.194	0.054
59		947/5/2	0.195	
60		947/6	0.389	
61		947/7/1	0.453	
62		947/7/2	0.453	
63		947/8	0.902	
64		917	0.251	0.012
65		919/1	0.486	0.008
66		919/2	0.190	
67		887	0.680	0.034
68		888/1	0.158	0.003
69		888/2	0.158	
70		886/1	0.231	
71		886/2/1	0.295	
72		886/2/2	0.296	0.027
73		886/3	0.210	
74		886/4	0.214	
75		886/5	0.214	
76		821/1/1	0.502	
77		821/1/2	0.061	0.018
78		821/2	0.040	
79		820/1	0.878	0.032
80		824/1/1	0.377	0.032
81		824/1/2	0.376	
82		824/2	0.750	
83		824/3/1/1	0.995	
84		824/3/1/2	0.060	
85		824/3/1/3	0.060	
86		824/3/1/4	0.016	
87		824/3/1/5	0.060	
88		824/3/2	0.032	
89		824/3/3	0.028	
90		824/3/4	0.032	
91		824/4	0.632	
92		825	0.287	0.004
93		816/1/1/1	0.220	
94		816/1/1/2	0.020	
95		816/1/1/3	0.241	
96		816/1/2	0.457	0.070
97		816/1/3	0.482	
98		816/2	1.434	
99		816/3	1.963	
100		816/4	0.049	
101		74/1/1/1	0.888	
102		74/1/1/2	2.269	
103		74/1/2	0.526	0.060
104		74/2/1	1.701	
105		74/2/2	2.504	
106		74/3	0.526	
107		94/1/1	0.936	
108		94/1/2	0.467	
109		94/2/1	0.700	0.059
110		94/2/2	0.234	
111		94/3	0.955	
112		93	3.197	0.031
113		92	1.238	0.036
114		123/1	0.166	0.010
115		123/2	0.162	
116		125	0.829	0.035
117		126	0.454	0.003
118		127	4.904	0.011
119		153	3.840	0.053
120		152/1/1/1	0.811	
121		152/1/1/2	0.200	
122		152/1/1/3	0.200	
123		152/1/2	0.668	
124		152/1/3/1	0.007	
125		152/1/3/2	0.012	
126		152/1/3/3	0.012	0.040
127		152/1/3/4	0.012	
128		152/1/3/5	0.012	
129		152/1/3/6	0.390	
130		152/1/4	0.678	
131		152/2	0.445	
132		152/3	0.445	
133		152/4	0.103	
134		154/1/1/1	0.128	
135		154/1/1/2	0.127	
136		154/1/2/1	0.129	0.009
137		154/1/2/2	0.129	
138		154/2/1	0.321	
139		154/2/2	0.193	
140		158/1/1/1	0.801	
141		158/1/1/2	0.848	
142		158/1/1/3	0.848	
143		158/1/2/1	0.343	0.033
144		158/1/2/2	0.377	
145		158/1/3/1	0.277	
146		158/1/3/2	0.274	
147		158/1/3/3	0.274	
148		158/1/3/4	0.274	
149		158/1/3/5	0.162	
150		158/1/4/1	0.382	
151		158/1/4/2	0.129	
152		158/1/4/3	0.547	
153		158/1/4/4	0.446	
154		158/1/5/1	0.430	
155		158/1/5/2	0.426	
156		158/1/5/3	0.405	
157		158/2	1.261	
158		160/1/1/1	0.556	
159		160/1/1/2	0.556	
160		160/1/1/3	0.557	
161		160/1/2	0.841	0.078
162		160/1/3	0.837	
163		160/1/4/1	0.449	
164		160/1/4/2	0.448	
165		160/2	0.821	
166		1991/1/1/160/1/1	0.020	
167		1991/1/1/160/1/2	0.331	
168		1991/1/1/160/1/3	0.352	
169		1991/1/1/160/1/4/1	0.176	
170		1991/1/1/160/1/4/2	0.019	0.027
171		1991/1/1/160/1/4/3	0.019	
172		1991/1/1/160/1/5	0.352	
173		1991/1/1/160/2	1.406	
174		1991/2/160	1.405	
175		175/1	2.096	0.006
176		175/2	2.096	
177		174/1/1	0.487	0.039
178		174/1/2	0.974	
179		174/2	0.219	
180		170/1	12.805	0.028
181		170/2/1	0.505	
182		170/2/2	0.505	
183		170/2/3	0.505	
184		170/2/4	0.510	
185		170/2/5	0.520	
186		170/2/6	1.000	
187		173/1/1	1.307	
188		173/1/2	0.036	
189		173/2/1	1.299	
190		173/2/2	0.044	0.016
191		173/3/1	0.818	
192		173/3/2	0.048	
193		173/4	0.482	
	(अ) निजी भूमि का योग-	193 किता	103.544	1.097
1		1180	0.019	0.019
2		935	0.003	0.003
3		817	0.013	0.013
4		148	0.007	0.007
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता	0.042	0.042
	अ + ब का योग-	कुल 197 किता	103.586	1.139

अनुविभागीय अधिकारी, अपर सी0डब्ल्यू0सी0 उप संभाग क्र.-3 गोविंदगढ रीवा (म.प्र.) | कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म.प्र.) | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग सिरमौर जिला-रीवा (म.प्र.)

G- 12171/26

सड़क में पन्नी लगाकर दुकान सजाने वालों पर प्रशासन नहीं करता कार्यवाई

वाहन निकलने के लिए नहीं बचती जगह हनुमना बाजार में अतिक्रमण से आमजन परेशान

हनुमना, नि.प्र.। मऊगंज जिले के हनुमना नगर में समस्त नगरीय जनता एवं ग्रामीण जनता परेशान हो चुकी है। नगर के विभिन्न बाजार के मार्ग संकरें हो चुके हैं। अतिक्रमणकारियों इतने प्रभावशाली हो चुके हैं कि सड़क पर पन्नी छाकर स्थान घेर लेते हैं और अपनी दुकान सड़क पर लगा लिए हैं। जय गुप्ता ने आगे कहा कि आखिर नगर के यह ग्रामीण जनता को अगर बाजार में कुछ सामान क्रय एवं विक्रय करना है तो वह अपने मोटरसाइकिल फोर व्हीलर कहां पर सुरक्षित खड़ी करें, कहीं पर जगह नहीं मिलती। केवल और केवल दुकानदारों से अभद्र गलियां मिलती हैं जिस कारण से हनुमना बाजार अब प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लोग बाजार में आने में कतराते हैं। अतिक्रमण की खबरें समाचार में प्रकाशित होने के बाद स्थानीय अधिकारियों द्वारा खाना पूर्ति की कार्यवाही करते हुए फोटो खिंचवाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जैसे ही अधिकारी थोड़ी ढील बरतते हैं।

नगर वासी नगर उपाध्यक्ष प्रतिनिधि जय गुप्ता वार्ड क्रमांक 10 प्रतिनिधि गुड्डा ग, रितेश केसरी, वाहन कर्मचारी संघ अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता, पूर्व उपाध्यक्ष भरत लाल गुप्ता, विपिन मोबाइल सेंटर आज नगर के सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्टर मऊगंज, अनुविभागीय अधिकारी हनुमना मुख्य नगर पालिका अधिकारी हनुमना यातायात प्रभारी मऊगंज हनुमना से आम जनता की यह मांग है कि विभिन्न गलियों को शख्ती के साथ की कार्रवाई की जाए।

अंगूठा लगवाकर गरीबों का अनाज हड़प रहा कोटेदार

गढ़ी गांव में कोटेदार पर महिलाओं से अभद्रता के आरोप, प्रशासन मौन

त्योंथर ब्यूरो। त्यौंथर तहसील अंतर्गत गढ़ी ग्राम सभा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खुलेआम लूट के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए संवाददाता को बताया कि कोटेदार राजेन्द्र शर्मा द्वारा हर महीने पात्र हितग्राहियों से अंगूठा लगवाने के बावजूद अनाज वितरित नहीं किया जाता, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने संवाददाता को बताते हुए कहा कि जब महिलाएं और बुजुर्ग अपने हक का राशन मांगने जाते हैं तो कोटेदार राजेन्द्र शर्मा व उसका बेटा शालू धमकाते हुए कहते हैं कि जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, जहां जाना हो चले जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ राशन की लूट नहीं बल्कि गरीबों के अधिकारों का खुला उल्लंघन है। कुछ महिलाओं ने संवाददाता को बताया कि कोटेदार का बेटा महिलाओं से अभद्र और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता है, जिससे गांव की महिलाएं भयभीत हैं। पीड़ित महिलाओं में दुर्गावती कुशवाहा, प्रेमकली सहित अन्य ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। लोगों ने संवाददाता को बताते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी की वजह से यह अनियमितताएं की जा रही हैं। लोगों ने कहा कि अंगूठा लगने के बाद राशन न देना सीधे तौर पर बायोमेट्रिक धोखाधड़ी, शासकीय संपत्ति के गबन और महिला उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। ग्रामीणों की मांग है कि कोटेदार राजेन्द्र शर्मा का कोटा तत्काल निरस्त किया जाए, जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच हो तथा महिलाओं से अभद्रता और धमकी देने के मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि ग्राम सभा में महिलाओं की इज्जत और गरीबों का हक सुरक्षित रह सके।

कटरा-मऊगंज मुख्य मार्ग पर शराब दुकान से बढ़ रहा खतरा

हादसे और अराजकता चरम पर

मऊगंज। जिले के कटरा-मऊगंज मुख्य मार्ग पर स्थित शराब दुकान अब आम लोगों के लिए गंभीर परेशानी और खतरे का कारण बनती जा रही है। यह मार्ग प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ होते हुए देश के प्रमुख शहरों दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता है, जहां हर दिन भारी यातायात बना रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्य सड़क किनारे संचालित शराब दुकान के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है। शराब लेने आने वाले लोग सड़क पर ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि इस मार्ग पर कई सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड संबंधित थाने में मौजूद है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि बिना नंबर की गाड़ियां और संदिग्ध लोग अक्सर दुकान के आसपास खड़े रहते हैं, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ठेकेदार के कथित गुर्गों और रसूखदार व्यक्तियों के संरक्षण में यहां अराजकता फैल रही है। हाल ही में एक वन विभाग से जुड़े अधिकारी के परिजनों के साथ मारपीट की घटना ने मामले को और गंभीर बना दिया है। इसके बाद से रामपुर क्षेत्र के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

कमिश्नर ने कार्यपालन यंत्री संजय पाण्डेय को दिया कारण बताओ नोटिस

मऊगंज जागरण। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संजय पाण्डेय को विकासखण्ड नईगढ़ी अन्तर्गत ग्राम खटखरी में गतदिनों टंकी ध्वस्त होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कमिश्नर ने अपने नोटिस में कहा है कि पुनरीक्षित लागत 121.42 लाख रुपये से बनाई गयी टंकी की गुणवत्ता ठीक न होने पर मौके की जांच कराई गयी। टंकी का निर्माण वर्ष 2021-22 से प्रारंभ होकर वर्ष 2024 में पूर्ण हुआ। गत 27 मार्च को यह टंकी पूर्णतः ध्वस्त हो गई। कार्यपालन यंत्री द्वारा टंकी के निर्माण कार्य के दौरान अपेक्षित निगरानी एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गयी जिससे टंकी परीक्षण के दौरान ध्वस्त हो गई और शासन को आर्थिक क्षति के साथ जल जीवन मिशन की महत्वाकांक्षी योजना प्रभावित हुई। उन्होंने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता व कर्तव्यहीनता बरतने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यपालन यंत्री से सात दिवस में जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

किसानों को नहीं मिल रही बिजली, सिर्फ थमाए जा रहे बिल

तीन माह से बिजली संकट पर कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी

गोविन्दगढ़ ब्यूरो। टीकर सब स्टेशन से सप्लाई की जाने वाली बिजली पिछले 3 महीने से कटौती का शिकार हो रही है। क्षेत्र में पिछले तीन महीनों से लगातार बिजली कटौती ने किसानों और आम जनजीवन को गंभीर संकट में डाल दिया है। किसानों का आरोप है कि उन्हें नियमित बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही, जबकि हर महीने बिजली बिल जरूर थमा दिया जा रहा है। इस समस्या को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस कमेटी ग्रामीण महामंत्री पं. सुखसागर प्रसाद शुक्ल ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब किसानों को बिजली मिल ही नहीं रही, तो वे बिल का भुगतान क्यों करें। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए वन विभाग भी जिम्मेदार है, इसलिए बिजली बिल का भुगतान वन विभाग को करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में हाथियों के लगातार मूवमेंट के चलते वन विभाग, बिजली विभाग से अनुमति लेकर रात-रात भर बिजली कटौती करवा रहा है। इसका सीधा असर किसानों की फसलों पर पड़ रहा है, क्योंकि सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। इससे फसलें सूखने की कगार पर हैं और किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। इधर, हाथियों के आतंक से पहले ही ग्रामीण भयभीत हैं, वहीं बिजली कटौती ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ जान का खतरा है, तो दूसरी तरफ खेती भी प्रभावित हो रही है।

कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी

पं. सुखसागर प्रसाद शुक्ल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही बिजली आपूर्ति सुचारु नहीं की गई और किसानों को राहत नहीं दी गई, तो कांग्रेस कमेटी द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग, वन विभाग और शासन-प्रशासन की होगी।

प्रशासन की चुप्पी,जिम्मेदार मौन

मामले में अब तक बिजली विभाग और वन विभाग की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर प्रशासनिक समन्वय और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां एक ओर वन्यजीवों का खतरा है, तो दूसरी ओर बुनियादी सुविधाओं का संकट गहराता जा रहा है।

मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक रघुराजगढ़ में ग्राहकों को नहीं मिल रहा कैश

मनिकवार, नि.प्र.। क्षेत्र के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की रघुराजगढ़ शाखा में पिछले कई दिनों से खाताधारकों को नकद राशि नहीं मिलने के कारण लोगों में भारी नाराज़गी देखी जा रही है। संवाददाता को हितधारकों ने बताया कि 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लगातार ग्राहक बैंक के संपर्क में रहे, लेकिन उन्हें कैश उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राहकों का आरोप है कि शाखा प्रबंधक द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आगामी 10 दिनों तक भी कैश मिलने की कोई संभावना नहीं है। इस स्थिति से आमजन की दैनिक जरूरतें प्रभावित हो रही हैं। शादी-ब्याह, बच्चों की परीक्षा फीस और अन्य जरूरी कार्यों में बाधा आ रही है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की रघुराजगढ़ शाखा की सेवाओं को लेकर असंतोष जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें समय पर नकद राशि नहीं मिल पा रही है और अन्य बैंकिंग सुविधाओं में भी देरी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहकों के अनुसार, बार-बार बैंक जाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिससे दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति से परेशान होकर कुछ लोगों ने अन्य बैंकों में खाता खुलवाने का विकल्प अपनाने की बात कही है। स्थानीय नागरिकों का सुझाव है कि एसबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों में बेहतर सुविधाएँ और समय पर नकद उपलब्धता मिल सकती है, इसलिए लोग वहाँ खाते खोलने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बैंक का खाता बंद करने से पहले ग्राहकों को अपनी शिकायत बैंक प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों तक पहुँचानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। स्थानीय निवासी जगपति सिंह (खुराहा, रघुराजगढ़) ने प्रशासन और बैंक अधिकारियों से इस समस्या पर ध्यान देने और जल्द समाधान करने की मांग की है।

पेंशनधारियों को मार्च माह की जारी की गयी पेंशन

मऊगंज जागरण। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम सें प्रदेश के साथ-साथ मऊगंज जिलें के 60980 पेंशन हितग्राहियों को मार्च माह की पेशन राशि 600 रूपये प्रति व्यक्ति के मान सें कुल 3.66 करोड़ रुपये की राशि खातें मे स्थानान्तरित की गयी है। कार्यक्रम का प्रसारण मऊगंज कलेक्ट्रेट मे एनआईसी के माध्यम सें पेशनधारियों एवं जिले व ब्लाक के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर संजय कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी, अपर कलेक्टर पीके पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद मऊगंज परमानंद तिवारी एवं सामाजिक न्याय विभाग के अजय पटेल उपस्थित रहें।

जिला स्तरीय ज्ञान भारतम पांडुलिपि मिशन समिति गठित

मऊगंज। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा हस्तलिखित विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण व प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से ज्ञान भारतम मिशन की महत्वपूर्ण पहल की गयी है। मऊगंज जिले में कलेक्टर संजय कुमार जैन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ज्ञान भारतम पांडुलिपि मिशन समिति का गठन किया गया है। समिति के समन्वयक एसडीएम मऊगंज व हनुमना तथा सदस्य सचिव डिप्टी कलेक्टर पवन गुरैया बनाये गये हैं जबकि सदस्य के तौर पर सीईओ जिला पंचायत, प्राचार्य शहीद केदारनाथ महाविद्यालय डॉ. सोमदत्त पाण्डेय व इतिहास व पुरातत्व प्रतिनिधि राजयोग शिक्षिका बीके पूर्णिमा को शामिल किया गया है।

गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने सौंपा ज्ञापन

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम गौसेवकों ने तहसीलदार मनगवां को सौंपा ज्ञापन

मनगवां नि.प्र.। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत 27 अप्रैल दिन सोमवार को मनगवां तहसील में गौसेवकों ने गौमाता को राष्ट्रमाता एवं अन्य कई मांगों को लेकर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार मनगवां आंचल अग्रहरि को हिंदू समाज से 1500 लोगों के हस्ताक्षर समर्थन के साथ ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन संवैधानिक रूप से पूरे भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने और उनके संरक्षण-संवर्धन के लिए ठोस कानून बनाने की मांग की। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गौ माता को संवैधानिक रूप से राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना है।

ये हैं मुख्य मांगें : गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। देश में गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाए। केंद्र में एक अलग गौ सेवा मंत्रालय का गठन हो। गौचर भूमि से अवैध कब्जे हटाना और गौशालाओं की स्थिति में सुधार करना इत्यादि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मातृशक्ति रेखा मिश्रा ,गौरक्षा दल के जिला मंत्री रवि यादव, मनीष शुक्ला, प्रभात गुप्ता, शिवम दहिया, सूर्या सोनी, सूरज नामदेव, विक्कू शुक्ला, शशिधर शुक्ला, शिवम पांडे, प्रभात शुक्ला, अनूप पांडे, सौरभ तिवारी, शुभम पटेल, प्रियांशू पाण्डेय, मंटू पाठक इत्यादि गौसेवक कार्यकर्ता सम्मिलित रहे।

डॉ अजय सिंह को विंध्य विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाए जाने हनुमना में खुशी की लहर

हनुमना, नि.प्र.। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अजय सिंह को रीवा जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं कुशल संगठक अजय सिंह को विंध्य विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हनुमना नगर पंचायत ग्रामीण कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न कार्यकर्ताओं ने हर्ष एवं खुशी जाहिर की है जिसमें प्रमुख रूप से नगर परिषद पूर्व उपाध्यक्ष मोहनलाल कचेर, रमाकांत, अमरेंद्र बहादुर सिंह, रितेश केशरी, शनि सब्जी वाले, गुलशन गुप्ता, राम बाबू गुप्ता आदि कई कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहीर की है।

डोडकिया में खेत तालाब योजना की राशि डकार गए सरपंच-सचिव

सचिव के साथ मिलकर सरपंच का पुत्र पंचायत की राशि का लगा रहा पलीता

त्योंथर ब्यूरो। जिले की त्योंथर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत डोडकिया के सरपंच सचिव उपयंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता पवन ओझा पूर्व सैनिक निवासी डोडकिया द्वारा संवाददाता को बताया गया कि सूचना अधिकार के तहत जानकारी हासिल की गयी जिससे उन्हें पता चला कि सरपंच सचिव द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पवन ओझा ने संवाददाता को बताते हुए कहा कि मनरेगा के तहत खेत तालाब योजना एवं वित्त आयोग की परफार्मेंस ग्रान्ट योजना के तहत प्राप्त राशि का व्यापक तौर पर दुरुपयोग किया गया है जो कि सरपंच डोडकिया पढ़ी लिखी महिला नहीं है उनके समस्त कार्य उनके पुत्र अरूण ओझा द्वारा निष्पादित किया जाता रहा है और किया जा रहा है यहां तक कि महिला सरपंच की पदमुद्रा पर भी हस्ताक्षर उनके पुत्र अरूण ओझा द्वारा किया जाता रहा है और किया भी जा रहा हौ मनरेगा योजना के अन्तर्गत निम्न हितग्राहियों के भूमि पर खेत तालाब स्वीकृत किये गये है उनके स्वीकृति लागत और मास्टर रोल भरकर धन को आहरित कर लिया गया, किन्तु धरातल पर कार्य नहीं हुआ है, जिसमें अंजना सिंह स्वीकृति राशि 1.47 लाख आहरित राशि मस्टर रोल 0.87 लाख, 2 दिलीप उपाध्याय स्वीकृति राशि 1.47 लाख मस्टर रोल से आहरित राशि 0.88 लाख, रामलोचन ओझा स्वीकृति राशि 1.47 लाख मस्टर रोल से आहरित राशि 0.23 लाख, - लवकुश ओझा स्वीकृति लागत 1.47 लाख मस्टर रोल से आहरित राशि 0.07 लाख रूपए, हरिश्चंद्र सिह स्वीकृति राशि 1.47 लाख मस्टर रोल से आहरित राशि 0.75 लाख, बालेन्द्र उपाध्याय स्वीकृति राशि 3.85 लाख मस्टर रोल से आहरित राशि 2.21 लाख, रत्नेश सिंह स्वीकृति राशि 3.85 लाख मस्टर रोल से आहरित राशि 1.90 लाख, मानेन्द उपाध्याय स्वीकृति राशि 3.85 लाख मस्टर रोल से आहरित राशि 2.35 लाख, इन्दल प्रसाद शुक्ल स्वीकृति राशि 3.85 लाख मस्टर रोल से आहरित राशि 1.39 लाख, सतीश चन्द्र उपाध्याय स्वीकृति राशि 3.85 लाख मस्टर रोल से आहरित राशि 2.26 लाख, श्रीकांत मिश्र स्वीकृति राशि 3.85 लाख मस्टर रोल से आहरित राशि 1.19 लाख रूपए आदि शामिल है।

मनरेगा योजना की मजदूरी और सामग्री के नाम पर भ्रष्टाचार : मनरेगा योजना अन्तर्गत कई सामुदायिक कार्यों में भी मजदूरी और सामग्री खरीद पर राशि का आहरण किया गया है किन्तु मौके फर कोई काम नहीं कराया गया है, जिसमें नाली निर्माण कार्य प्राथमिक स्कूल से राम लोचन के घर तक स्वीकृति लागत 1304884, लाख मजदूरी पर व्यय 208046 लाख सामग्री पर खर्च 1096838 नाला सफाई एवं गहरी करण रामजस के खेत से राजकुमार के खेत तक स्वीकृति राशि 498761 मजदूरी पर व्यय 328625 रूपए कोई सफाई का कार्य नहीं कराया गया। नाला सफाई एवं गहरी करण राजकुमार के खेत से राजबहोर के खेत तक स्वीकृति राशि 498761 रूपए मजदूरी पर व्यय राशि 433151 रुपये कोई सफाई का कार्य नहीं कराया गया। चितौली नाला धुरिया बाबा से आत्मा प्रसाद ओझा के खेत तक स्वीकृति राशि 388328 लाख रुपए कोई कार्य नहीं कराया गया है जिसकी जांच की मांग श्री ओझा ने की है। उन्होने पंचायत में किए गए निर्माण कार्य की जांच की मांग की है जिससे सरपंच-सचिव डोडकिया द्वारा कराए गए कार्यों में भ्रष्टाचार जनता के सामने आ सके।

बसों में नहीं चस्पा रहती किराया सूची, यात्री लुटने को मजबूर

प्रयागराज यात्रा के नाम पर यात्रियों का शोषण रोकने की मांग

चाकघाट, नि.प्र. । जिला मुख्यालय रीवा से चाकघाट एवं इलाहाबाद के बीच चलने वाली प्राइवेट बसों में यात्रियों से किराये के नाम पर मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। प्राइवेट बस में यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक किराया लिया जाता है। संवाददाता को पीड़ित यात्रियों ने बताया कि रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाले अधिकांश बसों में प्रयागराज का बोर्ड लगा रहता है। यात्रियों से प्रयागराज जाने की बात बाता कर प्रयागराज तक का टिकट बना दिया जाता है। टिकट भी ऐसा होता है जिसमें न तो बस का नंबर होता न लिए गए किराये का उल्लेख। आए दिन रीवा से चलकर प्रयागराज जाने वाली यात्रियों को चाकघाट बाडर में उतार दिया जाता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं बच्चों और परिवार के साथ लोगों को बॉर्डर में आगे की यात्रा हेतु भटकना पड़ता है। बसों में किराया सूची भी नहीं लगाई जाती और मनमाने ढंग से गिराया लिया जाता है। जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से अपेक्षा है कि रीवा से चाकघाट एवं प्रयागराज तक चलने वाली बसों में प्रयागराज का बोर्ड लगाकर यात्रियों को अपने जाल में फंसाने का काम बन्द कराया जाय तथा यात्री किराया सूची प्रदर्शित करवाया जाए, जिससे यात्रियों का शोषण रोका जा सके।

सीतापुर-हनुमना एवं नईगढ़ी माइक्रो परियोजना के संबंध में बैठक का आयोजन आज

मऊगंज जागरण। कलेक्टर संजय कुमार जैन आज 30 अप्रैल को सीतापुर हनुमना उद्वहन सिंचाई परियोजना एवं नईगढ़ी माइक्रो परियोजना की समीक्षा करेंगे। कलेक्टर कार्यालय में यह बैठक दोपहर 12 बजे से आरंभ होगी। अपर कलेक्टर पी.के. पाण्डेय ने संबंधित अधिकारियों को उपस्थिति के निर्देश दिये हैं।

पेयजल के संबंध में बैठक आज

मऊगंज जागरण। कलेक्टर संजय कुमार जैन की अध्यक्षता में आज 30 अप्रैल को जिले में ग्रीष्मकाल में होने वाली पेयजल की समस्या एवं उसके निराकरण के संबंध में बैठक आयोजित की गई है। अपर कलेक्टर पी.के. पाण्डेय ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय में सुबह 11 बजे से आयोजित बैठक में एसडीएम, पीओडब्ल्यू, कार्यपालन यंत्री पीएचई, सीएमओ तथा सीईओ जनपद उपस्थित रहेंगे।

जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की बैठक 8 मई को

मऊगंज जागरण। कलेक्टर संजय कुमार जैन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की बैठक 8 मई को दोपहर एक बजे कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गयी है। बैठक में संबंधित अधिकारियों को उपस्थित के निर्देश दिये गये हैं।

बिना नंबर प्लेट के अवैध खनिज का परिवहन कर रहे ट्रक

जिम्मेदार बने मूक दर्शक

त्योंथर ब्यूरो। रीवा आरटीओ और खनिज विभाग की निष्क्रियता के कारण त्योंथर क्षेत्र में खुलकर अवैध रूप से खनिज संपदाओं का परिवहन हो रहा हैं। चाकघाट क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने बताया कि अवैध खनिज के परिवहन से शासन को राजस्व में भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने संवाददाता को बताया कि सोहागी, चाकघाट, जनेह थाना के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में बिना नंबर प्लेट के हाइवा और ट्रक जो कि गिट्टी, रेत एवं अन्य ओवरलोड खनिज ढोने में लगे हैं। ये वाहन चाकघाट बॉर्डर, जनेह बॉर्डर से उत्तर प्रदेश प्रयागराज में खनिज संपदाओं का सहजता से परिवहन कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि न तो रीवा आरटीओ और न ही खनिज विभाग, न ही क्षेत्रीय पुलिस इस खनिज तस्करी को रोकने को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। बता दें कि संबंधित विभागों की खामोशी के चलते स्थानीय स्तर पर खनन और परिवहन माफिया के हौसले बुलंद हैं। नियम अनुसार बिना दस्तावेज और नंबर प्लेट के चालित खनिज संपदा से लोड वाहन पूरी तरह अवैध हैं। फिर भी ऐसे वाहनों की आवाजाही अधिकारियों की मिलीभगत या उदासीनता को दर्शाती है। आरोप है कि विभागीय चुप्पी से खनन और परिवहन में लगे माफिया बेलगाम हो गए हैं, जिससे सरकारी तंत्र की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

इम्पैक्ट फीचर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भागीरथी प्रयासों से बढ़ रहा हैं मप्र में सिंचाई का रकबा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए निरंतर भागीरथी प्रयास हो रहे है। केन-बेतवा,पार्वती-कालीसिंध- चम्बल अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना और मेगा तापी रिचार्ज परियोजना जैसी तीन बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं ने सिंचाई के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की गति को उन राज्यों से तेज कर दी है,जो लहलहाती फसलों के राज्य के तौर पर जाने जाते रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब 100 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि वाला मध्यप्रदेश किसानों की समृद्धि के उस मुकाम तक पहुंच जाएगा,जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा होगा और ये सपना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अथक प्रयासों से ही संभव हो पा रहा हैं। पिछले दो वर्षों में 7.31 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई क्षमता विकसित की गई है।

चालू परियोजनाओं की प्रगति

जल संसाधन विभाग ने बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति प्रस्तुत की

सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना, उज्जैन
लागत : 614.53 करोड़

कान्ह डायवर्सन क्लोज-डक्ट परियोजना, उज्जैन
लागत : 919.94 करोड़

सिंहस्थ 2028 हेतु घाट निर्माण व अन्य कार्य
लागत : 778.91 करोड़

बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह सभी प्रयास प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का तेज़ी से विस्तार कर कृषि विकास को नई दिशा देने वाले हैं।

दो साल में 7.31 लाख हेक्टेयर बढ़ा सिंचाई क्षेत्र - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में 7.31 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई से जुड़ा है। वर्ष 2026 तक सिंचाई क्षमता में 8.44 लाख हेक्टेयर की और वृद्धि होने जा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश को 100 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र तक पहुँचाना है। सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा अब प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ताकि योजनाओं की गति और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

नदी जोड़ो परियोजनाओं से सिंचाई में बड़ा उछाल

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से पार्वती-कालीसिंध-चम्बल- केन-बेतवा और मेगा तापी अंतर्राज्यीय परियोजनाएँ प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि हैं। इसी तर्ज पर राज्य में नदियों को जोड़ने की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू किए गए हैं।

राज्य में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ये नदी जोड़ो योजनाएँ प्रस्तावित हैं

- कान्ह-गंभीर (उज्जैन)
- कालीसिंध-चंबल (मंदसौर, नीमच, उज्जैन)
- केन-मंदाकिनी (सतना)
- शक्कर-पेंच और दूधी-तामिया (सिवनी, छिंदवाड़ा)
- जामनेर-नेवन और नेवन-बीना (रायसेन)

इन परियोजनाओं से 5.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की नई सुविधा मिलेगी। कुल अनुमानित लागत ?9,870 करोड़ है और 7 जिलों के हजारों किसान सीधे लाभान्वित होंगे।

भोपाल मॉडल से कम लागत में सुरक्षित जलाशय

सीएम डॉ. यादव ने भोपाल की प्राचीन झील तकनीक का अध्ययन कर कम लागत में सुरक्षित जलाशय और बांध विकसित करने के निर्देश दिए। विभाग को इस मॉडल का प्रदर्शन तैयार करने को कहा गया है।

मध्यप्रदेश दो नदी जोड़ो परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाला देश पहला राज्य

देश की प्रमुख नदियों का मायका है मध्यप्रदेशः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत का हृदय मध्यप्रदेश, यहां के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य और अथाह, अविरल जल राशि के लिए समूचे विश्व में जाना जाता है। मध्यप्रदेश में बहने वाली नदियां भारत की सनातन संस्कृति की संवाहक हैं, जिनके किनारे सदियों से हमारी शाश्वत सभ्यता फल फूल रही है। यहाँ की पहचान केवल प्राचीन धरोहरों, मंदिरों, किलों और जनजातीय संस्कृति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की छोटी-बड़ी 750-800 नदियों से भी है।प्रदेश की इस समृद्ध जल राशि के कारण ही मध्यप्रदेश को 'नदियों का मायका' कहा जाता है। मध्यप्रदेश से उद्गमित छोटी-बड़ी नदियाँ, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, माही और महानदी जैसे विशाल नदी प्रवाह तंत्रों में समाहित होकर पूरे भारत की जीवन-रेखा बनाती हैं।

चंबल नदी : महाभारत काल में चंबल नदी का नाम चर्मणवती था। यह भगवान परशुराम के जन्म-स्थल जानापाव से निकली। यह राजस्थान और मध्यप्रदेश की सीमा बनाती है। जानापाव से निकलकर चंबल नदी मध्यप्रदेश-उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित 'पंचनदा' संगम पर यमुना में परिमित जलराशि के साथ समाहित हो जाती है।

मोझदायिनी क्षिप्रा नदी: मोझदायिनी क्षिप्रा नदी के तट पर प्राचीन उज्जयिनी शहर बसा है। ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर और सिंहस्थ कुम्भ समागम का यह तीर्थ क्षेत्र विश्वविख्यात है। क्षिप्रा को भी मालवा की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा नदी इंदौर जिले में उज्जैनी-मुंडला गांव के ककड़ी-बड़ली नामक स्थान से निकल कर लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद चंबल नदी में मिल जाती है।

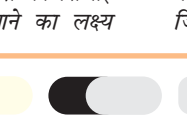

ताप्ती नदी : सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात तक जाती है और लगभग 724 किलोमीटर की दूरी तय कर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। माही नदी की विशेषता है कि यह कर्क रेखा को दो बार पार करती है। माही नदी भी मध्यप्रदेश से गुजरात तक 583 किलोमीटर की यात्रा कर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है।

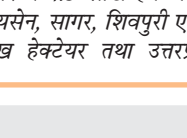

नर्मदा नदी: मध्यप्रदेश की नदियाँ केवल भौतिक जल स्रोत नहीं, बल्कि संस्कृति की वाहक भी हैं। नदियों के किनारे प्राचीन नगरों, धार्मिक स्थलों और व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन प्राचीन समय से ही खगोल विज्ञान और श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है। प्राचीन उज्जयिनी सिंहस्थ 'कुंभ' समागम का तीर्थ क्षेत्र भी है। नर्मदा नदी के तट पर बसे महेश्वर और ओंकारेश्वर शहर शैव परंपरा के प्रमुख तीर्थ-स्थल हैं। ओंकारेश्वर 12 ज्योर्तिलिंगों में एक है। बेतवा नदी के तट और प्रवाह क्षेत्र के ओरछा, सांची और विदिशा मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक यशोगाथा के प्रतीक होने के साथ ही बौद्ध संस्कृति के उदयावसान के साक्षी भी रहे हैं। मध्यप्रदेश का अधिकांश भूभाग विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों से आच्छादित है। यही कारण है कि यह अनेक महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, जबकि सोन, क्षिप्रा, चंबल, बेतवा उत्तर और पूर्व की ओर बहकर अपनी अथाह जलराशि के साथ गंगा-यमुना में समाहित हो जाती हैं।

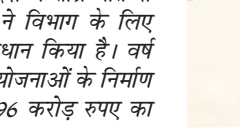

पुण्य सलिला मां नर्मदा : पुण्य सलिला मां नर्मदा का दूसरा नाम रेवा भी है।भगवान शिव की पुत्री मानी जाने वाली रेवा मध्यप्रदेश और गुजरात दोनों की जीवन रेखा है। मान्यता है कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से 'गंगा स्नान' का पुण्य मिलता है। श्रद्धालुओं के लिए 3000 किमी से अधिक लंबी नर्मदा परिक्रमा जीवन का सबसे बड़ा तप माना जाता है। मां नर्मदा अमरकंटक से जन्म लेकर लेकर जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती हुई गुजरात को अभिसिंचित कर लगभग 1312 किलोमीटर की यात्रा तय कर अरब सागर की खंभात की खाड़ी में विराम पाती हैं।

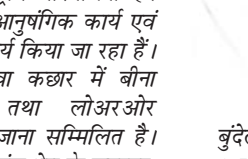

पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो अभियान से संपूर्ण पश्चिमी मप्र होगा लाभान्वितः डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मंगलवार का दिन मध्यप्रदेश और राजस्थान के लिए ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पार्वती, चंबल और कालीसिंध नदी जोड़ो अभियान के लिए त्रि-पक्षीय अनुबंध होने वाला है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश और राजस्थान को 72 हजार करोड़ रुपये की अद्भुत परियोजना की बड़ी सौगात दी जाएगी। इससे मध्यप्रदेश के 13 जिलों में न केवल पीने के पानी की बल्कि सभी प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था भी होगी। जल, भगवान की देन है लेकिन जल का सद्पयोग सरकार के माध्यम से समाज के हित में होता है। गत 20 वर्ष से किसी न किसी कारण से राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच होने वाला समझौता टला। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में यह बदलाव का दौर है। इस परियोजना से श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर सहित आगर, इंदौर, धार, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर इत्यादि संपूर्ण पश्चिमी मध्यप्रदेश में पीने के पानी और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा राजस्थान के ग्राम दादिया (जयपुर) में पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना के कार्यक्रम केलिये रवाना होने के पहले जारी अपने संदेश में यह बात कही।

40 लाख आबादी को सिंचाई जल के साथ पेयजल भी होगा उपलब्ध

इस परियोजना से प्रदेश के 3217 ग्रामों को लाभ मिलेगा। मालवा और चंबल क्षेत्र में 6 लाख 13 हजार 520 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त लगभग 60 वर्ष पुरानी चंबल दाईं मुख्य नहर एवं वितरण-तंत्र प्रणाली के आधुनिकीकरण कार्य से भिंड, मुरैना एवं श्योपुर जिले में कृषकों की मांग अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाएगा। पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 72 हजार करोड़ है, जिसमें मध्यप्रदेश 35 हजार करोड़ और राजस्थान 37 हजार करोड़ रूपये व्यय करेगा। केन्द्र की इस योजना में कुल लागत का 90 प्रतिशत केन्द्रांश और 10 प्रतिशत राज्यांश रहेगा। परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 1908.83 घन मीटर होगी। साथ ही 172 मिलियन घन मीटर जल, पेयजल और उद्योगों के लिये आरक्षित रहेगा। परियोजना अंतर्गत 21 बांध/बैराज निर्मित किये जाएंगे।

सिंचाई रकबा बढ़ाने के प्रमुख कदम और परियोजनाएं

नदी जोड़ो परियोजनाएं

सरकार पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना और केन-बेतवा लिंक परियोजना पर तेजी से काम कर रही है, जिससे राज्य के 10-15 जिलों में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। सूक्ष्म सिंचाई पानी की बचत और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, 133 से अधिक बड़ी और मध्यम सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ निर्माणाधीन हैं।

नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी

सागर, विदिशा, छतरपुर और दमोह जिलों में नई परियोजनाएं (जैसे हनोता मध्यम सिंचाई परियोजना) शुरू की गई हैं।

जल गंगा संवर्धन अभियान

वर्षा जल संचयन के लिए अमृत सरोवर विकसित करना और खेत तालाबों का निर्माण करना, ताकि भूजल स्तर में सुधार हो।

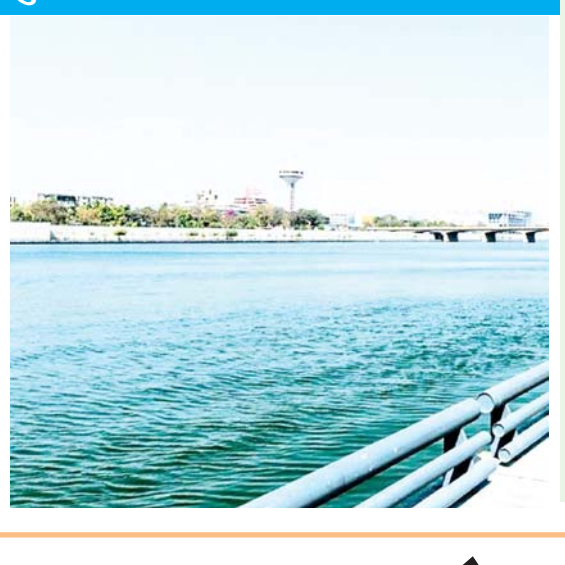

किसानों के लिए विशेष राहत

ब्याज की माफी : 35 लाख से अधिक किसानों के बकाया सिंचाई कर पर पेनल्टी और ब्याज की माफी की गई है, बशर्ते मूलधन 31 मार्च 2026 तक जमा किया जाए।

सोलर पंप योजना : किसानों को बिजली के बिल से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई एवं सोलर पम्प योजना को प्राथमिकता दी जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य कृषक कल्याण वर्ष 2026 तक किसानों की आय दोगुनी करना और हर खेत तक पानी पहुँचाना है।

मध्यप्रदेश में निरंतर बढ़ रहा है सिंचाई का रकबा : डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है, जो सबसे ज्यादा फिक्र अपने अन्नदाता की करती है। सरकार निरंतर हर खेत तक पानी पहुंचाने के कार्य कर रही है। जल संसाधन विभाग की विभिन्न वृहद, मध्यम एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से मध्यप्रदेश में निरंतर सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाने से अब किसान 2 फसलों के स्थान पर 3 फसल लेने लगे है। इससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और किसान समृद्ध भी हो रहे है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 में जहां प्रदेश का सिंचाई रकबा लगभग 3 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़कर लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश की निर्मित और निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं से प्रदेश में वर्ष 2025-26 तक सिंचाई का रकबा लगभग 65 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है। सरकार ने वर्ष 2028-29 तक प्रदेश की सिंचाई क्षमता 1 करोड़ हैक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए प्रदेश में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार ने विभाग के लिए बजट में भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है। वर्ष 2024-25 के बजट में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं में केन-बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है। इसमें केन नदी पर दौधन बांध, आनुषंगिक कार्य एवं लिंक नहर का निर्माण संबंधित कार्य किया जा रहा हैं। इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा कछार में बीना काम्पलेक्स, कोटा बैराज तथा लोअरओर परियोजनाओं का निर्माण किया जाना सम्मिलित है। परियोजना से मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं दमोह जिलों में माइक्रो इरिगेशन से केन कछार में 4.5 लाख हेक्टेयर, बेतवा कछार के विदिशा, रायसेन, सागर, शिवपुरी एवं दतिया जिलों में 2.06 लाख हेक्टेयर तथा उत्तरप्रदेश के

बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा, महोबा और झांसी जिलों में 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना से उत्पन्न होने वाली 103 मेगावाट जल विद्युत तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पर पूरा अधिकार मध्यप्रदेश का होगा। परियोजना के द्वितीय चरण की डीपीआर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 2014 में तैयार की गई। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश द्वारा बेतवा कछार में अंतिम रूप से प्रस्तावित 3 परियोजनाएं: बीना परिसर से 96 हजार हेक्टेयर, कोटा बैराज से 20 हजार हेक्टेयर तथा लोअर ओर परियोजना से 90 हजार हैक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित है। साथ ही परियोजनाओं से 66.7 मिलियन घन मीटर पेयजल एवं मांग आधार पर उद्योगों हेतु जल का प्रावधान रखा गया है। परियोजना की सभी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। मध्यप्रदेश में द्वितीय चरण की परियोजना का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच एक त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रि-परिषद द्वारा 44 करोड़ 605 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना को 8 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके लिए मध्यप्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों को लाभ मिलेगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती-कालीसिंध परियोजना और नर्मदा घाटी की अन्य प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं से प्रदेश में 19 लाख 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। प्रदेश में 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 वृहद् एवं मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजना निर्माणाधीन है। प्रदेश में 1320 करोड़ रुपए की लागत वाली चितरंगी दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई है। इस परियोजना से सिंगरौली जिले में 32 हजार 125 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा। इसी प्रकार 4197 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृत किया गया है। नीमच जिले में इस परियोजना से 18 हजार 600 हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा।

D-19022/26

प्रभारी प्राचार्य हाई स्कूल बांस का वेतन काटा गया

रीवा। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शासकीय हाई स्कूल बांस के प्राचार्य शिवबहादुर सिंह का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि गत जनसुनवाई के दौरान प्राचार्य अपने स्वयं एवं अन्य की जनगणना कार्य हेतु प्रगणक की ड्यूटी निरस्त कराने उपस्थित हुए थे।

स्वगणना कार्य शत-प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें: कलेक्टर

रीवा। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने आयुक्त नगर निगम, नगर पालिका के सीएमओ तथा तहसीलदारों को निर्देश दिये हैं कि अपने चार्ज स्तर पर 30 अप्रैल तक सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का स्वगणना शत प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें। एक मई से 30 मई तक होने वाली जनगणना कार्य को संपन्न करायें।

आपत्तिजनक वीडियो मामले में दो आरोपी उड़ीसा से गिरफ्तार

जागरण, रीवा। मऊगंज जिले में पूर्व जनपद अध्यक्ष से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो वायरल मामले में पुलिस ने महिला सहित दो आरोपियों को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गुरुवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी। जानकारी के अनुसार पूर्व जनपद अध्यक्ष की शिकायत पर मऊगंज थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्हें नशीली चाय पिलाकर सुनियोजित तरीके से आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया और बाद में ब्लैकमेल किया गया। इस मामले में पुलिस ने रुचि सिंह और रविशंकर तिवारी निवासी पन्नी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। फरार चल रहे दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने उन्हें उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी रुचि सिंह का वास्तविक नाम टिंकी गाडिया है, जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ की रहने वाली है। वहीं आरोपी रविशंकर के खिलाफ सुंदरगढ़ में मारपीट का मामला भी दर्ज बताया जा रहा है। उड़ीसा पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद मऊगंज पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर रवाना हो गई है।

REWA INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
Affiliated to CBSE New Delhi | Affiliation No.- 1031367
Where Every Student is Valued .... Science, Art, Commerce
ADMISSION OPEN 2026-27 Nursery to 12th
Call: 9806154224, 8120154224
Add.: Ward 15, Gadariya, Ratahara, Rewa (M.P.)
Email: ripsrewaschool@gmail.com

चर्म, सौन्दर्य, एलर्जी एवं स्कीन केयर
डॉ. सिद्धार्थ तिवारी
MBBS, MD (Dermatology & STD)
परामर्श शुल्क मात्र 300/-
मिलने का समय प्रतिदिन सुबह 10 से 2 बजे साय 4 से 7 बजे (रविवार अवकाश)
चर्म, सौन्दर्य, नाखून, बाल, कुष्ठ, गुप्त (यौन) एवं एलर्जी रोग विशेषज्ञ
परामर्श- दाद, खाज, खुजली, मुंहासे, मस्से, अपरस, सोरायसिस, सफेद दाग, एक्जिमा, गंजापन, त्वचा की एलर्जी, नाखुनों का खराब होना, चेहरे पे दाग धब्बे, झाइयाँ, (Glow & Fairness), सेहुंआ, फोड़े, फुन्सी, गुप्त एवं यौन समस्या आदि।
कामता मेडिकल
ए-ब्लॉक समदड़िया, न्यू बस स्टैन्ड रीवा (म.प्र.)
9399312433 9981287311

ड्राइवर की आवश्यकता है
एक पद कार ड्राइवर की आवश्यकता है, जिसे स्कार्पियों कार चलाने का अनुभव हो
वेतन योग्यतानुसार, रहना + खाना फ्री
शीघ्र संपर्क करें
बालेन्द्र शुक्ला पहड़िया, जिला रीवा (म.प्र.)
9039489049, 8349009802

मेट्रो हॉस्पिटल, रीवा
आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध है
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM-JAY
24/7 इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है
अपॉइंटमेन्ट के लिए सम्पर्क करें:
07662-314775, 7771000668, 777100669
न्यू बस स्टैंड के पास, शारदा पुरम रोड, रीवा

वैवाहिकी
म.प्र. निवासी सरयूपारी ब्राह्मण 'गर्ग गोत्र' शिक्षा- बी.ई., रंग गोरा, उम्र 33 वर्ष, कद 5'8" के विवाह हेतु समकक्ष या तलाक सुदा ब्राह्मण 'कन्या' की आवश्यकता है, विवाह हेतु अतिशीघ्र संपर्क करें।
संपर्क नं. 9826308896

BBS MEMORIAL HR. SEC. SCHOOL AZAD NAGAR, REWA (M.P.)
BBS KIDS ZONE 9424777617
More than 50 student Scored 90% in Board Examination
9th Vishesh Rank in State Merit 12th Math Group 2025-26
3rd Priyanshi Rank in State Merit 12th Bio Group 2025-26
9th Harshita Rank in State Merit 12th Bio Group 2025-26
मध्यप्रदेश टॉप 10 में निरंतर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
NEET selected: Astha, Anshika, Pranjul, Rahul
IIT selected: Krishna, Divy, Swastik, Akshat
ADMISSION OPEN For Nursery to 12th
NO ADMISSION FEE

डॉ. बीरभान सिंह
एम.डी. (मेडिसिन)
DrNB (न्यूरोलॉजी) पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक
कंसल्टेन्ट न्यूरोलॉजिस्ट
उपलब्ध सुविधाएं
• कमर दर्द (साइटिका • मिर्गी (फिट), बुखारी मिर्गी, बच्चों की मिर्गी • सिर दर्द माइग्रेन/अर्ध कपारी
• मूवमेंट डिसार्डर्स (ऑखें एवं चेहरे का फड़कना, गर्दन टेढ़ी होना) • बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाना
• पार्किंसंस (हाथ पैर में कपन होना), अनिद्रा, नीद में बडबडाना या चौक जाना। • चक्कर आना (वर्टाइगो)
• यादाश्त में कमी, पेशाब का पता न चलना व कपड़ों में पेशाब निकल जाना, भूलने की बीमारी।
• आँखों में दर्द के साथ-साथ धुंधला दिखना और दो-दो दिखाई देना, रंग साफ न दिखना आचानक से आँखो की रोशनी कम होना • हाथ पैर में झनझनाहट या सुन्नपन, झुनझुनी (न्यूरोपैथी)
• अनिद्रा (स्लीप डिसाआर्डर) • मस्तिष्क एवं रीढ़ के इन्फेक्शन • चलने में परेशानी, लड़खड़ा के चलना, धीरे-धीरे चलना, चलते समय गिर जाना व गिरने का भय। • दिमागी बुखार • मांसपेशियों में कमजोरी, फड़कना या हाथ पैर का पतला होना • गर्दन दर्द (सर्वाइकल स्प,एडलाइटिस) • चेहरा का तिरछापन (बेल्स पालसी)
पताः श्रवण कुमारी स्कूल के पास, गुड़ रोड चिरहुला, रीवा (म.प्र.) मो. 7869516171

Minerva The Medicity A MULTI SUPERSPECIALITY HOSPITAL
मिनर्वा द मेडिसिटी
मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रीवा
जन्मजात बाल्य हृदय रोग एवं बाईपास सर्जरी
आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज
फोर्टिस हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा
विशेष सूचना
कार्डियक सर्जरी पुनः निःशुल्क उपलब्ध
असुविधा से बचने के लिए पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन करवाएं
खन्ना टॉवर, पुराना बस स्टैंड, रीवा (म.प्र.)
9893516364, 8770288324 | टोल-फ्री नंबर:- 18008892250

मिनर्वा आई.व्ही.एफ. (टेस्ट ट्यूब बेबी सेन्टर)
(निः संतान दंपत्तियों के लिए)
कम खर्च बेहतर इलाज
सर्वश्रेष्ठ टेस्ट ट्यूब बेबी सुविधा
उपलब्ध सुविधाएँ
* IUI, IVF, ICSI
* फ्रोजन एंब्रिया ट्रांसफर साइकिल (FET)
* एग फ्रीजिंग
* एंब्रियो फ्रीजिंग
* स्पर्म फ्रीजिंग
डॉ. ज्योति ओझा मिश्रा
स्त्री एवं प्रसूति रोग
निःसंतानता रोग एवं टेस्टट्यूब बेबी विशेषज्ञ
MBBS, MD (ऑब्स & गायनी)
फैलोशिप इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एण्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी
मध्यप्रदेश की प्रथम एवं अत्याधुनिक ICSI मशीन द्वारा इलाज उपलब्ध
टोल फ्री : 18008892250, मो.: 8878819362, 9303733830
खन्ना टॉवर, पुराना बस स्टैण्ड, रीवा

डॉ. अनुशा पाण्डेय
एम.बी.बी.एस., एम.एस. (ऑब्स एण्ड गायनी)
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन
संबंधित समस्याएँ
● सफेद पानी जाना, मासिक में अनियमितता
● मासिक के समय दर्द एवं अधिक रक्त स्त्राव
● पेशाब का लीक होना, बदबू आना, जलन होना एवं पेशाब सम्बन्धी समस्या
● बच्चा रोक थाम का उपाय
● बाँझपन का इलाज
● अंडाशय की गांठ के ऑपरेशन
● बच्चेदानी के ऑपरेशन
● बच्चेदानी के रसौनी का इलाज
● पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज का इलाज
● रजोनिवृति (Menopause) की समस्याएँ
● नॉर्मल डिलिवरी एवं सिजेरियन डिलिवरी
परामर्श समयः सुबह 11:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक प्रतिदिन
निःशुल्क परीक्षण कैम्प
हर महीने की 15 तारीख को
समयः सुबह 11 से दोपहर 02 बजे तक
एच.बी. और सुगर जांच फ्री
सोनोग्राफी में 20% की छूट
मिलने का पता
श्री समाधान सोनोग्राफी सेंटर
कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने शॉप नं.-39, 39A समदड़िया मेडिकल मॉल-रीवा
8085813545

विंध्य के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ
डॉ. पी. सी. द्विवेदी
एम.एस. (नेत्र)
सेवानिवृत्त एवं पूर्व विभागाध्यक्ष
का नया पता
समयः सुबह 10 बजे से 2 बजे तक
जूनियर MIG-3 हेडगेवार नगर
कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने, रीवा
आस्था मेडिकल स्टोर, ढेकहा तिराहा, रीवा
समयः शाम 5 बजे से 7 बजे तक
8966825155, 7225925922, 9179687302

10 YEAR WARRANTY | BAJAJ SECURE • AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE | 72198 21111 | BAJAJ AUTO CREDIT | SHRIRAM Finance | IDFC FIRST Bank | L&T Finance | TATA CAPITAL Two Wheeler Loans

*नियम और शर्तें लागू. ऑफ़र 31 मई 2026 तक मान्य है. फ़ायनान्स उपलब्ध है फ़ायनान्सर के अपने स्व-निर्णय पर. पल्सर N160 USD सिंगल सीट वैरिएंट पर दिए गए ई-कॉम ऑफ़र्स, संबंधित ई-कॉम पार्टनर की शर्तों के अधीन हैं. ई-कॉम ऑफ़र्स हर पार्टनर के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं. स्टंट्स, एक्सपर्ट्स द्वारा प्रोफ़ेशनल सुपरविज़न के तहत, आम जनता या आम रास्तों से हट कर नियंत्रित और बंद सीमित वातावरण में किए गए हैं. कृपया इन स्टंट्स की नक़ल करने का प्रयास न करें और हर समय ट्रैफ़िक तथा सुरक्षा नियमों का पालन करें.

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Balaghat: SAI BAJAJ 9425822517 • **Chatarpur:** TIKARIYA BAJAJ 7470901984• **Satna:** FOUZDAR BAJAJ 8109073002, 9399480294, 9425173001, AA Autorider: 9098500556 9098500557 **Rewa** UPPAL BAJAJ 07662-408300, 9301991092, 9424822015 • **Seoni** FRONTIER A S BAJAJ 9302893612• **Sidhi JL Motors 9303942425 6269279293• Shahdol:** JAYSHREE BAJAJ 7879858023 • **Singroli: Waidhan** JAISWAL BAJAJ 7354131415 • **Tikamgarh:** TIKARIYA BAJAJ **7999169461.**

जागरण पब्लिकेशन प्रा. लिमि. के लिए मुद्रक/प्रकाशक मदन मोहन गुप्ता द्वारा दैनिक जागरण प्रेस गांधी नगर उर्रहट रीवा (म.प्र.)से मुद्रित एवं प्रकाशित। सम्पादकः **मदन मोहन गुप्ता।** आर.एन.आई. नं- 1505/57, डाक पंजीयन क्र.- रीवा संभाग 04 /म.प्र. संस्थापक **स्व. गुरुदेव गुप्त**
कार्यालयः- मोबाइल नं रीवा- 9098357869, 9425018958 **सतना** - 9993315949 **सीधी**-7089620900 **सिंगरौली**-9424652999 E-mail: rewajagrannew2015@gmail.com